आज का विचार
जमाने से शिकायत न करो, बल्कि खुद को बदलो क्योंकि पांव को गंदगी से बचाने का तरीका जूता पहनना है न कि कालीन बिछाना।

दैनिक सिटी दर्पण

आईना सच का

5

सिटी दर्पण-राष्ट्रीय दैनिक हिंदी समाचार पत्र की अधिकारिक वेबसाइट पर जाने के लिए स्कैन करें।

चंडीगढ़ । शुक्रवार, 27 जून, 2025 वर्ष 23, अंक 157, मूल्य: 3 रुपए, पृष्ठ 8 RNI Regn No.: CHAHIN/2003/09265 Established 2003 www.citydarpan.com

छोटी मछलियों के बाद अब नशे के कारोबार में शामिल जरनैलों की बारी: भगवंत मान

मुख्यमंत्री बोले- मजीठिया के खिलाफ कार्रवाई ने नशे से संबंधित राजनीतिक दलों के गंदे गठजोड़ को उजागर किया

संवाददाता
चंडीगढ़

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने आज कहा कि छोटे नशा तस्करों के खिलाफ कार्रवाई के बाद अब इस कारोबार में शामिल बड़े तस्करों की बारी है और उन्हें इस कारोबार में अपनी संलिप्तता के परिणाम भुगतने होंगे। अपने आधिकारिक आवास पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने नशे और इस काले कारोबार में शामिल या संरक्षण देने वाले प्रभावशाली व्यक्तियों के प्रति अपनी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति को दोहराया। उन्होंने कहा कि छोटे तस्कर केवल डिस्ट्रीब्यूटर की तरह काम करते हैं, जबकि पूरा नेटवर्क चलाने वाले बड़े तस्कर लंबे समय से जवाबदेही से बचते रहे हैं। अब इन बड़े तस्करों की बारी है। भगवंत सिंह मान ने दृढ़ता से कहा, इस धंधे में शामिल कोई भी व्यक्ति, चाहे वह कितना भी प्रभावशाली क्यों न हो, उसे बख्शा नहीं जाएगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने पहले ही छोटे-छोटे इलाकों में काम करने वाले तस्करों को जेलों में डाल दिया है। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी ने इस घिनौने कारोबार में शामिल सभी तस्करों को जेल में डालने की गारंटी दी थी। अब यह वादा पूरा हो रहा है। उन्होंने आगे कहा कि मौजूदा कार्रवाई ने नशे के काले धंधे की कमर तोड़ दी है। भगवंत सिंह मान ने खुलासा किया कि गिरफ्तार किए गए सभी व्यक्तियों के खिलाफ पर्याप्त सबूत इकट्ठा किए गए हैं, जिनमें हवाला कारोबार का रिकॉर्ड शामिल है, और यह इन कारोबारियों के ताबूत में आखिरी कील है। उन्होंने वादा किया कि यह नजीर बनने वाली कार्रवाई दूसरों को भी इस धंधे में आने से रोकेगी। उन्होंने सभी दोषियों को न्याय के दायरे में लाने की सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया।

> **राजनीतिक बदले की कोई बात नहीं, क्योंकि नशा तस्करों के खिलाफ पर्याप्त सबूत मौजूद हैं**

मुख्यमंत्री ने राज्य में चल रहे ह्ययुद्ध नशे के विरुद्धह्न की सफलता के बारे में बताया और कहा कि कई तस्कर पंजाब छोड़कर भाग गए हैं। उन्होंने कहा कि यह अभियान अब व्यापक जन समर्थन के साथ जन आंदोलन बन गया है। मुख्यमंत्री ने नशे की बुराई के खिलाफ प्रस्ताव पारित करने के लिए गांवों की पंचायतों की सराहना करते हुए इसे पंजाब में नशे के खतरे को खत्म करने के लिए रचनात्मक कदम बताया। अकाली नेता बिक्रम सिंह मजीठिया की गिरफ्तारी पर टिप्पणी करते हुए भगवंत सिंह मान ने कहा कि विभिन्न पार्टियों के नेताओं द्वारा मजीठिया के पक्ष में बयान देने से नशा तस्करों को संरक्षण देने वाला राजनीतिक गठजोड़ उजागर हुआ है।

मुख्यमंत्री ने बताया कि मजीठिया के घर से 29 मोबाइल फोन, आठ लैपटॉप और अन्य महत्वपूर्ण सबूत बरामद हुए हैं। उन्होंने कहा कि इस गिरफ्तारी ने नशे के मुद्दे पर पारंपरिक राजनीतिक दलों के गंदे गठजोड़ का पदार्फाश किया है। भगवंत सिंह मान ने कहा कि इनकी गतिविधियों ने पंजाब को तबाह कर दिया है। उन्होंने चेतावनी दी कि इस कारोबार में शामिल अन्य महत्वपूर्ण राजनीतिक हस्तियों को भी जल्द गिरफ्तार किया जाएगा और उनकी संपत्तियां जब्त की जाएंगी या ढहाई जाएंगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि नशे के कारोबार में आए पैसे की पूरी श्रृंखला से संबंधित हर कड़ी की गहन जांच होगी। जिन्होंने इस काले कारोबार से बड़ी-बड़ी संपत्तियां बनाई हैं, उन्हें जवाबदेह बनाया जाएगा। राजनीतिक बदले के आरोपों को खारिज करते हुए भगवंत सिंह मान ने कहा कि हर कार्रवाई कानून के मुताबिक की गई है।

मुख्यमंत्री ने सवाल किया कि जब पंजाब के लोगों ने विपक्ष को पूरी तरह नकार दिया है, तो यह राजनीतिक बदला कैसे हो सकता है? उन्होंने कहा कि विपक्ष अपने बचाव के लिए इस मुद्दे का राजनीतिकरण करने की कोशिश कर रहा है। भगवंत सिंह मान ने कहा कि ऐसी सभी कोशिशें बेकार जाएंगी क्योंकि राज्य के लोग इन नेताओं के दागी चरित्र से अच्छी तरह वाकिफ हैं।

प्रदेश सरकार 7500 पदों पर नौकरी के लिए जल्द जारी करेगी परिणाम : नायब सिंह सैनी

कहा- विभिन्न विभागों में ग्रुप-सी के पदों के लिए विज्ञापन निकालकर मांगेगी आवेदन

संवाददाता
चंडीगढ़/लाडवा

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि जल्द ही प्रदेश सरकार 7500 पदों पर युवाओं को नौकरी देने जा रही है। इन पदों की परीक्षा व अन्य सभी प्रकार की प्रक्रियाओं को पूरा कर लिया गया है अब जल्द ही परिणाम घोषित किया जाएगा। साथ ही प्रदेशभर के सभी विभागों में खाली पदों का ब्योरा इक्क्ठा किया गया है और ग्रुप-सी के पदों के लिए सीईटी का आवेदन लिए जा चुके हैं। जल्द ही परीक्षा भी आयोजित करवाई जाएगी और विभिन्न विभागों में खाली पदों के विज्ञापन जारी किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि सरकार ने अपने संकल्प पत्र में 50 हजार युवाओं को नौकरी देने का वायदा किया है। जिसको गंभीरता से लेकर हुए इन पदों पर नौकरी देने की योजना भी बनाई जा चुकी है।

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बुधवार सायं गांव बन पौधा रोपण कर पर्यावरण को बचाने का संदेश भी दिया। भाजपा मीडिया प्रभारी व कार्यक्रम संयोजक विजय कौशिक ने पुष्प गुच्छ देकर मुख्यमंत्री नायब सैनी जी का स्वागत किया। मण्डल अध्यक्ष शिव गुप्ता ने सरोपा भेंट कर मुख्यमंत्री जी का स्वागत किया। शक्ति केंद्र प्रमुख जितेंद्र काका ने भी पुष्प गुच्छ देकर मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त किया। साथ ही ब्राह्मण समाज ने परशुराम जी की प्रतिमा भेंट स्वागत किया। सुरेन्द्र शर्मा ने बन गांव में मुख्यमंत्री नायब सैनी जी के पहुँचने पर पगड़ी पहनाकर पुरे गांव की ओर से स्वागत व आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री ने गांव वालों का गांव से प्रचंड जीत के लिए धन्यवाद व्यक्त किया और कहा की बन गांव से मेरा पारिवारिक रिस्ता है मैं यहाँ अपने परिवार के बीच आया हूँ। मेरे परिवार का कोई भी व्यक्ति कभी भी मेरे पास पास आ सकता है 24 घंटे मेरे घर के दरवाजे आपके लिए खुल्ले हैं।

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि चुनाव के समय कांग्रेस के लोगों ने कोर्ट में जाकर 26,000 पदों के परिणाम पर रोक लगवा दी थी। तब हमने संकल्प लिया था कि सरकार बनते ही शपथ लेने से पहले युवाओं को उनके नौकरियों का परिणाम घोषित कर ज्वाइन करवाया जाएगा और सरकार ने ऐसा ही किया है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने प्रदेश में युवाओं को बिना खर्ची बिना पर्ची के मेरिट के आधार पर सरकारी नौकरी दी है और आगे भी इसी नीति से युवाओं को नौकरी दी जाती रहेगी।

इस मौके पर मुख्यमंत्री कार्यालय के प्रभारी कैलाश सैनी, उपायुक्त नेहा सिंह, पुलिस अधीक्षक नीतीश अग्रवाल, मुख्यमंत्री के मीडिया कोऑर्डिनेटर तुषार सैनी, भाजपा जिला अध्यक्ष तिजेंदर सिंह गोल्डी, चेयरमैन धर्मवीर मिजापुर, दीप सैनी, मंडल अध्यक्ष शिव गुप्ता, सुरेन्द्र शर्मा, जितेंद्र काका, डॉ सिंदर, पोला, गुरमेज कश्यप, राजेश पाल, जय सिंह, धर्मेंद्र शर्मा, कृष्ण, राहुल शर्मा, पार्थ, विजय कौशिक सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे।

मंत्रिमंडल के फैसले

- एसीबी का नाम बदलकर राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, हरियाणा करने को दी मंजूरी
- हरियाणा सेवा का अधिकार नियम, 2014 के नियम 9 में संशोधन को मंजूरी दी
- ग्रुप सी और डी कर्मचारियों को मिलेगा प्रतिपूरक अवकाश
- कर्मचारी भत्ता नियमों में संशोधन को दी मंजूरी
- सेवानिवृत्ति के 15 वर्ष बाद समर्पित पेंशन को बहाल करने को मंजूरी दी
- हरियाणा मंत्रीमंडल ने गुरुद्वारा चुनाव नियमों में संशोधन को दी मंजूरी

-संबंधित पेज 3 पर

राजनाथ ने एससीओ देशों के सामने पाक के आतंकवाद को बेनकाब किया

सीमा पार के आतंकवाद केंद्र अब सुरक्षित नहीं हम उन्हें निशाना बनाने में संकोच नहीं करेंगे

एजेंसी (हि.स.)
नई दिल्ली

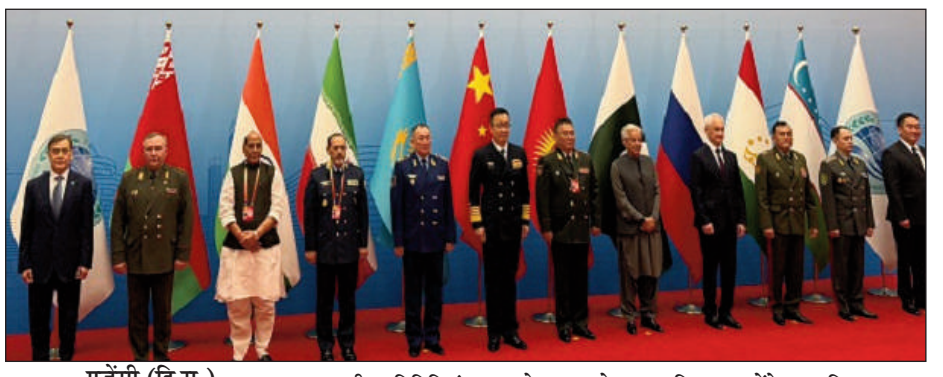

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीन के किंगदाओ में शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) के रक्षा मंत्रियों की बैठक में आतंकवाद के विरुद्ध एकजुट होने का आान किया है। उन्होंने एससीओ देशों के सामने पहलगाम आतंकी हमले और उसके जवाब में शुरू किये गए ऑपरेशन 'सिंदूर' की जानकारी देकर पाकिस्तान के आतंकवाद को बेनकाब किया। उन्होंने भारत की नीति स्पष्ट करते हुए कहा कि क्षेत्र के सामने सबसे बड़ी चुनौतियां शांति, सुरक्षा और विश्वास की कमी से संबंधित हैं तथा बढ़ती कट्टरता, उग्रवाद और आतंकवाद इन समस्याओं का मूल कारण हैं। चीन की मेजबानी में इस बार एससीओ के रक्षा मंत्रियों की बैठक किंगदाओ में हो रही है। उच्चस्तरीय भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करने के लिए राजनाथ सिंह गए हैं। सदस्य देशों के रक्षा मंत्रियों, एससीओ महासचिव, एससीओ के क्षेत्रीय आतंकवाद निरोधक ढांचे (आरएटीएस) के निदेशक और अन्य प्रतिष्ठित प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि कुछ देश सीमा पार आतंकवाद को अपनी नीति के रूप में इस्तेमाल करके आतंकवादियों को पनाह देते हैं। ऐसे दोहरे मानदंडों के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए और एससीओ को ऐसे देशों की आलोचना करने में संकोच नहीं करना चाहिए।

रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत ने जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए जघन्य आतंकी हमले के जवाब में आतंकवाद से बचाव और सीमा पार से होने वाले हमलों को रोकने के अपने अधिकार का इस्तेमाल करते हुए ऑपरेशन 'सिंदूर' शुरू किया। उन्होंने कहा कि पहलगाम आतंकी हमले के दौरान पीड़ितों को उनकी धार्मिक पहचान के आधार पर गोली मार दी गई थी। संयुक्त राष्ट्र से घोषित आतंकी समूह लश्कर-ए-तैयबा (एलईटी) से जुड़े ह्यद रेजिस्टेंस फ्रंटह्न ने हमले की जिम्मेदारी ली थी। उन्होंने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ खुद का बचाव करना हमारा अधिकार है। हमने दिखाया है कि आतंकवाद के केंद्र अब सुरक्षित नहीं हैं और हम उन्हें निशाना बनाने में संकोच नहीं करेंगे। राजनाथ ने आतंकवाद के हर कृत्य को आपराधिक और अनुचित करार दिया। उन्होंने कहा कि एससीओ सदस्यों को इस बुराई की स्पष्ट रूप से निंदा करनी चाहिए। उन्होंने आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों से लड़ने की भारत की प्रतिबद्धता जताई।

मोदी से मिले रोहन जेटली, पिता की स्मृतियों को किया साझा

एजेंसी (हि.स.)
नई दिल्ली

वरिष्ठ भाजपा नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री स्व. अरुण जेटली के पुत्र रोहन जेटली ने आज अपने परिवार सहित प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से भेंट की। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने स्व. अरुण जेटली के योगदान को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके सिद्धांतों एवं मूल्यों को याद किया।

प्रधानमंत्री कार्यालय में हुई इस आत्मीय भेंट के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने आपातकाल के दौर और उसमें अरुण जेटली की भूमिका को याद करते हुए कहा कि वह आज भी जेटली जी के विचारों और मूल्यों से प्रेरणा लेते हैं।

भेंट के बाद रोहन जेटली ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर अपनी भावना साझा करते हुए लिखा, आज परिवार सहित माननीय प्रधानमंत्री से भेंट कर अत्यंत गौरव और सम्मान की अनुभूति हुई। उनकी आत्मीयता, सौम्यता और गहराई ने हम सभी को घर जैसा महसूस कराया। आपातकाल के दिनों की स्मृतियां, पिता जी की भूमिका, कई विचारों का आदान-प्रदान और कुछ हल्की-फुल्की बातें भी हुईं, जिनका विशेष आनंद हमारी बेटी ने उठाया!

यह मुलाकात केवल एक शिष्टाचार भेंट नहीं थी, बल्कि भारतीय लोकतंत्र और राजनीतिक मूल्यों की विरासत को याद करने का एक महत्वपूर्ण अवसर भी बनी। प्रधानमंत्री और जेटली परिवार के बीच की यह संवादात्मक भेंट भारतीय राजनीति में साझा आदर्शों और पारिवारिक संबंधों की गर्मजोशी का प्रतीक कही जा सकती है।

भारतीय भाषाएं बनेंगी भारत को जोड़ने का सशक्त माध्यम : शाह

एजेंसी (हि.स.)
नई दिल्ली

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित राजभाषा विभाग के स्वर्ण जयंती समारोह में कहा कि भारतीय भाषाएं भारत को जोड़ने का सबसे सशक्त माध्यम बनेंगी। शाह ने कहा कि आने वाले समय में केंद्र और राज्यों के प्रशासन में भारतीय भाषाओं का उपयोग और भी बढ़ेगा। वह इसके लिए राज्यों से संपर्क करेंगे और उन्हें समझाने का प्रयास करेंगे। इस अवसर पर शाह ने राजभाषा हिन्दी और सभी भारतीय भाषाओं के प्रेमियों को शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा, हमें किसी भी भाषा या विदेशी भाषा से विरोध नहीं है, लेकिन आग्रह अपनी भाषा के सम्मान और उपयोग का होना चाहिए। जब तक हम अपनी भाषा में सोचेंगे और गर्व से बोलेंगे नहीं, तब तक गुलामी की मानसिकता से मुक्ति संभव नहीं है। राजभाषा विभाग की 1975 से 2025 तक की यात्रा का उल्लेख कर शाह ने कहा कि भारत की आजादी की शताब्दी (2047) तक देश के आत्मगौरव से जुड़े हर प्रयास में राजभाषा विभाग का योगदान स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज होगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि सरकारी प्रशासन आम नागरिकों की भाषा में हो, यह लोकतंत्र और आत्मसम्मान दोनों के लिए जरूरी है। शाह ने बताया कि अब जेईई, नीट और सीयूईटी जैसी परीक्षाएं 13 भारतीय भाषाओं में कराई जा रही हैं। सीएपीएफ कांस्टेबल भर्ती परीक्षा भी अब 13 भाषाओं में हो रही है और 95 प्रतिशत उम्मीदवारों ने अपनी मातृभाषा में परीक्षा दी है। यह दिखाता है कि भारतीय भाषाओं का भविष्य उज्ज्वल है। गृह मंत्री ने कहा कि हिंदी किसी भी भारतीय भाषा की विरोधी नहीं है। हिंदी सभी भाषाओं की मित्र है और सब भाषाएं मिलकर ही भारत के स्वाभिमान को ऊंचा उठा सकती हैं। उन्होंने कहा कि पहले भाषाओं का इस्तेमाल देश को बांटने के लिए किया गया, लेकिन अब उन्हें भारत को जोड़ने का जरिया बनाया जाएगा।

आपातकाल की 50वीं बरसी पर आयोजित कार्यक्रम में बोले केंद्रीय मंत्री

युवाओं को जानना चाहिए वह भयावह इतिहास: नितिन गडकरी

एजेंसी (हि.स.)
नई दिल्ली

केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने गुरुवार को कहा कि देश में 1975 में लगाए गए आपातकाल के दौरान लोकतंत्र को कुचलने का प्रयास हुआ था और उसकी रक्षा में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एवं उससे प्रेरित संगठनों की महत्वपूर्ण भूमिका रही। उन्होंने कहा कि आज के युवाओं को आपातकाल और इससे जुड़ा भयावह इतिहास जरूर जानना-समझना चाहिए।

केंद्रीय मंत्री गडकरी आपातकाल की 50वीं बरसी पर बहुभाषी न्यूज एजेंसी हिन्दुस्थान समाचार के तत्वावधान में डॉ. अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। गडकरी ने कहा कि तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने अपनी सत्ता बचाने के लिए संविधान के मूल भाव को बदला, प्रेस, संसद और न्यायपालिका पर दबाव डाला गया। उन्होंने बताया कि उस दौर में ऐसा भय का माहौल था कि लोग अपने अधिकारों के लिए भी आवाज नहीं उठा सकते थे।

गडकरी ने बताया कि 1975 में वह मैट्रिक के छात्र थे और आपातकाल की सुबह अखबार नहीं छपे थे। उस दौर में हजारों निर्दोष लोगों को जेल में डाल दिया गया। संविधान प्रदत्त मौलिक अधिकार समाप्त कर दिए गए थे। पुलिस की गोली से मारे गए व्यक्ति को भी न्याय मांगने का हक नहीं था।

उन्होंने जयप्रकाश नारायण द्वारा शुरू किए गए भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन की चर्चा करते हुए कहा कि बिहार आंदोलन के केंद्र में था, जिसमें अनेक छात्र संगठनों और संघ से प्रेरित कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। उन्होंने पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे, वरिष्ठ पत्रकार रामबहादुर राय और सामाजिक कार्यकर्ता केएन गोविंदाचार्य जैसे नेताओं के योगदान को भी याद किया।

गडकरी ने कहा कि रायबरेली चुनाव में सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग पर जब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इंदिरा गांधी के खिलाफ फैसला सुनाया, तब उन्होंने इस्तीफा देने की बजाय देश पर आपातकाल थोप दिया। उन्होंने कहा कि इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा जैसे नारों के जरिए चाटुकारिता की पराकाष्ठा देखी गई। इस दौरान कांग्रेस ने भारतीय संविधान की जमकर धज्जियां उड़ाईं, जबकि आज उसी पार्टी के नेता दूसरों पर संविधान बदलने का आरोप लगाते हैं।

गडकरी ने कहा कि आपातकाल का विरोध करने वालों में अटल बिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण आडवाणी, जॉर्ज फर्नांडिस जैसे नेता थे, जिन्हें जेल में डाल दिया गया था। संघ के हजारों कार्यकर्ताओं ने भूमिगत रहकर लोकतंत्र की रक्षा के लिए संघर्ष किया। उन्होंने कहा कि आपातकाल के 50 वर्ष हमें यह याद दिलाते हैं कि लोकतंत्र की रक्षा केवल कानून से नहीं, बल्कि लोगों की आस्था, संघर्ष और बलिदान से होती है। उन्होंने युवाओं से आग्रह किया कि वे इस इतिहास को जानें और लोकतंत्र की रक्षा के लिए सजग रहें।

स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल होगा नशे के प्रति जागरूकता पर आधारित अध्याय: सुक्खू

एजेंसी (हि.स.)
शिमला

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार मादक पदार्थों के दुरुपयोग के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए स्कूली पाठ्यक्रम में एक अध्याय शामिल करने जा रही है। मुख्यमंत्री ने मादक पदार्थों के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के विरुद्ध आज यहां अंतरराष्ट्रीय दिवस के अवसर पर आयोजित समारोह की अध्यक्षता करते हुए समाज के हर वर्ग से हिमाचल प्रदेश को नशा मुक्त राज्य बनाने के लिए मादक पदार्थों के दुरुपयोग के खिलाफ अभियान का हिस्सा बनने का आग्रह किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि देवभूमि में नशे के लिए कोई भी स्थान नहीं है। उन्होंने युवाओं से आह्वान किया कि वे खुद को नशे से दूर रखें और अपने साथियों को भी इस विनाशकारी रास्ते पर जाने से रोकें। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार नशा तस्करी से जुड़े नेटवर्क को जड़ से समाप्त करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। नशा मुक्ति से उबर रहे लोगों को रोजगार और उनका कौशल उन्नयन कर उन्हें मुख्य धारा से जोड़ा जा रहा है। इसी उद्देश्य से सिरमौर जिला के कोटला-बड़ोग में 5.34 करोड़ रुपये की लागत से 100 बिस्तर क्षमता का आधुनिक नशा मुक्ति केन्द्र स्थापित किया जा रहा है जिसका निर्माण कार्य आरंभ कर दिया गया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार का लक्ष्य प्रत्येक जिला में नशा मुक्ति केन्द्र स्थापित करना है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने सत्ता संभालने के उपरांत वर्ष 2023 में पीआईटी-एंडीपीएस एक्ट लागू किया है, जिसे पूर्व भाजपा सरकार पूरे पांच वर्षों में लागू करने में असमर्थ रही।

ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने उपस्थित लोगों को नशे के विरुद्ध शपथ दिलाई तथा राज्य में नशा निवारण के प्रति उत्कृष्ट कार्यों के लिए विभिन्न संस्थाओं और व्यक्तियों को सम्मानित किया। इनमें जिला कुल्लू के भुंतर नशा मुक्ति केन्द्र के डॉ. सत्याव्रत वैद्य, जिला कांगड़ा के बजीर राम सिंह राजकीय महाविद्यालय देहरी के प्राचार्य प्रो. सचिन कुमार, जिला सिरमौर कलगीधर ट्रस्ट बड़ू साहिब, एक पहल वेल्फेयर सोसायटी बिलासपुर, गुंजन ऑर्गेनाईजेशन फॉर कॉम्यूनिटी डवेल्पमेंट जिला ऊना, जिला सोलन के पुलिस अधीक्षक गौरव सिंह, जय बाबा कमलाहिया अराधना जिला हमीरपुर, जिला शिमला के चौपाल की मानव कल्याण सेवा समिति कराई, जिला शिमला के रोहडू के चिड़गांव के एन्टी ड्रग फोर्स के अध्यक्ष नरेन्द्र चौहान, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय जिला मंडी और जिला कुल्लू के विकास खंड निरमंड की ग्राम पंचायत जगातखाना शामिल हैं।

इस अवसर पर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. (कर्नल) धनी राम शांडिल ने कहा कि नशीली दवाओं के दुरुपयोग के विरुद्ध लड़ाई में और प्रयास करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि यह अभियान आजादी की लड़ाई जैसा जन आंदोलन बनाने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को सक्रिय रूप से भाग लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि नशा तस्कर समाज के दुश्मन हैं, जो देश के भविष्य को अंधकार में धकेल रहे हैं।

मंडी में अंतरराष्ट्रीय नशा निरोधक दिवस पर मंडी में जनजागरूकता कार्यक्रम आयोजित

एजेंसी (हि.स.)
मंडी

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के तत्वावधान में अंतरराष्ट्रीय नशा निरोधक दिवस के अवसर पर औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई) मंडी में जनजागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता उपायुक्त मंडी अपूर्व देवगन ने की। कार्यक्रम के दौरान उपायुक्त ने आईटीआई के प्रशिक्षुओं को अपने जीवन, परिवार, समाज और राष्ट्र को नशे की बुराइयों से मुक्त रखने की शपथ दिलाई। उन्होंने कहा कि जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए नशे से दूर रहना आवश्यक है। मेहनत तभी रंग लाएगी जब मन और शरीर स्वस्थ होंगे। उन्होंने युवाओं से अपील की कि वे स्वयं भी नशे से दूर रहें और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करें।

एडीसी गुरसिमर सिंह ने भी युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि नशे की लत अक्सर पीयर प्रेशर से शुरू होती है। इसे सामाजिक कलंक के रूप में देखने की बजाय एक बीमारी के रूप में देखा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि नशा करने वाले को साथ देकर ही उसे इस दलदल से बाहर निकाला जा सकता है। उन्होंने कहा कि नशे की रोकथाम केवल कानून से संभव नहीं, बल्कि इसके लिए समाज के हर वर्ग को मिलकर जन आंदोलन खड़ा करना होगा।

कार्यक्रम में विशेष रूप से एक पूर्व नशा उपयोगकर्ता ने भी अपनी आपबीती सांझा की। उन्होंने बताया कि यह सिलसिला सिगरेट से शुरू होकर शराब और अंततः चिट्टे तक पहुंच गया। उन्होंने युवाओं को आगाह किया कि नशा किसी भी समस्या का समाधान नहीं बल्कि विनाश की ओर पहला कदम है। उन्होंने समाज से आग्रह किया कि नशा ग्रस्त लोगों को सहयोग दें, न कि उन्हें हाशिए पर ढकेलें। यह एक मानसिक बीमारी है, और इसके इलाज में समय, सहानुभूति और इच्छाशक्ति की आवश्यकता होती है मनोचिकित्सक डॉ. अभिलक्ष कांगो ने नशे के लक्षण, उसके दुष्परिणाम, उपचार और रिकवरी प्रक्रिया पर विस्तार से जानकारी दी। वहीं, पुलिस उपाधीक्षक दिनेश कुमार ने समाज पर नशे के घातक प्रभावों की जानकारी देते हुए युवाओं को इससे बचने की सलाह दी।

मनूनी खड्ड हादसा : चार शव बरामद एक व्यक्ति जिंदा निकाला

एजेंसी (हि.स.)
धर्मशाला

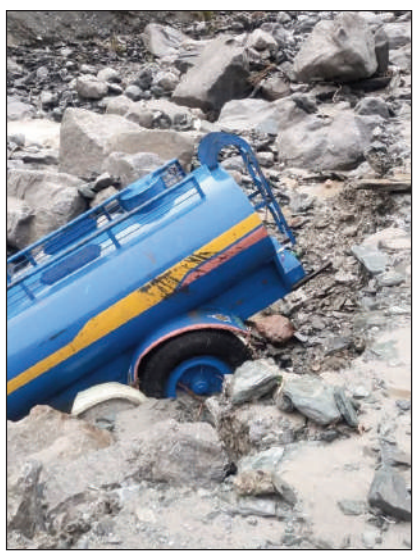

भारी बारिश ने जिला कांगड़ा के मुख्यालय धर्मशाला के साथ लगते खनियारा की मनूनी खड्ड में आई बाढ़ की चपेट में बहे मजदूरों में से अब तक चार शव बरामद कर लिए गए हैं जबकि एक को जीवित रेस्क्यू किया गया है। इस हादसे में मारे गए चार लोगों में आदित्य ठाकुर सुपुत्र शिव कुमार निवासी राख तहसील और जिला चंबा, चैन सिंह (20) सुपुत्र मुल्ख राज निवासी कुमादी तहसील भाल्ला जिला डोडा जम्मू कश्मीर, प्रदीप वर्मा (35) सुपुत्र राम कांत वर्मा निवासी सोहनपुर देवरिया उत्तर प्रदेश तथा चंदन सुपुत्र प्रदीप निवासी सोहनपुर देवरिया उत्तर प्रदेश शामिल हैं। वहीं रेस्क्यू दल ने एक व्यक्ति को जिंदा बचा लिया है। जिसकी पहचान लवली सुपुत्र सुरमा राम निवासी पूना डाकखाना सुनारा तहसील धरवाला जिला चंबा के रूप में हुई है। एसएसपी कांगड़ा शालिनी अग्निहोत्री ने यह पुष्टि की है।

उन्होंने बताया कि वहीं लापता अन्य लोगों को खोजने के लिए बीती रात से ही युद्ध स्तर पर सर्च ऑपरेशन चला हुआ है। सुरक्षा के दृष्टिगत पावर प्रोजेक्ट में कार्यरत बाकी लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया गया है। जिला प्रशासन पूरी सतर्कता एवं समन्वय के साथ राहत एवं बचाव कार्य में जुटा हुआ है। लापता व्यक्तियों की खोज के लिए सर्च ऑपरेशन को और अधिक तेज कर दिया गया है। राहत एवं बचाव कार्य लगातार युद्धस्तर पर जारी है। घटनास्थल पर राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल की दो टुकड़ियाँ तथा होम गार्ड की एक टीम तैनात है और निरंतर सर्च ऑपरेशन में जुटी हुई हैं।

नशे से बचाव के लिए समाज की एकजुटता आवश्यक है : आकांक्षा डोगरा

एजेंसी (हि.स.)
सोलन

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सोलन की सचिव आकांक्षा डोगरा ने कहा कि नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी से निपटने के लिए सम्पूर्ण समाज को एकजुटता से कार्य करने की आवश्यकता है तभी हम नशामुक्त समाज की परिकल्पना कर सकते हैं। आकांक्षा डोगरा वीरवार को यहां जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सोलन के सौजन्य से आयोजित एक जागरूकता शिविर को संबोधित कर रही थीं।

आकांक्षा डोगरा ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाने के लिए नशीली दवाओं के दुरुपयोग के खिलाफ जागरूकता और संवेदनशीलता के लिए विशेष अभियान चलाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि नशीली दवाओं के दुरुपयोग के विरूद्ध वर्ष 2025 के अंतर्राष्ट्रीय दिवस का नारा ह्यजंजीरों को तोड़ना सभी के लिए रोकथाम, उपचार और सुधारह्ण विषय रखा गया है। इस दिवस का मुख्य उद्देश्य बच्चों को नशे के सेवन से बचाना और नशीली दवाओं की तस्करी पर प्रतिबंध लगाना है ताकि बच्चों का भविष्य स्वर्णिम बन सके।

उन्होंने कहा कि इस दिन दुनियाभर में नशे के विरूद्ध जागरूकता अभियान चलाया जाता है। इसमें लोगों को नशे से होने वाले नुकसान से अवगत कराया जाता है। भारत में भी नशा और अवैध तस्करी को रोकने के लिए सख्त कानून का प्रावधान है, लेकिन फिर भी लोगों को जागरूक करने की नितांत आवश्यकता है। इसके लिए आमजन का सहयोग अपेक्षित रहता है। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय नशा निषेध दिवस के अवसर पर आस-पास के ऐसे लोग, जो नशा और अवैध नशे के व्यापार में लिप्त हैं, उन्हें सत्य की राह पर लाने की पहल करनी चाहिए। आकांक्षा डोगरा ने शिविर में उपस्थित महिलाओं को निःशुल्क कानूनी सहायता, मध्यस्थता, लोक अदालत राज्य पीड़ित मुआवजा योजना व नालसा के बारे में विस्तार से जानकारी प्रदान की।

संक्षिप्त-समाचार

स्कूल प्रिंसिपल पर महिला कर्मचारी से दुष्कर्म का आरोप, एफआईआर

शिमला। शिमला जिले के ठियोग उपमंडल में एक महिला से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। एक निजी स्कूल की महिला कर्मचारी ने स्कूल के प्रिंसिपल पर जबरन शारीरिक संबंध बनाने और जान से मारने की धमकी देने के आरोप लगाए हैं। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार महिला पिछले वर्ष 2024 से एक निजी स्कूल में कार्यरत है। पीड़िता ने पुलिस को बताया कि नौकरी जॉइन करने के कुछ ही समय बाद स्कूल प्रिंसिपल ने उस पर व्यक्तिगत दबाव डालना शुरू कर दिया। महिला का आरोप है कि प्रिंसिपल ने कई बार उसकी इच्छा के विरुद्ध उसके कमरे में तथा अन्य जगहों पर जबरन शारीरिक संबंध बनाए। पीड़िता के अनुसार जब उसने इसका विरोध किया तो प्रिंसिपल ने उसे गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी और जान से मारने तक की बात कही। महिला ने बताया कि वह मानसिक रूप से लंबे समय से तनाव में थी, लेकिन अब हिम्मत जुटाकर उसने पुलिस से संपर्क किया और पूरी घटना से अवगत करवाया।

एबीवीपी ने एनटी भर्ती में अनिवार्य उर्दू योग्यता परीक्षा के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया

जम्मू। नायब तहसीलदार भर्ती में अनिवार्य उर्दू परीक्षा के खिलाफ एबीवीपी द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया। उनका मानना है कि विविध भाषाई उम्मीदवारों के साथ यह भेदभाव है। सनक वत्स, राज्य सचिव, एबीवीपी जम्मू कश्मीर ने कहा कि सरकार का निर्णय एनटी भर्ती में नायब तहसीलदार पदों के लिए उर्दू को अनिवार्य योग्यता परीक्षा बनाना एक प्रतिगामी कदम है जो समानता और निष्पक्षता के सिद्धांतों को कमजोर करता है। हम इसकी मांग करते हैं सरकार राजस्व भर्ती नियमों पर पुनर्विचार करे और सुनिश्चित करे कि सभी अभ्यर्थी इन पदों के लिए प्रतिस्पर्धा करने का समान अवसर हो चाहे उनकी भाषा कोई भी हो । उर्दू को अनिवार्य रूप से लागू करने से न केवल उम्मीदवारों को नुकसान होगा बल्कि क्षेत्र की समृद्ध सांस्कृतिक विविधता को भी कमजोर करेगा। हम सरकार से अधिक समावेशी दृष्टिकोण अपनाने और भर्ती सुनिश्चित करने का आग्रह करते हैं। महानगर सचिव हरीश शर्मा ने कहा कि नायब के लिए उर्दू की परीक्षा अनिवार्य है जो क्षपातपूर्ण निर्णय है जो योग्य लोगों को अवसर से वंचित कर देगा

राजौरी जिले के कालाकोट में अचानक आई बाढ़ में दो बच्चों की मौत

राजौरी। जम्मू-कश्मीर के राजौरी जिले में कालाकोट तहसील के सियालसुई इलाके में गुरुवार सुबह अचानक आई बाढ़ में दो बच्चों की मौत हो गई और एक अन्य को बचा लिया गया। क अधिकारी ने बताया कि भारी बारिश के कारण अचानक आई बाढ़ में तीन बच्चे बह गए। दुख की बात है कि उनमें से दो की मौके पर ही मौत हो गई जबकि एक को स्थानीय लोगों ने सुरक्षित बचा लिया और नजदीकी चिकित्सा सुविधा में ले जाया गया। उन्होंने कहा कि पुलिस और स्थानीय लोगों के साथ एक बचाव दल ने घटना पर तुरंत प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि प्रशासन शोक संतप्त परिवारों को सभी आवश्यक सहायता प्रदान कर रहा है तथा स्थिति का आकलन करने और क्षेत्र की सुरक्षा सुनिश्चित करने के प्रयास जारी हैं। अधिकारियों ने जल निकायों और संवेदनशील स्थानों के पास रहने वाले निवासियों से सतर्क रहने और चल रही बारिश के दौरान सावधानी बरतने का आग्रह किया है।

अंतरराष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस पर संकाय और छात्रों ने शपथ ली

कठुआ। नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय दिवस के अवसर पर ऑपरेशन संजीवनी के बैनर तले जीडीसी मढ़हीन के शारीरिक शिक्षा विभाग द्वारा एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में 24 जून 2025 से 26 जून 2025 तक हस्ताक्षर अभियान जैसी दो गतिविधियाँ शामिल हैं और कॉलेज के संकाय और छात्रों द्वारा शपथ ली गई। कार्यक्रम का आयोजन गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज मढ़हीन की प्रिंसिपल प्रोफेसर अनुपमा गुप्ता के कुशल मार्गदर्शन में किया गया था। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में छात्रों ने सक्रिय रूप से भाग लिया। कार्यक्रम का प्रबंधन डॉ बलबिंदर सिंह (जीडीसी मढ़ीन के शारीरिक निदेशक) द्वारा किया गया था। अपने व्याख्यान में उन्होंने दिन के महत्व का वर्णन किया और छात्रों को नशीली दवाओं से संबंधित चुनौतियों से निपटने और एक स्वस्थ नशा मुक्त समाज को बढ़ावा देने के लिए प्रेरित किया। इस अवसर पर प्रोफेसर संदीप चैधरी, डॉ अरुण देव सिंह, प्रोफेसर अनूप शर्मा और डॉ मुनीषा देवी

जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग और मुगल रोड़ यातायात के लिए खुला

जम्मू। जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग और मुगल रोड़ गुरुवार को यातायात के लिए खुला है। आज छोटे वाहनों को राष्ट्रीय राजमार्ग के दोनों तरफ से जबकि बड़े वाहनों को केवल जम्मू से श्रीनगर की ओर रवाना किया जा रहा है। यातायात विभाग के अधिकारी ने बताया कि खराब मौसम के बावजूद जम्मू-श्रीनगर राजमार्ग पर वाहनों की आवाजाही रोजाना की तरह जारी है। छोटे वाहनों को अपनी लेन में चलने की हिदायत दी गई है और किसी भी वाहन को तेज चलने या फिर ओवरटेक करने से बचने की सलाह दी गई है ताकि राजमार्ग पर जाम की स्थिति न उत्पन्न हो सके। इसी बीच छोटे वाहनों को जम्मू से श्रीनगर और श्रीनगर से जम्मू दोनों तरफ से रवाना किया जा रहा है जबकि बड़े वाहनों को केवल जम्मू से श्रीनगर की ओर जाने इजाजत दी गई है।

आपातकाल संविधान पर था हमला, हर नागरिक को याद रखना चाहिए ये काला दिन : रिजिजू

एजेंसी (हि.स.)
शिमला

आपातकाल के 50 साल पूरा होने पर केंद्र सरकार द्वारा मनाए जा रहे 'संविधान हत्या दिवस' की कड़ी में केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने गुरूवार को शिमला में मॉक पार्लियामेंट, संगोष्ठी और पौधारोपण कार्यक्रमों में भाग लिया। रिजिजू ने इस अवसर पर पत्रकार वार्ता में आपातकाल को भारतीय लोकतंत्र का काला अध्याय बताते हुए कहा कि यह दिन पूरे देश को राजनीति से ऊपर उठकर याद रखना चाहिए, ताकि फिर कभी लोकतंत्र पर ऐसा हमला न हो।

रिजिजू ने कहा कि 1975 में एक परिवार की सत्ता बचाने के लिए पूरे देश पर आपातकाल थोपा गया, प्रेस की आजादी छीनी गई और नागरिक अधिकार कुचले गए। उन्होंने कहा कि आज वही नेता संविधान की दुहाई दे रहे हैं, जिन्होंने स्वयं बाबा साहेब अंबेडकर के बनाए संविधान को कुचलने का काम किया था।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि यह दिन सिर्फ राजनीति का विषय नहीं है बल्कि लोकतंत्र की चेतना को जीवित रखने का प्रतीक है। आज हम इस दिन को 'संविधान हत्या दिवस' के रूप में मना रहे हैं ताकि देश की नई पीढ़ी इस ऐतिहासिक भूल को न भूले। हिमाचल प्रवास के बारे में जानकारी देते हुए रिजिजू ने कहा कि वे तीन दिन के दौरे पर प्रदेश में हैं और जनजातीय लाहौल-स्पीति क्षेत्र में खेल सुविधाओं सहित करोड़ों की विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। चंबा, सिरमौर और ऊना जिलों में भी खेल और युवा कल्याण की योजनाएं लाई जाएंगी।

कांग्रेस पर हमला बोलते हुए रिजिजू ने कहा कि कांग्रेस ने सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़कों और बुनियादी ढांचे के लिए कुछ नहीं किया, लेकिन मोदी सरकार ने बॉर्डर इलाकों में मजबूत सड़कों के साथ चहुंमुखी विकास को प्राथमिकता दी है।

प्रदेश सरकार से सहयोग पर उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सुक्खू से भेंट कर केंद्र की योजनाओं में राज्य सरकार के सहयोग की अपेक्षा की है। उन्होंने यह भी कहा कि सियासी मजबूरी में मुख्यमंत्री केंद्र की मदद न मिलने का बयान दे रहे हैं, जबकि केंद्र सरकार हिमाचल की हरसंभव मदद कर रही है।

वक्फ बोर्ड संशोधन को लेकर पूछे गए सवाल पर उन्होंने स्पष्ट किया कि यह मुसलमानों के खिलाफ नहीं है बल्कि वक्फ के असीमित अधिकारों को संतुलित करने वाला एक संवैधानिक कदम है जिससे मुस्लिम समाज को ही लाभ मिलेगा।

नाहन में रोड सेफ्टी क्लब की बैठक में ट्रैफिक व्यवस्था सुधार को लेकर मंथन

एजेंसी (हि.स.)
नाहन

नाहन में बुधवार को एसपी कार्यालय के कॉन्फ्रेंस हॉल में रोड सेफ्टी क्लब की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता उप पुलिस अधीक्षक रमाकांत ठाकुर ने की। बैठक में शहर की ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर विशेष रूप से रात्रि 8 से 9 बजे के बीच बिना हेलमेट और ओवर स्पीडिंग करने वाले बाइक चालकों पर नियंत्रण के उपायों पर गंभीरता से चर्चा की गई। बैठक में ट्रैफिक से जुड़े अन्य प्रमुख मुद्दों जैसे अवैध पार्किंग, अतिक्रमण और व्यस्त समय में लगने वाले जाम को लेकर भी विभिन्न सुझाव सामने आए। सदस्यों ने सख्त चालान प्रणाली लागू करने, जन-जागरूकता अभियानों की शुरूआत करने और प्रमुख चौराहों पर अतिरिक्त निगरानी व्यवस्था स्थापित करने के सुझाव दिए। अधिकारियों ने इन सुझावों को गंभीरता से संज्ञान में लिया और आवश्यक कार्रवाई का भरोसा दिलाया। इस अवसर पर डीएसपी रमाकांत ठाकुर ने कहा कि यातायात नियमों का पालन केवल कानून के डर से नहीं, बल्कि एक जिम्मेदार नागरिक के कर्तव्य के रूप में किया जाना चाहिए। सभी के सहयोग से हम नाहन की ट्रैफिक व्यवस्था को अधिक सुरक्षित और व्यवस्थित बना सकते हैं।

ब्यास नदी से गाय को बजरंग दल के सदस्यों ने सुरक्षित निकाला, निभाई जिम्मेदारी

एजेंसी (हि.स.)
मंडी

मंडी के पंडोह बाजार ब्यास नदी के किनारे नदी की सिल्ट में फंसी एक गाय को बचाने के लिए बजरंग दल के सदस्यों ने मानवीय साहस और सेवा भावना का परिचय दिया। स्थानीय समाजसेवी रोहित कुमार ने सबसे पहले इस घटना को देखा और तुरंत बजरंग दल के कार्यकताओं को इसकी सूचना दी। सूचना मिलते ही बजरंग दल के अध्यक्ष सौरव गुलेरिया उर्फ. कान्हा अपने दल के सदस्यों के साथ मौके पर पहुंचे और बिना समय गंवाए बचाव कार्य में जुट गए।

सिल्ट में गहराई तक फंसी हुई गाय को निकालने के लिए रस्सियों और सामूहिक प्रयास से करीब एक घंटे की मेहनत के बाद सुरक्षित बाहर निकाला गया। बाद में स्थानीय पशु चिकित्सक की देखरेख में गाय को प्राथमिक उपचार दिया गया और उसे सुरक्षित स्थान पर भेजा गया।

बजरंग दल अध्यक्ष सौरव गुलेरिया ने बताया कि गौ सेवा ही सच्ची राष्ट्र सेवा है। हम हमेशा ऐसे कार्यों के लिए तत्पर रहते हैं। स्थानीय लोगों ने इस कार्य की सराहना करते हुए बजरंग दल और समाजसेवी रोहित कुमार का आभार व्यक्त किया। यह घटना न केवल मानवीय सेवा की मिसाल है बल्कि समाज में सकारात्मक संदेश भी देती है कि यदि इच्छाशक्ति हो, तो कोई भी जीवन बचाया जा सकता है। इस मोके पर बजरंग दल के सदस्य रविंद्र ठाकुर उर्फ रिंकू, देविंदर ठाकुर उर्फ डीके एवं अन्य सदस्य मौजूद रहे।

मौसम | **छह लापता, भारी वर्षा का अलर्ट जारी**

हिमाचल में बादल फटने से तबाही, दो शव बरामद

एजेंसी (हि.स.)
शिमला

हिमाचल प्रदेश में मानसून की पहली बड़ी बारिश ने भारी तबाही मचाई है। बीते 24 घंटे में कुल्लू और कांगड़ा जिलों में बादल फटने और अचानक आई बाढ़ से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। भारी वर्षा के कारण भूस्खलन, सड़कें बंद और बिजली आपूर्ति बाधित हुई है। मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटे के लिए और अधिक सतर्कता बरतने की चेतावनी दी है।

कांगड़ा जिले के धर्मशाला क्षेत्र में मनुनी खड्ड में बुधवार शाम आई बाढ़ में कई मजदूर बह गए। अब तक दो के शव बरामद हो चुके हैं, जबकि छह लापता हैं। लापता मजदूरों में दो उत्तर प्रदेश से, तीन नूरपुर से और एक चंबा से हैं। इनकी खोज में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और पुलिस की टीमें लगी हैं। राहत एवं बचाव कार्य तेजी से जारी हैं और जिला प्रशासन स्वयं मौके पर निगरानी कर रहा है।

प्रशासन ने संवेदनशील इलाकों में अलर्ट जारी कर लोगों को सतर्क रहने की अपील की है। निमार्णाधीन हाइड्रो प्रोजेक्ट में कार्यरत अन्य मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। उपायुक्त कांगड़ा ने भ्रामक अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है और स्पष्ट किया है कि अब तक दो लोगों की मौत की पुष्टि हुई है।

उधर कुल्लू के बंजार व सैंज क्षेत्र में भी बुधवार को बादल फटने से तीन लोग बह गए हैं। इलाके में कई वाहन, छोटे पुल और एक बिजली परियोजना को नुकसान पहुंचा है। बाहंग क्षेत्र में तीन दुकानें बह गईं जबकि नेशनल हाईवे-3 पर यातायात अस्थायी रूप से बाधित हुआ था जिसे अब बहाल कर दिया गया है। जनजातीय जिला लाहौल-स्पीति में स्थिति फिलहाल सामान्य है, लेकिन काजा-सुमदो और दारचा-शिंकुला सड़क मार्ग पर बाढ़ और भूस्खलन के कारण आवागमन बाधित है। बीआरओ इन मार्गों को बहाल करने में जुटा है।

प्रदेशभर में अब तक 171 सड़कें भूस्खलन या जलभराव के कारण बंद हैं। 550 से अधिक बिजली ट्रांसफार्मर ठप होने से ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली संकट गहराया है।

शिमला स्थित मौसम विज्ञान केंद्र ने कांगड़ा, मंडी, शिमला और सोलन जिलों के लिए आज गुरूवार के लिए भारी बारिश का ओरेंज अलर्ट जारी किया है। चंबा, सिरमौर और मंडी सहित अन्य जिलों में अचानक बाढ़ की चेतावनी दी गई है। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों तक वर्षा का सिलसिला जारी रह सकता है।

दैनिक सिटी दर्पण आईना सच का

नवोन्मेषक: स्व. कृष्णा शर्मा
स्व. गीता शर्मा
संस्थापक: सतपॉल शर्मा

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक एवं संपादक भुपेंद्र शर्मा द्वारा इंप्रेशन्ज प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग लिमिटेड, प्लॉट नं. 22, ग्राउंड फ्लोर, फेस-2, इंडस्ट्रियल एरिया, पंचकूला-134113 (हरियाणा) पर मुद्रित एवं 801/1 सेक्टर-40ए, चंडीगढ़ से प्रकाशित- 160036

सभी विवादों का केंद्र न्यायालय चंडीगढ़ होगा।

स्थानीय कार्यालय
801/1, सेक्टर-40ए, चंडीगढ़।
संपर्क: 7888450261
Email: citydarpan1@gmail.com

हरियाणा में शहीद सैनिकों एवं अर्धसैनिक बलों के बच्चों को मिलेगी छात्रवृत्ति

हरियाणा सरकार ने अपने संकल्प पत्र का एक और वादा किया पूरा

संवाददाता
चंडीगढ़

देश के वीर जवानों के सर्वोच्च बलिदान को श्रद्धांजलि स्वरूप, हरियाणा सरकार ने शहीद सैनिकों एवं अर्धसैनिक बलों के बच्चों के लिए एक विशेष छात्रवृत्ति योजना शुरू करने का निर्णय लिया है। वर्तमान सरकार ने अपने संकल्प पत्र में सैन्य सेवाओं के वीर शहीदों के बच्चों को छात्रवृत्ति प्रदान करने का वादा किया था, अब सरकार ने अपने वादे से भी आगे बढते हुए सैन्य सेवाओं के शहीदों के बच्चों के साथ-साथ शहीद अर्ध-सैनिक बलों के बच्चों को भी छात्रवृत्ति देने का निर्णय लिया है।

प्रधानमंत्री छात्रवृत्ति योजना से प्रेरित इस नई नीति के तहत कक्षा 6 से 12 तक के छात्रों को प्रतिवर्ष 60 हजार रुपए की छात्रवृत्ति दी जाएगी। स्नातक स्तर तक के विद्यार्थियों को 72 हजार रुपए प्रति वर्ष जबकि स्नातकोत्तर स्तर पर अध्ययनरत छात्रों को 96 हजार रुपए प्रति वर्ष छात्रवृत्ति मिलेगी।इस योजना से 189 छात्रों को छात्रवृत्ति के रूप में 1 करोड, 31 लाख 64 हजार रुपए की प्रोत्साहन राशि मिलेगी।

यह ऐतिहासिक निर्णय आज मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई हरियाणा कैबिनेट की बैठक में स्वीकृत किया गया। इस नीति का उद्देश्य शहीद सैनिकों और अर्धसैनिक बलों के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करने हेतु आर्थिक सहयोग प्रदान करना है, जिससे उनका भविष्य उज्जवल और सुरक्षित बन सके।

हरियाणा मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में आज यहाँ आयोजित राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा लघु खनिज रियायत, भण्डारण, खनिजों का परिवहन तथा अवैध खनन रोकथाम नियम, 2012 में संशोधन को स्वीकृति प्रदान की गई। संशोधन के तहत , किसानों को मुआवजा और रेंट प्रदान करने की प्रक्रिया को अधिक सुगमता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सरल बनाया गया है। इसके अतिरिक्त, पत्थर और रेत के लिए रॉयल्टी दरों में संशोधन किया गया है। पत्थर की रॉयल्टी 45 रुपये से बढ़ाकर 100 रुपये प्रति टन की गई है, जबकि रेत की रॉयल्टी को 40 रुपये से बढ़ाकर 80 रुपये प्रति टन किया गया है। बैठक में अंतर-राज्यीय खनिज परिवहन शुल्क लिए जाने को भी मंजूरी प्रदान की गई है।

खनिजों के अंतर-राज्यीय परिवहन के लिए 100 रुपये प्रति टन का शुल्क लगाया जाएगा। यदि ई-ट्रांजिट में गंतव्य हरियाणा के भीतर है, तो अंतर-राज्यीय पारगमन शुल्क 100 रुपये निर्धारित किया गया है, और यदि ई-ट्रांजिट में गंतव्य हरियाणा के बाहर कहीं भी है, तो 20 रुपये निर्धारित किया गया है। इन नियमों को हरियाणा लघु खनिज रियायत, खनिजों का भण्डारण, परिवहन एवं अवैध खनन निवारण नियम (संशोधन) नियम, 2025 कहा जाएगा।

तीन दिवसीय मैंगो मेला 4 से, सैनी करेंगे उद्घाटन

संवाददाता
चंडीगढ

हरियाणा के सहकारिता, विरासत व पर्यटन मंत्री डॉ. अरविंद शर्मा ने कहा है कि पिंजौर के प्रसिद्ध मुगलकालीन यादवेन्द्र गार्डन में पर्यटन विभाग व बागवानी विभाग द्वारा 4 जुलाई से 6 जुलाई तक 32वें मैंगो मेले का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने बताया मेले का उद्घाटन मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी करेंगे। देशभर के आम उत्पादकों द्वारा सैंकड़ों व विविधता से भरपूर किस्मों का प्रदर्शन मैंगो मेले में किया जाएगा। इसके लिए अधिकारियों को मैंगो मेले के शानदार आयोजन के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए हैं। विरासत व पर्यटन मंत्री डॉ. अरविंद शर्मा ने आज कैंप कार्यालय में हरियाणा पर्यटन विकास निगम के प्रबंध निदेशक डॉ. शालीन व अन्य अधिकारियों के साथ बैठक करके तैयारियों का जायजा लिया व उन्हें आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।पर्यटन मंत्री डॉ. अरविंद शर्मा ने कहा कि हरियाणा पर्यटन विकास निगम व बागवानी विभाग वर्ष 1992 से यादवेन्द्र गार्डन, पिंजौर में मैंगो मेले का आयोजन कर रहा है। मैंगो मेले के 32वें संस्करण का आयोजन इस बार 4 जुलाई से किया जाएगा, जो 6 जुलाई तक चलेगा। उन्होंने कहा कि देशभर से आम उत्पादक किसान सैकड़ों

- देशभर के आम उत्पादक सैंकड़ों किस्म के आमों की लगाएंगे प्रदर्शनी

किस्म के आम लेकर आएंगे और उनकी प्रदर्शनी भी लगाएंगे। पर्यटन विभाग और बागवानी विभाग द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित इस वार्षिक कार्यक्रम की शुरूआत देशभर में उगाए जाने वाले आमों की विविधतापूर्ण और समृद्ध किस्मों का जश्न मनाने और किसानों को अपनी उपज दिखाने के लिए एक मंच प्रदान करने के लिए की गई थी।

कैबिनेट मंत्री डॉ. अरविंद शर्मा ने कहा कि बीते सालों में आम मेला एक क्षेत्रीय उत्सव से बढ़कर अंतरराष्ट्रीय ख्याति के आयोजन में बदल चुका है। मेला न केवल आम की पारंपरिक किस्मों पर प्रकाश डालने के साथ-साथ आमजन को आम की नई प्रजातियों से भी परिचित कराने का बड़ा माध्यम बनता है। उन्होंने कहा कि आम मेला सिर्फ आमों का उत्सव नहीं है बल्कि यह सभी के लिए गतिविधियों और आकर्षणों से भरा उत्सव है। पर्यटन मंत्री डॉ. अरविंद शर्मा ने विभागीय अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि मैंगो मेले की पहचान अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बढे, इसके लिए इसका मीडिया, सोशल मीडिया के माध्यम से बेहतर प्रचार-प्रसार किया जाए। उन्होंने कहा कि मैंगो मेले में ढांचागत विकास से लेकर सांस्कृतिक कार्यक्रमों को लेकर समय से तैयारी की जाए, ताकि मेले में आने वाले आम प्रशंसकों व पर्यटकों को अच्छा अनुभव मिले। उन्होंने किसानों के लिए आम प्रतियोगिताओं, स्कूली विद्यार्थियों की प्रतियोगिताओं, पुरस्कार वितरण की सुनियोजित व्यवस्था बनाने पर जोर दिया, ताकि किसी को भी असुविधा का सामना न करना पड़े। कैबिनेट मंत्री डॉ. अरविंद शर्मा ने कहा कि आमजन फूड कोर्ट में देशभर से आए आम उत्पादकों की अलग-अलग किस्मों के आम के स्वाद का आनंद ले सकें, इसके लिए फूडकोर्ट में बेहतर व्यवस्था व स्वच्छता का विशेष ध्यान रखने के निर्देश अधिकारियों को दिए।

विधानसभा अध्यक्ष हरविन्द्र कल्याण ने दी सौगात

संवाददाता
चंडीगढ़

- पौने दो करोड़ में बनने वाले सामुदायिक केंद्र का किया शिलान्यास
- प्रोजेक्ट्स पूरा होने के बाद युवाओं को मिलेगे रोजगार के नए अवसर

हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष श्री हरविन्द्र कल्याण ने घरौंडा के फूरलक रोड पर पौने दो करोड़ की लागत से बनने वाले सामुदायिक केंद्र का शिलान्यास करते हुए कहा कि हलके में जिस गति से विकास कार्य हो रहे हैं, इससे अगले कुछ सालों में घरौंडा हलके की सूरत बदल जाएगी। इसका लाभ पूरे हलके की जनता को मिलेगा। हरविन्द्र कल्याण आज घरौंडा में फुरलक रोड पर सामुदायिक केंद्र का शिलान्यास करने के बाद जनसमूह को संबोधित कर रहे थे।

कल्याण ने कहा कि घरौंडा के विकास कार्यों की बात करें तो शहर में लड़कियों का स्कूल, पार्कों और बस अड्डे का निर्माण कराया गया। इसके अलावा, न केवल घरौंडा को उपमंडल का दर्जा दिलाया गया बल्कि हलके में 16 स्कूलों को सीनियर सैकेंडरी बनवाया गया, 40 नए पुल और 75 सड़कें बनवाई गईं।इतना ही नहीं अवैध कॉलोनियों को अप्रूव्ड घोषित करवा कर उन में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाई गईं। नए अस्पतालों के साथ-साथ युवाओं के लिए आईटीआई बनवाई गई। एनसीसी अकेडमी और रिंग रोड का निर्माण कार्य जारी है। मेडिकल यूनिवर्सिटी इसी साल शुरू हो जाएगी।

विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि घरौंडा हलके में तेजी से विकास कार्य हो रहे हैं। अब तरक्की की पक्की नींव रखी जा चुकी है। बड़े प्रोजेक्ट्स पूरा होने के बाद युवाओं को रोजगार के नए अवसर उपलब्ध होंगे।

डीटीपी की टीम ने लाडवा में तीन 3 अवैध कालोनियों व दुकान में किए गए निर्माण को किया नष्ट

अनिल गोयल
लाडवा

जिला नगर योजनाकार की टीम ने उपायुक्त के आदेशानुसार लाडवा में राजस्व संपदा लाडवा में 3 जगहों पर लगभग 14 एकड़ में पनप रही 3 अवैध कालोनियों व 200 वर्गमीटर में पनप रही एक अवैध दुकान को जिला प्रशासन की मदद से तोड़-फोड़ की कार्रवाई अमल में लाई गई।

जिला नगर योजनाकार अधिकारी विक्रम कुमार ने जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा कि राजस्व संपदा लाडवा के गांव बण में रादौर रोड पर स्थित लगभग 3 एकड़, गांव निवारसी पिपली में 200 वर्ग मीटर में स्थित एक दुकान को उपायुक्त के आदेशानुसार प्रशासन के सहयोग से तोडफोड़ की कार्रवाई अमल में लाई गई है।

डीटीपी विक्रम कुमार ने कहा कि उपायुक्त के आदेशानुसार डयूटी मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में पुलिस बल के साथ डीटीपी की टीम ने लाडवा में राजस्व संपदा लाडवा में गांव बण में अवैध निर्माण के साथ-साथ गांव निवारसी पिपली में 200 वर्ग मीटर में स्थित एक दुकान को पीले पंजे से हटाया गया। उन्होंने कहा कि डीटीपी विभाग के पास राजस्व संपदा लाडवा में 3 जगहों पर लगभग 14 एकड़ में पनप रही 3 अवैध कालोनियों व 200 वर्गमीटर में पनप रही एक अवैध दुकान के पनपने का मामला आया था।जिसके उपरांत विभाग द्वारा भूस्वामी और प्रॉपर्टी डीलरों को एचडीआर एक्ट 1975 की धाराओं के तहत नोटिस जारी कर जरूरी अनुमति लेने के आदेश दिए गए थे। परंतु भूस्वामी और प्रॉपर्टी डीलरों ना तो अवैध कालोनियों में किए जा रहें निर्माण को रोका और ना ही विभाग से अनुमति प्राप्त की।इस पर कार्रवाई करते हुए विभाग द्वारा इन अवैध कालोनियों में निर्माण को नष्ट करने का काम किया गया है।

उन्होंने लोगों को सचेत करते हुए कहा कि सस्ते प्लाटों के चक्कर में प्रॉपर्टी डीलर के बहकावे में आकर प्लाट ना खरीदें और ना ही किसी प्रकार का निर्माण कार्य करे।

इतना ही नहीं जमीन की खरीद करने से पहले डीटीपी कार्यालय से कॉलोनी की वैधता और अवैधता की जानकारी प्राप्त कर लें। सभी तहसीलदार और नायब तहसीलदार भी रजिस्ट्री करने से पहले सरकार द्वारा जारी हिदायतों की पालना करें। यदि कोई व्यक्ति अवैध कालोनियों में कोई प्लॉट खरीदता है तो उसके विरुद्ध भी डीटीपी कार्यालय द्वारा कार्रवाई अमल में लाई जाएगी और जिसमें 50 हजार का जुमार्ना व 3 साल की सजा का प्रावधान है।

संक्षिप्त-समाचार

कन्या महाविद्यालय, खरखौदा के अधिग्रहण को मिली मंजूरी

चंडीगढ़। हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक आज मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई। बैठक में कन्या महाविद्यालय, खरखौदा के अधिग्रहण से संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। महाविद्यालय के प्रबंधन की लगातार मांग और उच्च शिक्षा विभाग की पांच सदस्यीय विभागीय समिति की सिफारिश के आधार पर कन्या महाविद्यालय, खरखौदा के अधिग्रहण के प्रस्ताव को कैबिनेट द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई है।

भविष्य विभाग की स्थापना को कैबिनेट की मंजूरी

चंडीगढ़। मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में आज हुई हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक में ₹भविष्य विभाग (ऊक्षं९ईल्ल३ ड्ढ ञ्४३४९)₹ की स्थापना को मंजूरी दी गई। इस विभाग की स्थापना का उद्देश्य हरियाणा को ₹भविष्य-समर्थ₹ बनाना है। यह निर्णय हरियाणा सरकार के निर्धारित कार्य नियम, 1977 के नियम 5 व अनुसूचि के क्रम संख्या 20 के अंतर्गत लिया गया है। सरकार का उद्देश्य एक ऐसा संस्थागत ढांचा तैयार करना है जो पूर्वदृष्टि-आधारित शासन को प्रोत्साहित करे और सभी प्रशासनिक विभागों के बीच नीतिगत समन्वय को मजबूत बनाए। यह विभाग हरियाणा की ₹विजन 2047₹ नीति के अनुरूप एक ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था और समावेशी विकास के लक्ष्य को साकार करने के लिए दीर्घकालिक रणनीतिक पहलों, तकनीकी दृष्टिकोण और समेकित नीति निर्माण का नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करेगा।

मंत्रिमंडल ने विकास परियोजनाओं, 2025 के लिए नई भूमि खरीद नीति को दी मंजूरी

चंडीगढ़। हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में आज यहां हुई मंत्रिमंडल की बैठक में विकास परियोजनाओं के लिए सरकारी विभागों, उसकी संस्थाओं अर्थात बोर्ड एवं निगमों तथा सरकारी कंपनियों को स्वेच्छा से दी जाने वाली भूमि खरीद के लिए नीति, 2025 को मंजूरी दी गई। नीति का उद्देश्य, भूमि मालिकों को एक ऐसा मंच प्रदान करना है, जिससे वे उपयुक्त खरीदारों की अनुपलब्धता के कारण अत्यधिक आवश्यकता के समय अपनी भूमि को कम दामों पर बेचने से बच सकें। इसके अलावा, भूमि मालिक अपनी भूमि की पेशकश करके और उसका अधिकतम मूल्य प्राप्त करके सरकारी परियोजनाओं के निर्णय लेने में भाग ले सकते हैं। राज्य सरकार ने विकास परियोजनाओं के लिए सरकार को स्वेच्छा से दी जाने वाली भूमि की खरीद के लिए नीति अधिसूचित की थी, ताकि भूमि मालिकों द्वारा भूमि की डिस्ट्रेस सेल को रोका जा सके और राज्य में विकास परियोजनाओं के स्थान का चयन करते समय उन्हें निर्णय लेने में शामिल किया जा सके। इसके पश्चात यह महसूस किया गया कि इस नीति को और व्यापक बनाने की आवश्यकता है, जिसमें भूमि के एकत्रीकरण के लिए एग्रीगेटर्स को प्रोत्साहन देने तथा ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से उनके पंजीकरण से संबंधित प्रावधानों को शामिल किया जाए। इसके लिए एक समेकित नीति तैयार की गई है, जो वर्ष 2017 की नीति और उसमें समय-समय पर किए गए संशोधनों को प्रतिस्थापित करती है।

ट्रेजरी अधिकारी भर्ती नियमों में संशोधन को दी मंजूरी

चंडीगढ़। हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में आज हुई बैठक में खजाना कार्यालय के संचालन को बेहतर बनाने और सुदृढ़ करने के उद्देश्य से हरियाणा वित्त विभाग ट्रेजरी (ग्रुप बी) सेवा नियम, 1980 में संशोधन को मंजूरी दी गई। संशोधन के बाद भर्ती प्रक्रिया में आसानी होगी और ट्रेजरी विभाग में नियुक्तियों में अधिक योग्यता आधारित पारदर्शिता आएगी। संशोधित नियमों के तहत अब सहायक ट्रेजरी अधिकारी (एटीओ) के केवल 25 प्रतिशत पद पदोन्नति के माध्यम से भरे जाएंगे, जबकि पहले 50 प्रतिशत भरे जाते थे। इसके अलावा, अब शेष 75 प्रतिशत पद हरियाणा लोक सेवा आयोग (एचपीएससी) द्वारा सीधे भर्ती किए जाएंगे, जोकि पहले 50 प्रतिशत होता था। ट्रेजरी ऑफिसर (टीओ) और असिस्टेंट ट्रेजरी ऑफिसर के पदों पर भर्ती में तीन पेपर होंगे।

मादक पदार्थ दुरुपयोग के खिलाफ एकजुट होकर करे कार्रवाई: बंडारू दत्तात्रेय

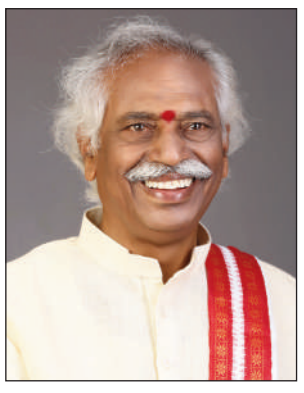

संवाददाता
चंडीगढ़

हरियाणा के राज्यपाल श्री बंडारू दत्तात्रेय ने गुरुवार को अंतरराष्ट्रीय मादक पदार्थ दुरुपयोग एवं अवैध तस्करी विरोधी दिवस के अवसर पर नशे के खतरे से लड़ने और युवाओं के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए हरियाणा की दृढ़ प्रतिबद्धता को दोहराया। उन्होंने नशा मुक्त समाज के निर्माण के लिए सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता पर बल दिया।

राज्यपाल ने कहा कि मादक पदार्थों का दुरुपयोग केवल स्वास्थ्य संकट तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हमारे सामाजिक ताने-बाने, राष्ट्रीय प्रगति और युवा पीढ़ी के भविष्य के लिए गंभीर खतरा है।इस चुनौती से निपटने के लिए सरकार, नागरिक समाज, शैक्षणिक संस्थानों, गैर-सरकारी संगठनों और परिवारों को मिलकर एक समग्र और समन्वित दृष्टिकोण अपनाना होगा।

दत्तात्रेय ने मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में हरियाणा सरकार के मादक पदार्थों के खिलाफ चलाए जा रहे कठोर अभियानों की सराहना की। पिछले एक वर्ष में, राज्य पुलिस और अन्य एजेंसियों ने कई प्रभावी अभियानों के माध्यम से मादक पदार्थों की बड़ी खेप जब्त की। नशा मुक्त भारत अभियान के तहत हरियाणा में चलाए जा रहे जागरूकता कार्यक्रमों ने भी उल्लेखनीय सफलता हासिल की है।ये कार्यक्रम स्कूलों, कॉलेजों, नुक्कड़ नाटकों, सामुदायिक कार्यशालाओं और पुनर्वास पहलों के माध्यम से लाखों लोगों, विशेषकर युवाओं तक पहुँचे हैं।

राज्यपाल ने नशे की लत से जूझ रहे व्यक्तियों के लिए पुनर्वास और नशा मुक्ति सेवाओं के विस्तार पर विशेष जोर दिया। उन्होंने कहा कि हमें नशे की चपेट में आए लोगों को सहानुभूति और समर्थन के साथ मुख्यधारा में वापस लाने की आवश्यकता है। इसके लिए अधिक पुनर्वास केंद्र, परामर्श सेवाएँ और सामुदायिक सहायता कार्यक्रम स्थापित किए जाने चाहिए।

पैरा ओलंपिक और एशियाई खेलों के पदक विजेताओं ने चंडीगढ़ में आरती सिंह राव से की मुलाकात

संवाददाता
चंडीगढ़

हरियाणा पैरा स्पोर्ट्स एसोसिएशन के तत्वावधान में पेरिस 2024 पैरा ओलंपिक और एशियाई खेलों के पदक विजेता खिलाड़ियों ने हरियाणा की स्वास्थ्य मंत्री एवं हरियाणा पैरा स्पोर्ट्स एसोसिएशन की अध्यक्ष कुमारी आरती सिंह राव से उनके चंडीगढ़ स्थित आवास पर मुलाकात की।

इस अवसर पर खिलाड़ियों ने अपनी मांगों, जैसे नकद इनाम और खेल कोटे के तहत नौकरी को लेकर एक लिखित ज्ञापन मंत्री को सौंपा। खिलाड़ियों की मांगों पर त्वरित और सकारात्मक प्रतिक्रिया देते हुए कुमारी आरती सिंह राव ने उन्हें हरसंभव सहायता का आश्वासन दिया। उन्होंने इस मुद्दे के शीघ्र समाधान के लिए खेल मंत्री श्री गौरव गौतम से बातचीत की और खेल विभाग के महानिदेशक एवं प्रमुख सचिव को भी आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए।

इस अवसर पर पैरा ओलंपिक पदक विजेता नितेश कुमार (बैडमिंटन), हरविंदर सिंह (तीरंदाजी), मनीष नरवाल (शूटिंग), नवदीप सिंह (भाला फेंक), पैरा एशियाई खेलों की पदक विजेता कोकिला (जूडो), पूजा (एथलेटिक्स), सरिता (तीरंदाजी), अशोक मलिक (पावरलिफ्टिंग), हनी (एथलेटिक्स) सहित अन्य खिलाड़ी उपस्थित रहे। इस मौके पर हरियाणा पैरा स्पोर्ट्स एसोसिएशन के महासचिव ज्योति कुमार छाबड़ा, कोषाध्यक्ष पवन अढाना और सचिव सुरेंद्र सिंह भी मौजूद रहे।

हरियाणा में मॉडल ऑनलाइन तबादला नीति के तहत नोडल अधिकारी नियुक्त करने के निर्देश

संवाददाता
चंडीगढ़

- 27 जून को न्यू हरियाणा सिविल सचिवालय में होगा प्रशिक्षण सत्र

हरियाणा सरकार ने मॉडल ऑनलाइन तबादला नीति को अमलीजामा पहनाने के मकसद से नीति के अनुसार, हर विभाग को ग्रुप ह्यएह्न या ग्रुप ह्यबीह्न श्रेणी के नोडल अधिकारी नियुक्त करने के निर्देश दिए हैं। इन नोडल अधिकारियों को कल यानी 27 जून को प्रातः 10.00 बजे सेक्टर-17, चंडीगढ़ स्थित न्यू हरियाणा सिविल सचिवालय में प्रशिक्षण सत्र में भाग लेने के भी निर्देश दिए गए हैं ताकि नई व्यवस्था को सुचारू तरीके चलाया जा सके। मुख्य सचिव श्री अनुराग रस्तोगी ने इस सम्बन्ध में 47 विभागों के 22 प्रशासनिक सचिवों को निर्देश जारी किए हैं।

नोडल अधिकारी संयुक्त निदेशक स्तर या उससे ऊपर का होगा, जो ऑनलाइन तबादला नीति के कार्यान्वयन में सम्बन्धित प्रशासनिक सचिव की सहायता करेगा। साथ ही, सरकार ने ऑनलाइन तबादला नीति में शामिल किए जाने या इससे निकाले जाने वाले काडर की सूची भी प्रकाशित करने के निर्देश दिए हैं। नोडल अधिकारी की नियुक्ति और काडर सूची के प्रकाशन का कार्य एचआरएमएस पोर्टलह्न के माध्यम से किए जाएंगे।

ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी मेनू से नोडल मास्टर एमओटीपी विकल्प चुनेगा, पात्र अधिकारियों की सूची डाउनलोड करेगा, उसमें से उपयुक्त अधिकारी का चयन कर स्वीकृत नोटिंग अपलोड करेगा और ओटीपी सत्यापन के माध्यम से नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करेगा। चयनित अधिकारी दिसंबर 2026 से पहले सेवानिवृत्त नहीं होना चाहिए। पोर्टल में नोडल अधिकारी का संपादन (एडिट) भी किया जा सकता है।

लाभ

2 लाख से अधिक कर्मचारियों को मिलेगा लाभ

हरियाणा ने एनपीएस के तहत एकीकृत पेंशन योजना को अपनाया

संवाददाता
चंडीगढ़

हरियाणा सरकार ने कर्मचारियों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए राज्य में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के तहत भारत सरकार द्वारा अधिसूचित एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) को लागू करने का निर्णय लिया है। इस ऐतिहासिक कदम के तहत यह 1 अगस्त, 2025 से प्रभावी होगी। 1 जनवरी, 2006 को या उसके बाद सरकार सेवा में आए 2 लाख से अधिक कर्मचारियों को लाभ मिलने की संभावना है। इस आशय का निर्णय आज यहां मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया। राज्य मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित इस योजना का उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों को सुनिश्चित पेंशन, पारिवारिक पेंशन और सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन देना है।

नई एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) राज्य सरकार के कर्मचारी को सेवानिवृत्ति से पहले 12 महीनों के दौरान प्राप्त औसत मूल वेतन का 50% प्रदान करेगी, बशर्ते कर्मचारी 25 साल की सेवा पूरी कर ले। यदि कर्मचारी 10 या उससे अधिक वर्ष की अर्हक सेवा पूरी करने के बाद सेवानिवृत्त होता है, तो उसे प्रति माह 10,000 रुपये का न्यूनतम गारंटीकृत भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा। पेंशनभोगी की मृत्यु की स्थिति में, परिवार को अंतिम आहरित पेंशन राशि का 60% प्राप्त होगा। यह महंगाई राहत सुनिश्चित पेंशन भुगतान और पारिवारिक पेंशन दोनों पर लागू होगी, जिसकी गणना सेवारत कर्मचारियों पर लागू महंगाई भत्ते के समान ही की जाएगी। हालांकि, महंगाई राहत केवल तभी देय होगी जब पेंशन भुगतान शुरू हो जाएगा।

सेवानिवृत्ति के समय एकमुश्त भुगतान की भी अनुमति दी जाएगी, जो अर्हक सेवा के प्रत्येक पूर्ण छह महीने के लिए मासिक परिलब्धियों (मूल वेतन + महंगाई भत्ता) का 10% होगा। यह एकमुश्त राशि सुनिश्चित पेंशन भुगतान को प्रभावित नहीं करेगी। वर्तमान नई पेंशन योजना के तहत, कर्मचारी 10% अंशदान करते हैं, जबकि राज्य सरकार 14% योगदान करती है। यूपीएस के कार्यान्वयन के साथ, सरकार का योगदान बढ़कर 18.5% हो जाएगा, इससे सरकार के खजाने पर लगभग 50 करोड़ रुपये मासिक और 600 करोड़ रुपये का वार्षिक वित्तीय भार पड़ेगा। एकीकृत पेंशन योजना के तहत कोष में दो निधियाँ शामिल होंगी: एक व्यक्तिगत कोष जिसमें कर्मचारी अंशदान और हरियाणा सरकार से प्राप्त योगदान शामिल होगा जो हरियाणा सरकार से अतिरिक्त योगदान द्वारा वित्त पोषित एक पूल कार्पस फंड के रूप में संचालित होगा।

योजना के तहत कर्मचारी अपने (मूल वेतन + महंगाई भत्ते) का 10% योगदान देंगे, जिसमें हरियाणा सरकार से मिला बराबर योगदान होगा। दोनों राशियाँ प्रत्येक कर्मचारी के व्यक्तिगत कोष में जमा की जाएँगी। इसके अलावा, हरियाणा सरकार वढर का विकल्प चुनने वाले सभी कर्मचारियों के (मूल वेतन + महंगाई भत्ते) का अनुमानित 8.5% औसत आधार पर पूल कार्पस में योगदान करेगी। इस अतिरिक्त योगदान का उद्देश्य योजना के तहत सुनिश्चित भुगतान करना है। कर्मचारी अपने व्यक्तिगत कोष के लिए निवेश विकल्पों का उपयोग कर सकते हैं, जिसे पेंशन फंड विनियामक और विकास प्राधिकरण (ढक्रष्ठ्रअ) द्वारा विनियमित किया जाएगा। यदि कोई कर्मचारी निवेश वरीयता निर्दिष्ट नहीं करता है, तो पीएफआरडीए द्वारा परिभाषित निवेश का 'डिफॉल्ट पैटर्न' लागू होगा। अतिरिक्त सरकारी अंशदान द्वारा वित्तपोषित पूल कॉर्पस के लिए निवेश निर्णय पूरी तरह से हरियाणा सरकार द्वारा प्रबंधित किए जाएंगे।

जो कर्मचारी यूपीएस के चालू होने से पहले सेवानिवृत्त हुए और यूपीएस का विकल्प चुनते हैं, उनके लिए पीएफआरडीए टॉप-अप राशि प्रदान करने की व्यवस्था निर्धारित करेगा। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत हरियाणा सरकार के मौजूदा कर्मचारियों के साथ-साथ भविष्य के कर्मचारियों के पास एनपीएस के तहत एकीकृत पेंशन योजना चुनने या यूपीएस विकल्प के बिना मौजूदा एनपीएस को जारी रखने का विकल्प होगा। एक बार जब कोई कर्मचारी यूपीएस का विकल्प चुनता है, तो योजना की सभी शर्तें स्वीकार की जाएंगी, और यह विकल्प अंतिम होगा। बोर्ड/निगमों/सार्वजनिक उपक्रम ब्यूरो तथा राज्य के विश्वविद्यालयों आदि में यूपीएस के कार्यान्वयन के बारे में निर्णय बाद में अलग से लिया जाएगा।

संपादकीय

भारत का अंतरिक्ष क्षेत्र: निजी भागीदारी से वैश्विक उड़ान की ओर

भारत का अंतरिक्ष क्षेत्र निजी कंपनियों की बढ़ती भागीदारी के साथ बदलाव के दौर में है।इसरो ने उपग्रह लांचर निर्माण हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड को सौंपकर पुनः प्रयोज्य रॉकेट और कक्षीय सुरक्षा जैसी तकनीकों पर ध्यान केंद्रित किया है।यह स्काईरूट, अग्निकुल और पिक्सल जैसे स्टार्टअप्स के प्रयासों को मजबूती देता है।वैश्विक अंतरिक्ष हब बनने की राह में सार्वजनिक और निजी क्षेत्र का तालमेल बेहद अहम है।आइये बात करते हैं भारत के अंतरिक्ष उद्योग के विस्तार में निजी क्षेत्र के अतुल्य योगदान की।इन-स्पेस के माध्यम से निजी क्षेत्र की भागीदारीः वर्ष 2020 में भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्द्धन और प्राधिकरण केंद्र की स्थापना एक ऐतिहासिक बदलाव था, जिससे भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी क्षेत्रों की भागीदारी बढ़ गई। इसरो और गैर-सरकारी संस्थाओं के बीच सहयोग को बढ़ावा देकर, इन-स्पेस ने उपग्रह प्रक्षेपण और अंतरिक्ष-आधारित सेवाओं में निजी क्षेत्र की भागीदारी को काफी हद तक बढ़ा दिया है।उदाहरण के लिये, एक निजी कंपनी, स्काईरूट एयरोस्पेस, वर्ष 2022 में सबऑर्बिटल रॉकेट, विक्रम-एस, लॉन्च करने वाली पहली कंपनी बन गई।भारत के अंतरिक्ष स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र में तीव्र वृद्धि देखी गई है, जिसमें अग्निकुल कॉसमॉस और ध्रुव स्पेस जैसे स्टार्टअप प्रक्षेपण यान प्रौद्योगिकी, उपग्रह निर्माण और अंतरिक्ष सेवाओं में अग्रणी हैं।सिर्फ वर्ष 2021 में ही भारतीय अंतरिक्ष स्टार्टअप्स ने 68 मिलियन डॉलर का निवेश प्राप्त किया, जो वर्ष-दर-वर्ष 196% की वृद्धि को दशार्ता है।महत्त्वपूर्ण अंतरिक्ष अवसंरचना के निर्माण के लिये इसरो और हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड, गोदरेज एयरोस्पेस और एल एंड टी जैसी उद्योग की दिग्गज कंपनियों के बीच साझेदारी के माध्यम से सार्वजनिक-निजी सहयोग को और बढ़ावा मिला है। ये कंपनियाँ प्रक्षेपण वाहनों, अंतरिक्ष यान और उपग्रह उप-प्रणालियों के लिये घटकों के निर्माण में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, जिससे अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में भारत की आत्मनिर्भरता बढ़ती है। निजी क्षेत्र के साथ भारतीय अंतरिक्ष क्षेत्र के सहयोग से प्रक्षेपण वाहनों में नवाचारों को बढ़ावा मिला है, जैसे लघु उपग्रह प्रक्षेपण वाहन और पुनः प्रयोज्य प्रक्षेपण वाहन का विकास। देश भर में अंतरिक्ष पार्कों की स्थापना छोटे उपग्रह निर्माण और प्रक्षेपण सेवाओं के लिये केंद्र के रूप में भी काम करेगी, जिससे निजी क्षेत्र की भागीदारी को और बढ़ावा मिलेगा। वर्ष 2023 में, एस एस एल वी प्रौद्योगिकी के सफल परीक्षण हुए, जो वाणिज्यिक अनुप्रयोगों के लिये आवश्यक छोटे उपग्रहों के लिये सस्ती, मांग पर प्रक्षेपण सेवाएँ प्रदान करने की दिशा में एक कदम होगा। अंतरिक्ष क्षेत्र को निजी क्षेत्र के लिये खोलने से वैश्विक अंतरिक्ष बाजार में भारत की स्थिति मजबूत हुई है।विदेशी उपग्रहों के प्रक्षेपण जैसी पहलों के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के साथ, इसरो की वाणिज्यिक शाखा न्यूस्पेस इंडिया लिमिटेड ने भारत की उपग्रह प्रक्षेपण सेवाओं के निर्यात में मदद की है।वर्ष 2023 में, इसरो विदेशी देशों के लिये 42 उपग्रहों को लॉन्च करेगा, जिससे वैश्विक अंतरिक्ष व्यावसायीकरण में भारत की बढ़ती उपस्थिति में योगदान मिलेगा।अंतरिक्ष-आधारित अनुप्रयोगों, विशेषकर संचार, सुदूर संवेदन और पृथ्वी अवलोकन में, इसरो और निजी क्षेत्र दोनों का महत्त्वपूर्ण योगदान रहा है।ये प्रौद्योगिकियाँ डिजिटल समावेशन को बढ़ावा, कृषि में सुधार और आपदा प्रबंधन को बढ़ा रही हैं। इसरो और निजी संस्थाओं द्वारा उपग्रह समूहों और पृथ्वी अवलोकन उपग्रहों के प्रक्षेपण से कृषि, दूरसंचार और शहरी नियोजन जैसे क्षेत्रों में बदलाव आ रहा है। वर्ष 2025 तक उपग्रह सेवाओं से अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में 36% का योगदान होने की उम्मीद है, जिसमें रिमोट सेंसिंग भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र में सबसे अधिक वृद्धि दर दर्ज करेगी। भारत का अंतरिक्ष उद्योग रॉकेटों के लिये हरित प्रणोदन प्रणालियों जैसी धारणीय अंतरिक्ष प्रौद्योगिकियों के विकास में भी अग्रणी है।बेलाट्रिक्स एयरोस्पेस जैसी स्टार्टअप कंपनियाँ इन प्रौद्योगिकियों में अग्रणी हैं, जिनका लक्ष्य अंतरिक्ष मिशनों के नकारात्मक पर्यावरणीय प्रभाव को कम करना है। यह अंतरिक्ष अन्वेषण और उपग्रह प्रक्षेपण प्रणालियों में पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकियों को अपनाने की वैश्विक प्रवृत्ति के अनुरूप है।बेलाट्रिक्स एयरोस्पेस ने पहले ही ब्रिटेन और फ्राँस की कंपनियों के साथ प्रणोदन प्रणालियों के लिये समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं, जो अंतरिक्ष स्थिरता में भारत के नवाचार का परिचायक है।भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी संस्थाओं के एकीकरण से संबंधित कई चिंताएं भी हैं जैसे नियामक एवं नीतिगत चुनौतियाँ, बौद्धिक संपदा संबंधी चिंताएँ, वित्तीय स्थिरता और निवेश अंतराल, राष्ट्रीय सुरक्षा और सामरिक चिंताएँ, तकनीकी अंतराल और विशेषज्ञता संबंधी बाधाएँ, विखंडित उद्योग और बेहतर पारिस्थितिकी तंत्र का अभाव कुशल कार्यबल की कमी आदि। आइये समझते हैं कि भारत अंतरिक्ष क्षेत्र में सक्रिय सार्वजनिक-निजी भागीदारी को किस प्रकार बढ़ावा दे सकता है। निजी अभिकताओं के लिये नियामक ढाँचे को सुव्यवस्थित करना, एकीकृत अंतरिक्ष नवाचार पारिस्थितिकीय तंत्र का निर्माण, वित्तीय सहायता के साथ अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी नवाचार को प्रोत्साहित करना, निजी विकास को प्रोत्साहित करने के लिये सरकारी अनुबंधों का लाभ उठाना, विशिष्ट अंतरिक्ष कार्यबल का विकास, अंतरिक्ष अवसंरचना में निजी निवेश को प्रोत्साहित करना, उन्नत बौद्धिक संपदा एवं प्रौद्योगिकी हस्तांतरण नीति की स्थापना, भारतीय अंतरिक्ष प्रौद्योगिकियों के निर्यात को बढ़ावा देना आदि शामिल हैं। अंत में कह सकते हैं कि भारत का अंतरिक्ष क्षेत्र बढ़ी हुई सार्वजनिक-निजी भागीदारी के माध्यम से महत्त्वपूर्ण वृद्धि के लिये तैयार है। बा' अंतरिक्ष संधि (1967) तथा अंतरिक्ष मलबे शमन दिशा-निर्देशों (2007) के अनुरूप विनियमों को सुव्यवस्थित करके, भारत नवाचार को बढ़ावा दे सकता है और अंतर्राष्ट्रीय अनुपालन सुनिश्चित कर सकता है।कार्यबल विकास एवं बौद्धिक संपदा अधिकारों को प्राथमिकता देने से भारत को राष्ट्रीय हितों की रक्षा करते हुए वैश्विक अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में अधिक प्रभावी ढंग से एकीकरण में सहायता प्राप्त होगी।

आज का राशिफल

मेषः अपने व्यवहार को लेकर लोगों के बीच आपका सम्मान बढ़ेगा। आप नया व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। गले में इन्फेक्शन और जुकाम की समस्या हो सकती है। किसी दीर्घकालिक लक्ष्य को लेकर आप योजना बना सकते हैं।किसी को बिना माँगे राय न दें।

वृषभः आपकी सेहत बहुत ही अच्छी रहेगी।कारोबार में आपको अपेक्षाकृत लाभ प्राप्त होगा। आप आज काफी ज्यादा व्यस्त रहेंगे।उलझे हुये मामलों को आप सुलझाने का प्रयास करें।जीवनसाथी की सलाह आपके काफी काम आने वाली है। अचानक धन लाभ हो सकता है।

मिथुनः परिवार में प्रसन्नता का वातावरण रहेगा। आर्थिक मामलों में लापरवाही न करें। आपके आत्मविश्वास में कमी आ सकती है। तनाव आपके ऊपर हावी हो सकता है। धन उधार देने से आपको बचना चाहिये।पेट खराब होने की सम्भावना है।

कर्कः पति-पत्नी के मध्य आपसी सामंजस्य बहुत अच्छा रहेगा।रक्तचाप की समस्या से निजात मिल सकती है।नया कारोबार शुरू करने के योग बन रहे हैं।नयी सम्पत्ति खरीद सकते हैं।सभी काम समय पर पूरा कर लेंगे।पुराने मित्रों से अपेक्षित मदद मिलेगी।

सिंहः मानसिक अशान्ति के कारण एकाग्रता में कमी हो सकती है।एक साथ कई काम करने पड़ेंगे। बच्चों के ऊपर गर्व की अनुभूति होगी। दोस्तों पर आँख-मूँदकर विश्वास न करें। आपका फोन खराब हो सकता है।नींद पर्याप्त मात्रा में अवश्य लें।

कन्याः दाम्पत्य जीवन काफी रोमान्टिक रहेगा। आपको नयी जिम्मेदारियाँ मिल सकती है।जोखिम भरे निवेश लाभकारी सिद्ध हो सकते हैं। साझेदारी वाले व्यवसाय में विशेष उन्नति की सम्वभावना बन रही है।युवाओं को प्रेम प्रस्ताव मिल सकते हैं।

तुलाः आपको सहकर्मियों से मदद मिल सकती है। आज बहुत सारा समय आत्ममन्थन में व्यतीत होगा।सोशल मीडिया में आप महत्वपूर्ण मुद्दों की चर्चा में सम्मिलित हो सकते हैं।व्यापार में कुछ कमी महसूस होगी। दाम्पत्य सम्बन्धों में निकटता बढ़ेगी।

वृश्चिकः अपनी आवश्यकताओं से अधिक धन खर्च न करें। आपके भीतर नयी ऊर्जा का संचार होगा। कड़ी मेहनत के बाद ही सफलता मिलेगी। अजनबियों से अपने मन की बातें शेयर न करें। गृहकार्यों में पूरा ध्यान नहीं दे पायेंगे। भविष्य को लेकर योजना बना सकते हैं।

धनुः धैर्य में कमी होने के कारण महत्वपूर्ण अवसरों को खो सकते हैं।अपनी वाणी में नियन्त्रण रखने की आवश्यकता है।अप्रिय कार्यों में आप रुचि ले सकते हैं।बच्चों की परवरिश पर ध्यान अवश्य दें। ऑनलाइन पेमेन्ट आदि के दौरान विशेष सावधानी रखें।

मकरः नयी वस्तुओं को खरीद सकते हैं।पुराने ऋणों को चुकाने के लिये दिन बहुत अच्छा है।घर के अनुभवी सदस्यों से राय अवश्य लें। व्यापारियों के लिये दिन बहुत ही अच्छा है। अपने उत्पादों की गुणवत्ता पर ध्यान दें।प्रेम सम्बन्धों में प्रगाढ़ता बढ़ेगी।

कुंभः समाज में आपको मान-सम्मान की चिन्ता रहेगी।विद्युतीय उपकरणों में खराबी आ सकती है। वरिष्ठ अधिकारियों से बहसबाजी न करें।नयी व्यापारिक साझेदारी होने के योग बन रहे हैं।राजनीति से जुड़े लोगों को सावधानी पूर्वक बयानबाजी करनी चाहिये।

मीनः आपकी कार्यक्षमता में वृद्धि होगी। तकनीकी विषयों के अध्ययन में आप रुचि ले सकते हैं। पारिवारिक सदस्यों के साथ हँसी-मजाक भरा समय बितायेंगे।मानसिक तनाव और भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो सकती है।पाचन सम्बन्धी परेशानियों का सामनो करनो पड़ेगा।

अमर है बंकिम चंद्र चटोपाध्याय का गीत 'वन्दे मातरम्...'

रमेश शर्मा (हि.स.)

कृतज्ञ राष्ट्र हर साल 27 जून को सुप्रसिद्ध साहित्यकार और पत्रकार बंकिम चंद्र चटोपाध्याय को उनकी जयंती पर याद करता है। 27 जून, 1838 को बंगाल के उत्तरी चौबीस परगना जिला अंतर्गत कंठालपाड़ा नैहाटी में जन्मे बंकिम चंद्र चटोपाध्याय गीत 'वन्दे मातरम्' अजर-अमर है।यह देश का राष्ट्रगीत है।उनका पूरा जीवन स्वत्व और स्वाभिमान जागरण अभियान के लिए समर्पित रहा।उनका हर आ'ान स्वाधीनता संघर्ष का महामंत्र बना है।वन्दे मातरम्का उद्घोष सशस्त्र क्रान्तिकारियों और अहिसंक आंदोलनकारियों ने किया है। कहीं-कहीं उनकी जन्म तिथि 26 जून भी लिखी है।

उनके पिता यादवचन्द्र चटोपाध्याय का परिवार संपन्न और सुसंस्कृत था। माता दुर्गा देवी भी परंपराओं के प्रति पूर्णतयः समर्पित थीं। राष्ट्र स्वाभिमान और सांस्कृतिक बोध उनके संस्कारों में था। उनकी शिक्षा हुगली कॉलेज और प्रेसीडेंसी कॉलेज में हुई। देश में जब 1857 की क्रान्ति आरंभ हुई तब वे महाविद्यालयीन छात्र थे। बीए कर रहे थे। अंग्रेजों ने क्रान्ति के दमन के लिए जो सामूहिक नरसंहार किए उनके समाचार प्रतिदिन आ रहे थे। उन्होंने क्रान्ति के कारणों को भी समझा और विफलता को भी।

इस पूरी अवधि में वे मानसिक रूप से उद्वेलित तो हुए पर अपनी पढ़ाई से विचलित नहीं हुए। 1857 में ही प्रेसीडेंसी कालेज से बीए की उपाधि लेने वाले वे पहले भारतीय विद्यार्थी थे। इस कारण तत्कालीन अंग्रेज सरकार ने उनका स्वागत किया और शिक्षा पूरी होने के साथ उनकी नियुक्ति डिप्टी मजिस्ट्रेट पद पर हो गई। कुछ समय वे बंगाल सरकार में सचिव पद पर भी रहे। लेकिन उन्होंने नौकरी छोड़ दी। 1869 में वकालत पास की। और इसके साथ ही उन्होंने वैचारिक रूप से समाज जागरण का अभियान आरंभ किया। वे अतीत में हुए संघर्ष से जितने प्रभावित थे उतने ही कुछ लोगों द्वारा परिस्थितियों के समक्ष झुक कर अपना स्वत्व और स्वाभिमान खो देने की मानसिकता से भी आहत थे। इसलिए उन्होंने स्वत्व जागरण और संगठन पर जोर देने के संकल्प के साथ अपनी रचना यात्रा आरंभ की।

उनकी पहली प्रकाशित रचना राजमोहन्स वाइफ थी। यह अंग्रेजी में थी।इसमें परिस्थितियों की विवशता को बहुत सावधानी से प्रस्तुत किया। बांग्ला में उनकी पहली रचना 1865 में 'दुर्गेशनंदिनी' प्रकाशित हुई। यह एक आध्यात्मिक रचना है पर इसके माध्यम से समाज की आंतरिक शक्ति से ठीक उसी प्रकार परिचित कराया गया जैसा मुगलकाल में बाबा तुलसी दास ने रामचरित मानस द्वारा जन जागरण करने का प्रयास किया था।इसी शृंखला में 1866 में उपन्यास कपालकुंडला प्रकाशित हुआ और 1872 में मासिक पत्रिका बंगदर्शन का भी प्रकाशन किया।इस पत्रिका के माध्यम से वे एक कुशल पत्रकार के रूप में सामने आए।

अपनी इस पत्रिका में उन्होंने अपने विषवृक्ष उपन्यास को भी धारावाहिक रूप से प्रकाशित किया।जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है कि इस उपन्यास में समाज के उस स्वभाव और

अदूरदर्शिता का प्रतीकात्मक वर्णन था जो भारत राष्ट्र के पतन का कारण बना। इसी प्रकार अपनी कृष्णकांतेर रचना में उन्होंने अंग्रेजी शासकों पर तीखे व्यंग्य किए। बंगाल के कांतल गांव में 07 नवम्बर, 1876 को गीत 'वन्दे मातरम्' की रचना की।जो 1882 में कालजयी उपन्यास 'आनंद मठ' पूर्ण हुआ।वन्दे मातरम्इस उपन्यास का प्रमुख अंश है। मूलरूप से वन्दे मातरम्के प्रारंभिक दो पद संस्कृत में थे, जबकि शेष गीत बांग्ला भाषा में था। वंदे मातरम् का अंग्रेजी अनुवाद सबसे पहले अरविंद घोष ने किया।

यूं तो उनकी प्रत्येक रचना भारतीय समाज को जाग्रत करने वाली है पर फिर भी 'आनंदमठ' उपन्यास और इसके अंतर्गत गीत वन्दे मातरम् संघर्ष और बलिदान का महामंत्र बना। इस उपन्यास की भूमिका बंगाल में हुए संन्यासी विद्रोह से पड़ गई थी।बंगाल में संतों और संन्यासियों ने 1873 में समाज जागरण का कार्य किया था ताकि अंग्रेजी कुचक्र से राष्ट्र संस्कृति और परंपराओ की रक्षा हो सके। संतों के इस अभियान को संन्यासी विद्रोह का नाम दिया गया जिसे अंग्रेजों ने बहुत क्रूरता से दमन किया था। आनंदमठ में संन्यासियों द्वारा की गई क्रान्ति के प्रयास का वर्णन था। जब उपन्यास के रूप में यह विवरण सामने आया तो मानो पूरे समाज का राष्ट्रबोध जाग्रत हो गया। समाज अंग्रेजों के विरुद्ध एकजुट सामने आने लगा। तब बंगाल के सामाजिक और सार्वजनिक आयोजन में वन्दे मातरम्का घोष मानो एक परंपरा ही बन गई थी।

बंकिम बाबू का अंतिम उपन्यास 1886 में सीताराम आया। इसमें सल्तनकाल के वातावरण और उसके प्रतिरोध को दशार्या गया था। उनके अन्य उपन्यासों में मृणालिनी, इंदिरा, राधारानी, कृष्णकांतेर, देवी चौधरानी और मोचीराम जीवनचरित शामिल है। उन्होंने धर्म, सामाजिक और समसामायिक विषयों पर आधारित कई निबंध और कविताएं भी लिखीं।

यह उनके रचना संसार से समाज में उत्पन्न जाग्रति का ही परिणाम था कि उस कालखंड में हुए प्रत्येक आन्दोलन के प्रतिभागी उनसे प्रेरित रहे। उनके चिंतन और जीवन में भारत राष्ट्र की संस्कृति और परंपरा का आह्वान था। वे स्वतंत्रता के आदर्शों के प्रति गहराई से प्रेरित थे।

पराधीनता के काल में राष्ट्रभाव जाग्रत करने की दिशा में बंकिम बाबू का योगदान सबसे बड़ा है।उन्होंने एक आदर्श सत्ता की स्थापना के लिए आवश्यक तत्वों को समाज के सामने लाने के लिए निबंध 'कृष्णचरित्र' प्रकाशित किया। जब उनका गीत वन्दे मातरम् पहली बार 1876 में बंगदर्शन समाचार पत्र में प्रकाशित हुआ, तो उससे मानो पूरे देश में वैचारिक आवेग उत्पन्न हुआ। उन्होंने सनातन परंपराओं और राष्ट्र के लिए अनिवार्य आदर्शों के बीच एक अद्भुत पूरकता और सामंजस्य स्थापित किया।

वहीं हिन्दुओं के बीच फैली विभ्रम की स्थिति के बारे में मानो एक प्रकार से शोक व्यक्त किया था। उन्होंने इस बात पर गहरा क्षोभ व्यक्त किया और झकझोरने का प्रयास किया। उनके इन शब्दों में "हिन्दू समाज कुमार संभव को छोड़कर स्वाइनबर्न पढ़ता है, गीता को छोड़ कर मिल को पढ़ता है।उड़ीसा की पत्थर कला को छोड़ देते हैं और साहिबों की चीनी गुड़िया को देखते हैं।" कितनी व्यथा और स्वत्व का आ'ान है इसे इन्ही शब्दों में छुपे संदेश से सहज समझा जा सकता है।

उन्होंने अपनी रचना 'धर्मशास्त्र' में देशभक्ति को सभी धर्मों से ऊपर रखा। 'लोक रहस्य' में उदारवादियों के भीख मांगने पर व्यंग्य किया और देश को अपने पैरों पर खड़ा होने पर जोर दिया। निबंध 'अमर दुर्गोत्सव' में उन्होंने विधवा विवाह, महिलाओं की स्वतंत्रता के बारे में बात की और अंधी अंग्रेजी नकल का जोरदार विरोध किया। उन्होंने अपनी मातृभूमि को अपनी मां के रूप में प्रस्तुत किया।

इस प्रकार उनका पूरा जीवन भारत राष्ट्र और उसकी संस्कृति के प्रति समाज को जाग्रत करने के लिये समर्पित रहा। स्वत्व, स्वाभिमान और राष्ट्र संस्कृति जागरण का यह महानायक 08 अप्रैल 1894 को संसार से विदा हो गया। संसार से यह विदाई केवल शरीर की थी। वे और उनका व्यक्तित्व आज भी प्रत्येक भारतीय के मन में विराजे हैं।

(लेखक, वरिष्ठ पत्रकार हैं।)

भारत का विनिर्माण क्षेत्र में कमजोर होना, ये तर्क कांग्रेस का व्यर्थ है

डॉ. मयंक चतुर्वेदी (हि.स.)

कांग्रेस ने इन दिनों अपने युवराज राहुल गांधी के जरिए लगातार केंद्र सरकार की आलोचना के लिए जो रास्ता चुना है, वह सही नजर नहीं आ रहा। क्योंकि उनके द्वारा उठाया गया ये मुद्दा सत्य से बहुत दूर दिखता है। उनका तर्क है कि मोबाइल फोन एवं विनिर्माण क्षेत्र के सभी उत्पाद भारत में असेंबल किए जा रहे हैं और उनके पुर्जे विदेश से आयात किए जा रहे। वे केंद्र सरकार को यह कहकर घेरते दिखे कि मेक इन इंडिया ने फैक्टरी बूम का वादा किया था। तो फिर विनिर्माण रिकॉर्ड निचले स्तर पर क्यों है, युवा बेरोजगारी रिकॉर्ड ऊंचाई पर क्यों है और चीन से आयात दोगुने से अधिक क्यों हो गया है ? राहुल यह भी समझाते हैं कि 'हमें दूसरों के लिए बाजार बनना बंद करना होगा। अगर हम यहां निर्माण नहीं करते हैं, तो हम उन लोगों से खरीदते रहेंगे जो निर्माण करते हैं।' किंतु क्या राहुल यहां जो बता रहे हैं, वह उतना ही सच है, जैसा कि कहा जा रहा है ? भारत क्या विनिर्माण क्षेत्र में लगातार कमजोर हुआ है ? या फिर जैसा कांग्रेस कह रही है कि हम दूसरों के लिए बाजार बन गए हैं, वह पूरा सच है ?

वस्तुतः जैसा कि अर्थ, वाणिज्य और उद्योग जगत के जानकार जानते हैं, बाजार में हर कुछ एक दूसरे पर निर्भर है। यह हो सकता है कि कभी कोई आगे तो कभी कोई कुछ या अधिक पीछे दिखाई दे, लेकिन हमेशा परिणाम सकारात्मक या नकारात्मक ही होंगे, यह बाजार में कभी स्थायी रूप से होता नहीं है। जहां तक भारत के विनिर्माण क्षेत्र में कार्य करने एवं विकास का प्रश्न है तो आंकड़े जो कहते हैं, वह ऐसे वक्त में जब दुनिया के तमाम देशों के बीच जहां परसपर युद्ध का साया मंडरा रहा है तो कहीं सीधे युद्ध जैसी स्थितियां हैं, फिर भी बहुत आशावादी और उत्साहवर्धक कहे जा सकते हैं।

ये कुछ आंकड़े हैं, जिन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। 2014 में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में जब केंद्र में सरकार बनी तब देश की अर्थव्यवस्था 11वें नंबर पर थी। ग्यारह साल में अर्थव्यवस्था को ग्यारहवें नंबर से चौथे नंबर पर आ गई। आज भारत दुनिया की टॉप पांच अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हो चुका है। यह लगातार चौथा वर्ष है जब भारत सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था रहा है। प्रति व्यक्ति आय में 67 प्रतिशत, विदेशी मुद्रा भंडार में 135 प्रतिशत, निर्यात में 825 अरब अमेरिकी डॉलर का रिकॉर्ड स्तर, एफडीआई में 106 प्रतिशत, टैक्सपेयर्स की संख्या में 127 प्रतिशत और डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन में 238 प्रतिशत की वृद्धि भारत के संदर्भ में आज दिखाई देती है। पिछले 11 वर्षों में 27 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से बाहर आए हैं। विचार करें; क्या यह सरकार के बिना सही प्रयास वगैर संभव होता ?

यह तो सभी जानते हैं कि सरकारी नौकरियां कुल जनसंख्या में अधिकतम तीन प्रतिशत लोगों को ही दी जा सकती है, ऐसे में शेष 97 प्रतिशत के लिए रोजगार, श्रम एवं कृषि ही वह उपाय है, जहां से वे अपने लिए आय प्राप्त कर सकते हैं। स्वभाविक तौर पर इसमें सबसे बड़ा हिस्सा वर्तमान में उद्योग-धंधे से होनेवाली आय का है। यदि देश में विनिर्माण क्षेत्र कमजोर होता तब फिर 27 करोड़ लोगों का गरीबी की रेखा से बाहर निकलना कभी संभव ही नहीं होता! यानी भारत के विनिर्माण क्षेत्र में अच्छा कार्य हो रहा है और रोजगार के तमाम अवसर सुगम है, इसलिए देश में गरीबी कम हो रही है, लखपति के बाद अब करोड़पति और अरबपतियों की संख्या में इजाफा हो रहा है।

इसी जून माह के प्रारंभ में भारत के मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई के संबंध में रिपोर्ट देखने को मिली। जो कहती है कि मई में भारत का मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई मई में 57.6 रहा। मजबूत मांग और रिकॉर्ड हायरिंग दर्ज की जा रही है। हालांकि मई में पीएमआई अप्रैल के 58.2 से मामूली रूप से कम रहा है, फिर भी ध्यान देने योग्य है कि पीएमआई 50 से ऊपर होता है तो यह वृद्धि को दिखाता है। यानी भारत वर्तमान में वृद्धि करते हुए साफ दिखाई देता है। स्वभाविक है कि यह मजबूत वृद्धि घरेलू और विदेशी मांग के साथ-साथ सफल मार्केटिंग प्रयासों के कारण हुई है, जिसने निर्यात ऑर्डर को पिछले तीन वर्षों के सबसे उच्च स्तर पर पहुंचा दिया। एचएसबीसी की ओर से किए गए पीएमआई सर्वेक्षण में देश भर की फर्मों ने एशिया, यूरोप, पश्चिम एशिया और अमेरिका के प्रमुख बाजारों से बढ़ती रुचि के बारे में भी बताया है।

वाणिज्य मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, वैश्विक बाजारों में आर्थिक अनिश्चितताओं के बावजूद, भारत का माल और सेवा निर्यात वित्त वर्ष 2025 में रिकॉर्ड 820 बिलियन डॉलर को पार कर गया है, जो पिछले वित्त वर्ष के 778 बिलियन डॉलर के इसी आंकड़े से करीब 6 प्रतिशत की वृद्धि दशार्ता है। देश की जीडीपी पिछली तिमाही में एक साल पहले की तुलना में 7.4% बढ़ी, जो 2024 की शुरूआत के बाद से इसकी सबसे तेज गति है। एसएंडपी ग्लोबल द्वारा संकलित एचएसबीसी इंडिया मैन्युफैक्चरिंग परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स (पीएमआई) तो यही दर्शा रही है कि विनिर्माण नौकरियों में सबसे तेज वृद्धि देखी गई, जिसमें कंपनियों ने अस्थायी श्रमिकों की तुलना में स्थायी कर्मचारियों को प्राथमिकता दी है।

जहां तक विशेष रूप से मोबाइल फोन उत्पादक का विषय है तो इसमें आज भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है, पिछले 11 सालों के दौरान 2014 में दो विनिर्माण इकाइयां से बढ़कर आज इनकी संख्या 300 से अधिक हो गई है। मोबाइल फोन का निर्यात 2014-15 में 1,566 करोड़ रुपये से बढ़कर 2023-24 में 1.2 लाख करोड़ रुपये हो गया है, जो 77 गुना वृद्धि है। यह भी एक तथ्य है कि भारत में बिकने वाले 99.2 प्रतिशत मोबाइल फोन अब भारत में निर्मित होते हैं, जबकि 2014-15 में यह आंकड़ा मात्र 26 प्रतिशत था। पीएलआई योजना से 10,905 करोड़ रुपये का संचयी निवेश और 7.15 लाख करोड़ रुपये का उत्पादन हुआ है।

अकेले इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए पीएलआई योजना के तहत 1,39,670 प्रत्यक्ष नौकरियां सृजित की गई हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन मूल्य वित्त वर्ष 2014 में 18,900 करोड़ रुपये से बढ़कर वित्त वर्ष 2024 में 4.22 लाख करोड़ रुपये हो गया। वित्त वर्ष 2024-25 में इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात 38 बिलियन अमेरिकी डॉलर को पार कर गया, जो साल-दर-साल 32 प्रतिशत की वृद्धि है। 2023-24 में 1.8 लाख नई कंपनियां पंजीकृत की गईं, जो पिछले वर्ष की तुलना में 16 प्रतिशत की वृद्धि को दशार्ती हैं, जो निरंतर औद्योगिक और उद्यमशीलता विकास का संकेत है।

आप सोचें ये जो नई कंपनियों की संख्या सामने आई है, यह भारत में क्या कर रही हैं, रोजगार का सृजन, माल का निर्माण और उसकी देशी एवं विदेशी बाजार में उसकी खपत। सरकार ने 1.52 लाख करोड़ रुपये की सेमीकंडक्टर परियोजनाओं को मंजूरी दी है, जिससे 2026 तक इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन 300 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है। इसलिए कांग्रेस या राहुल गांधी जो आज भारत के विनिर्माण क्षेत्र को कमजोर होना बता रहे हैं, उनका यह कहना वास्तव में साक्ष्यों और आंकड़ों के आधार पर सही नहीं है। यह तो देश की जनता को गुमराह करने जैसा है, ताकि वर्तमान सत्ता के प्रति आमजन का विश्वास कमतर किया जा सके।

(लेखक, हिन्दुस्थान समाचार से संबद्ध हैं।)

आपातकालः लोकतंत्र का काला अध्याय

आंतरिक अशांति का बहाना बनाकर 25 जून 1975 की आधी रात को देश पर थोपे गए 'आपातकाल' को 50 वर्ष पूरे हो रहे हैं। भारत की जनता ने तब तानाशाही के विरुद्ध स्वतंत्रता की एक और लड़ाई लड़ी थी। इस बार लड़ाई अपने ही दिग्भ्रमित सत्तालोलुप नेताओं से थी, जिसमें देश एक बार फिर विजेता बनकर उभरा था। पिछले कुछ वर्षों से कुछ विपक्षी नेता संविधान की प्रति हाथ में लिए भाषण देते दिखाई देते रहे हैं। बात-बात में संविधान की दुहाई देने का क्रम चल रहा है। भारत के स्वस्थ और मजबूत लोकतांत्रिक वातावरण में भी 'लोकतंत्र व संविधान बचाने' के लिए सभाओं के प्रहसन चल रहे हैं। आपातकाल के 50 वर्ष पूरे होने पर यह अवसर है जब मुड़कर इतिहास को फिर से देखने की आवश्यकता है।

आपातकाल का निर्णय किसी युद्ध या आंतरिक विद्रोह के कारण नहीं बल्कि एक प्रधानमंत्री के लोकसभा चुनाव रद्द होने और अपनी सत्ता बचाने की हताशा में लिया गया राष्ट्र विरोधी निर्णय था। कांग्रेस पार्टी ने आपातकाल के इस क्रूरकाल में न केवल संवैधानिक ढांचे को कुचला बल्कि प्रेस की स्वतंत्रता, न्यायपालिका की निष्पक्षता और नागरिकों के मौलिक अधिकारों को भी भंग किया।

1971 के आम चुनावों में इंदिरा गांधी ने रायबरेली से जीत तो हासिल की, लेकिन उनके निकटतम उमॅमीदवार राजनारायण ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर कर चुनाव में भ्रष्टाचार और सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग के आरोप लगाए। इधर देश की अर्थव्यवस्था खराब स्थिति में थी। आर्थिक विकास दर केवल 1.2% थी। देश का विदेशी मुद्रा भंडार मात्र 1.3 बिलियन डॉलर था (आज 640 बिलियन है)। महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार चरम पर था। 50% से ज्यादा जनता गरीबी रेखा के नीचे थी। बिहार और गुजरात में छात्रों के नेतृत्व में नवनिर्माण आंदोलन चल रहा था। 8 मई 1974 को जॉर्ज फर्नांडिस के नेतृत्व में देशव्यापी रेल हड़ताल हो चुकी थी। बिहार, गुजरात में राष्ट्रपति शासन के बाद कांग्रेस चुनाव हार चुकी थी। इस सबसे कांग्रेस की केंद्र सरकार परेशान हो चुकी थी।

12 जून 1975 को न्यायमूर्ति जगमोहनलाल सिन्हा ने अपने निर्णय में इंदिरा गांधी की जीत को अवैध करार दिया और 6 साल तक चुनाव लड़ने से प्रतिबंधित कर दिया। इस ऐतिहासिक निर्णय के बाद इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री नहीं रह सकती थीं। उनकी कुर्सी को गंभीर राजनीतिक संकट खड़ा हो गया। इससे घबराकर इंदिरा गांधी ने आंतरिक अशांति का बहाना बनाकर मंत्रिपरिषद् की अनुशंसा के बगैर ही राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद से अनुच्छेद 352 के तहत देश में आपातकाल लगाने की सिफारिश की, जिसे राष्ट्रपति ने 25 जून 1975 की आधी रात को मंजूरी दे दी।

आज संविधान की प्रतियां हाथ में लहराने का नाटक करने वालों को यह स्मरण रखना ही होगा कि आपातकाल वास्तव में भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था को कुचलने का प्रयास था। यह संविधान की हत्या की सोची-समझी रणनीति थी। इंदिरा गांधी ने 'आंतरिक अशांति' की आड़ लेकर संविधान के अनुच्छेद 352 का दुरुपयोग किया जबकि न तो उस समय बाहरी आक्रमण या युद्ध की स्थिति थी, न विद्रोह ही हुआ था। आपातकाल किसी राष्ट्रीय संकट का परिणाम नहीं था, बल्कि

हितानंद शर्मा (हि.स.)

यह एक डरी हुई प्रधानमंत्री की सत्ता बचाने की जिद थी।

संविधान की शपथ लेकर इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री बनी थीं, किन्तु उसी संविधान की आत्मा को कुचलते हुए एक झटके में उन्होंने लोकतंत्र को तानाशाही में बदलकर रख दिया और पूरी शासन व्यवस्था को कठपुतली की तरह उपयोग किया। कांग्रेस सरकार ने विधायिका और न्यायपालिका को बंधक बनाकर सत्ता के आगे घुटने टेकने को विवश कर दिया था।प्रेस की स्वतंत्रता पर कुठाराघात किया गया। बड़े-बड़े समाचार पत्र संस्थानों की बिजली काट दी गई। समाचार पत्रों के प्रकाशन पर सेंसरशिप लगा दी गई और पत्रकारों को जेल में डाल दिया गया।

21 महीने के आपातकाल का क्रूर समय नागरिकों पर हुए अत्याचारों की दारुण गाथा है।जहां विरोध में स्वर उठे वहां क्रूरता के साथ दमन किया गया। लोकतंत्र में आस्था रखने वाली हर आवाज को दबाया गया। मीसा जैसे काले कानून में लगभग एक लाख लोगों को बिना किसी सुनवाई के जेलों में डाला गया। जयप्रकाश नारायण, अटलबिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, राजनाथ सिंह जैसे अनेक वरिष्ठ विपक्षी नेताओं, सामाजिक कार्यकताओं, पत्रकारों यहां तक कि छात्रों तक को जेल में बंद करा दिया। जेलों में अमानवीय यातनाएं दी गईं। बीमार होने पर दवाएं तक नहीं दी गईं। महिला बंदियों के साथ असम्मानजनक और अमानवीय व्यवहार किया गया।

लोकतंत्र की रक्षा में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की भूमिका और संघर्ष अत्यंत महत्वपूर्ण है। डरी हुई सरकार ने आपातकाल लगाने के पांच दिन बाद ही सरसंघचालक बालासाहब देवरस को गिरफ्तार कर लिया। जयप्रकाश नारायण ने अपनी गिरफ्तारी से पहले लोक संघर्ष समिति का नेतृत्व संघ के पूर्णकालिक नानाजी देशमुख को सौंप दिया था, बाद में उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया। आरएसएस, जनसंघ, एवीबीपी और कई अन्य संगठनों पर प्रतिबंध लगाकर कांग्रेस द्वारा कठोर दमन चक्र चलाया गया। एक लाख स्वयंसेवक एवं विचार परिचार के कार्यकताओं ने सत्याग्रह किया। 25 हजार कार्यकताओं को मीसा में बंदी बना लिया गया। 100 कार्यकर्ता इस संघर्ष में बलिदान हो गए।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी उस समय साधारण कार्यकर्ता हुआ करते थे और उन्हीं की तरह लाखों स्वयंसेवकों ने आपातकाल विरोधी आंदोलन जारी रखा। रातों-रात रेलों में आपातकाल विरोधी पर्चे बांटे, मीसाबंदियों के परिवारों की देखरेख की, भूमिगत रहते हुए आंदोलन की गति बनाए रखी और कांग्रेस की सच्चाई घर-घर तक पहुंचाई। अंततः जनाक्रोश और नागरिकों के बढ़ते दबाव के कारण जनवरी 1977 में चुनावों की घोषणा हुई और मार्च 1977 में हुए चुनावोंमें जनता पार्टी को जबरदस्त समर्थन मिला। इंदिरा गांधी स्वयं रायबरेली से चुनाव हार गईं। लोकतंत्र फिर प्रतिष्ठित हुआ।

'इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा' जैसे नारों से आपातकाल के समय में कांग्रेस ने देश को व्यक्ति पूजा और परिवारवाद की प्रयोगशाला बना दिया। बिना किसी संवैधानिक दायित्व के संजय गांधी देश की नीतियों पर निर्णय ले रहे थे। वह आपातकाल में सत्ता का वास्तविक केंद्र थे। देश के नागरिकों पर आपातकाल थोपने वाली कांग्रेस आज भी इसी परिवारवाद के सीमित सांचे में सिमटकर रह गई है। इंदिरा गांधी की तानाशाही का सबसे भयावह चेहरा यह था कि उन्होंने अपने पुत्र के माध्यम से सत्ता को वंशवाद की जकड़ में पूरी तरह से कैद कर लिया था। सत्ता लोलुपता में कांग्रेस ने लोकसभा का कार्यकाल 5 से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया।

आपातकाल इतिहास की एक राजनीतिक घटना मात्र नहीं हैं, बल्कि उस दूषित मानसिकता का प्रमाण है, जो संविधान और लोकतंत्र को केवल अपनी सत्ता पाने और बचाए रखने के लिए इस्तेमाल करती है। लोकतंत्र के साथ विश्वासघात करने के बाद भी कांग्रेस ने न तो कभी माफी मांगी और न ही कोई पश्चाताप ही प्रकट किया।

(लेखक भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के प्रदेश संगठन महामंत्री हैं)

मुख्यमंत्री के नेतृत्व में पंजाब कैबिनेट का ऐतिहासिक फैसला, पंजाब के उद्योगों को दी बड़ी राहत

औद्योगिक प्लॉटों को अस्पतालों, होटलों, औद्योगिक पार्कों और अन्य उद्देश्यों के लिए उपयोग की अनुमति देने के उद्देश्य से उठाया कदम

संवाददाता
चंडीगढ़

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब कैबिनेट ने औद्योगिक प्लॉटों को अस्पतालों, होटलों, औद्योगिक पार्कों और अन्य स्वीकृत मदों के लिए उपयोग की अनुमति देने वाली पंजाब की हस्तांतरण नीति में महत्वपूर्ण संशोधनों को मंजूरी दे दी। इस संबंध में फैसला आज यहां मुख्यमंत्री के सरकारी आवास पर हुई मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया।

मुख्यमंत्री कार्यालय के प्रवक्ता ने बताया कि पहले हस्तांतरण नीति 2008, 2016 और 2021 में लाई गई थी। हालांकि, औद्योगिक संगठनों ने 2021 में लाई गई नीति की कुछ प्रतिबंधात्मक शर्तों पर आपत्ति जताई थी। इसके जवाब में एक कमेटी ने उद्यमियों की मांगों की समीक्षा की और फ्री होल्ड प्लॉटों पर लागू होने वाले परिवर्तनों का प्रस्ताव दिया। संशोधित नीति के अनुसार, औद्योगिक प्लॉट की आरक्षित कीमत का 12.5 प्रतिशत हस्तांतरण शुल्क लागू होगा।

कैबिनेट ने विशेष रूप से पी.एस.आई.ई.सी. के प्रबंधन वाले लीजहोल्ड औद्योगिक प्लॉटों और शेड्स को फ्री होल्ड में बदलने की नीति को भी मंजूरी दे दी। ये प्लॉट और शेड मूल रूप से लीजहोल्ड आधार पर आवंटित किए गए थे, जिनमें परिवर्तन संबंधी जटिल धाराएँ शामिल थीं, जिसके कारण संपत्ति के लेन-देन में कठिनाइयां आ रही थी। इस नई नीति का उद्देश्य औद्योगिक प्लॉटों के प्रबंधन को सुचारू करना, कारोबार में सुगमता बढ़ाना, आवंटियों के बीच मुकदमेबाजी और अनिश्चितता को कम करना है। इसके अलावा, इस हस्तांतरण से राज्य के लिए अतिरिक्त राजस्व उत्पन्न होने की उम्मीद है।

कैबिनेट ने एम.एस.एम.ई. डेवलपमेंट एक्ट, 2006 के तहत एम.एस.ई. फैसिलिटेशन काउंसिल नियम-2021 में संशोधनों को मंजूरी दे दी। वर्तमान में जिला स्तर पर माइक्रो और स्मॉल इंटरप्राइजेज फैसिलिटेशन काउंसिल संबंधित डिप्टी कमिश्नरों के नेतृत्व में काम कर रही हैं। हालांकि, इस एक्ट के तहत अवार्ड्स से संबंधित भुगतानों में देरी हो रही है। भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के आधार पर अब एक ऐसा ढांचा बनाया जाएगा, जिससे पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट, 1887 के तहत भू-राजस्व के बकाया के रूप में ऐसे अवार्ड्स की वसूली जल्द हो सके।

कैबिनेट ने पंजाब जल संसाधन विभाग में जूनियर इंजीनियर्स (ग्रुप-बी) से संबंधित सेवा नियमों में संशोधन को मंजूरी दे दी। इसके तहत जे.ई. की 15 प्रतिशत रिक्तियां पदोन्नति के लिए आरक्षित हैं, जिनमें से 10 प्रतिशत रिक्तियां जूनियर ड्राफ्ट्समैन, सर्वेयरों, वर्क मिस्त्रियों, अर्थ वर्क मिस्त्रियों और अन्य से भरी जाएंगी।

पंजाब सरकार का संकल्प - शहरी निवासियों को विश्वस्तरीय नागरिक सुविधाएं प्रदान करना: डॉ. रवजोत सिंह

संवाददाता
चंडीगढ़

- कहा, जिला एस.ए.एस. नगर (मोहाली) को स्वच्छ और सुंदर बनाया जाएगा

मुख्यमंत्री स भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार शहरी निवासियों को विश्व स्तरीय सुविधाएं प्रदान करने के लिए दृढ़ संकल्पित है। इसी दिशा में पंजाब के शहरों के सौंदर्यीकरण पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। यह विचार आज पंजाब के स्थानीय निकाय मंत्री डॉ. रवजोत सिंह ने यहां वरिष्ठ विभागीय अधिकारियों और जिला एस.ए.एस. नगर (मोहाली) के अधिकारियों तथा कार्यकारी अधिकारियों के साथ बैठक के दौरान व्यक्त किए। उन्होंने पंजाब के शहरों को स्वच्छ और सुंदर बनाने का संकल्प लेते हुए कहा कि एस.ए.एस. नगर (मोहाली) की शहरी स्थानीय इकाइयों – नगर परिषद खरड़, डेराबस्सी, राजपुरा, बनूड, जीरकपुर, लालडू, नवा गांव, घडूआं और कुराली को स्वच्छ और सुंदर बनाया जाएगा।

विभागीय अधिकारियों को शहरी विकास के कार्यों को योजनाबद्ध ढंग से पूरा करने के निर्देश देते हुए मंत्री ने कहा कि मोहाली की शहरी स्थानीय इकाइयों में लैंडस्केपिंग, सड़कों का विकास, मोहाली शहर के अधीन आने वाले गांवों का सौंदर्यीकरण, शहरी नागरिकों की सुविधा संबंधी कार्य, और शहरों में बनाई जा रही इमारतों का निर्माण सुरक्षा मानकों के अनुरूप सुनिश्चित किया जाएगा।

डॉ. रवजोत सिंह ने प्रगति अधीन विकास कार्यों की विस्तृत जानकारी लेने के बाद कहा कि ये विकास कार्य निर्धारित समय-सीमा में पूरे किए जाएं। उन्होंने कहा कि शहरी नागरिक सुविधाएं पंजाब सरकार की प्राथमिकता हैं और इस संबंध में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

इस बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री तेजवीर सिंह, सी.ई.ओ. पीएमआईडीसी श्रीमती दीप्ति उप्पल, संयुक्त निदेशक स्थानीय निकाय श्री जगदीप सहगल, नगर निगम मोहाली के आयुक्त श्री परमिंदर पाल सिंह, ए.डी.सी. शहरी विकास स अनमोल सिंह धालीवाल, चीफ इंजीनियर श्री नरेश बत्ता तथा नगर परिषद खरड़, डेराबस्सी, राजपुरा, बनूर, जीरकपुर, लालडू, नवा गांव, घडूआं और कुराली के कार्यकारी अधिकारी उपस्थित थे।

भगवंत मान सरकार और अनन्या बिरला फाउंडेशन ने नशे के खिलाफ जंग में तेजी लाने के लिए मिलाया हाथ

संवाददाता
चंडीगढ़

मुख्य मंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार ने आज नशाखोरी और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय दिवस के अवसर पर नशे के खिलाफ लड़ाई को तेज करने के उद्देश्य से एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए डेटा इंटेलिजेंस और तकनीकी सहायता इकाई स्थापित करने के लिए एक समझौता किया है। यह समझौता पंजाब सरकार और डॉ. बी.आर. अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, मोहाली, तथा विद्यासागर इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ, अमृतसर के बीच अनन्या बिरला फाउंडेशन के सहयोग से किया गया है।

इस अवसर पर सभा को संबोधित करते हुए मुख्य मंत्री ने कहा कि यह पहल पंजाब सरकार द्वारा नशे के खिलाफ चल रही जंग का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि डेटा इंटेलिजेंस और तकनीकी सहायता इकाई स्थापित करने की यह अनूठी पहल राज्य में नशे के खतरे से निपटने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि यह समझौता पंजाब सरकार द्वारा नशे की रोकथाम और पुनर्वास के लिए किए जा रहे व्यापक प्रयासों का हिस्सा है। भगवंत सिंह मान ने कहा कि नशे के खिलाफ युद्ध ने राज्य में नशे की आपूर्ति श्रृंखला को तोड़ दिया है और इस आपूर्ति के खत्म होने के साथ नशे से प्रभावित व्यक्तियों का पुनर्वास सुनिश्चित करना अत्यंत आवश्यक हो जाता है। मुख्य मंत्री ने कहा कि नशा पीड़ितों को नशे के जाल से बाहर निकालने और उन्हें सम्मानजनक जीवन जीने में सहायता करने के लिए सरकार न केवल विभिन्न सुविधाओं से लैस पुनर्वास केंद्र स्थापित कर रही है, बल्कि नशे की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए चिकित्सा देखभाल, शिक्षा और रोजगार के अवसर भी प्रदान कर रही है। उन्होंने कहा कि नशा विरोधी अभियान के दूसरे चरण में डेटा इंटेलिजेंस और तकनीकी सहायता इकाई स्थापित करके मनो-सामाजिक देखभाल का एक व्यापक मॉडल लागू किया जा रहा है। भगवंत सिंह मान ने कहा कि यह इकाई मेडिकल अधिकारियों, मनोवैज्ञानिकों, पुलिस कर्मियों और फ्रंटलाइन स्वास्थ्य कर्मियों की क्षमता बढ़ाकर नशा विरोधी अभियान में तकनीकी सहायता प्रदान करेगी। यह इकाई पुनर्वास से संबंधित चुनौतियों से निपटने के लिए प्रभावी रणनीतियां विकसित करने, ओ.ओ.ए.टी. (आउटपेशेंट ओपियोइड असिस्टेड ट्रीटमेंट) क्लीनिकों की सुचारू कार्यप्रणाली सुनिश्चित करने और आम लोगों तक आसान पहुंच के प्रयासों को मजबूत करने पर भी ध्यान केंद्रित करेगी।

रोष प्रदर्शनों पर प्रतिबंध के इस लोकतंत्र विरोधी फैसले को वापस लिया जाए

संवाददाता
चंडीगढ़

- लोकसभा सदस्य मीत हेयर ने उप-राष्ट्रपति को लिखा पत्र
- इस तानाशाही आदेश को मौलिक अधिकारों का घोर उल्लंघन बताया
- छात्रों से शपथ-पत्र लेना शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन के अधिकार को दबाने के बराबर

संगरूर से लोकसभा सदस्य गुरमीत सिंह मीत हेयर ने पंजाब विश्वविद्यालय में रोष प्रदर्शनों पर लगाई गई रोक को लोकतंत्र विरोधी करार देते हुए विश्वविद्यालय के कुलाधिपति और देश के उप-राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को पत्र लिखकर यह फैसला तुरंत वापस लेने की मांग की है।

मीत हेयर ने लिखा, पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ़, पंजाब की समृद्ध विरासत का प्रतीक है, जो आजादी से पहले से इस क्षेत्र की प्रमुख शैक्षणिक संस्था रही है। यह न केवल पंजाब बल्कि देश की श्रेष्ठ शिक्षा संस्थानों में से एक है। पंजाब विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों ने शिक्षा, विज्ञान, कानून, कला, संस्कृति, खेल और राजनीति सहित हर क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। पिछले कुछ समय से केंद्र सरकार द्वारा पंजाब विश्वविद्यालय से जुड़े जो तर्कहीन निर्णय लिए जा रहे हैं, वे इस शैक्षणिक संस्था की छवि को नुकसान पहुँचाने का प्रयास प्रतीत होते हैं। लोकसभा सदस्य ने पत्र में लिखा है कि पंजाब विश्वविद्यालय में छात्रों से धरना न देने और विरोध प्रदर्शन न करने का लिखित शपथ-पत्र लेना, उनके मौलिक अधिकारों पर सीधा हमला है। यह फैसला किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यह निर्णय जहां छात्रों के लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन है, वहीं यह एक तानाशाही सोच का भी प्रतीक है। हमारे संविधान में हमें विरोध प्रदर्शन करने का मौलिक अधिकार प्राप्त है और इस नए आदेश से सीधे-सीधे इन अधिकारों पर प्रहार किया गया है। उन्होंने कहा कि पिछले समय में जब-जब पंजाब विश्वविद्यालय में छात्र विरोधी फैसले लिए गए, छात्रों ने विरोध प्रदर्शन कर इन्हें वापस करवाया था। अब छात्रों को अपने इसी अधिकार से वंचित किया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा पंजाब विश्वविद्यालय के संबंध में लिए गए एकतरफा फैसलों ने इस महान शैक्षणिक केंद्र की साख को गहरी चोट पहुँचाने का प्रयास किया है। मीत हेयर ने कहा कि पंजाब विश्वविद्यालय में रोष प्रदर्शन न करने संबंधी छात्रों से लिखित शपथ-पत्र लेने का हाल ही में जारी किया गया आदेश न केवल संविधान में निहित उनके मौलिक अधिकारों को खत्म करता है, बल्कि यह लोकतंत्र और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की भावना का भी घोर उल्लंघन है।

मीत हेयर ने कहा कि एक ओर पंजाब विश्वविद्यालय काउंसिल के वार्षिक चुनावों के माध्यम से छात्रों को लोकतंत्र का पहला पाठ सिखाया जाता है, वहीं वर्तमान में लिया गया यह निर्णय इस परंपरा का सीधा विरोधाभास है। पंजाब विश्वविद्यालय ने देश की राजनीति को उच्च स्तर के नेता दिए हैं, लेकिन मौजूदा फैसले से इस शानदार परंपरा को गहरी चोट पहुँचेगी।

उन्होंने पत्र के अंत में लिखा, आप इस विश्वविद्यालय के कुलाधिपति भी हैं। इसलिए मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना है कि आप इस मामले में व्यक्तिगत रुचि लेकर इस तानाशाही फैसले को वापस करवाने की पहल करें।

मिड-डे मील स्टाफ को मिलेगा 16 लाख रुपये का बीमा कवर: हरजोत बैंस

संवाददाता
चंडीगढ़

एक और ऐतिहासिक पहल करते हुए पंजाब के स्कूल शिक्षा विभाग ने केनरा बैंक के साथ साझेदारी में प्रदेश भर के सरकारी स्कूलों में कार्यरत 44,301 मिड-डे मील कुक-कम-हेल्परों को 16 लाख रुपये का दुर्घटना बीमा कवर और अन्य लाभ प्रदान करने के लिए एक व्यापक बीमा योजना शुरू की है।

पंजाब के स्कूल शिक्षा मंत्री स हरजोत सिंह बैंस और स्कूल शिक्षा सचिव श्रीमती अनिंदिता मित्रा, आईएएस की उपस्थिति में आज यहां डायरेक्टोरेट ऑफ एलीमेंट्री एजुकेशन (मिड-डे मील) और केनरा बैंक, चंडीगढ़ के बीच एक समझौता (एमओयू) साइन किया गया। इस साझेदारी का उद्देश्य कुक-कम-हेल्परों को वित्तीय सुरक्षा और अन्य सुविधाएं प्रदान करना है।

इस बीमा योजना की प्रमुख विशेषताओं को साझा करते हुए स हरजोत सिंह बैंस ने बताया कि यह कवर व्यापक लाभ प्रदान करता है, जिसमें प्राकृतिक कारणों से मृत्यु होने पर 1 लाख रुपये का टर्म इंश्योरेंस, दुर्घटना में मृत्यु होने पर 16 लाख रुपये का बीमा कवर और हवाई दुर्घटना में मृत्यु होने पर 18 लाख रुपये का बीमा कवर शामिल है। इसके अलावा यह योजना बिना जीरो बैलेंस की शर्त के सरल बैंकिंग, खाता धारकों के लिए सुविधा और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए 10,000 रुपये तक की तत्काल ओवरड्राफ्ट सुविधा या पिछले महीने के कुल वेतन का 50 प्रतिशत तक की ओवरड्राफ्ट सुविधा भी प्रदान करती है।

स हरजोत सिंह बैंस ने कहा कि यह योजना इन कर्मचारियों के कल्याण को सुनिश्चित करेगी, ताकि वे राज्य की शिक्षा प्रणाली के समर्थन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका पर और अधिक ध्यान केंद्रित कर सकें।

गुणवत्ता नियंत्रण अभियान: खराब प्रदर्शन करने वाले 7 मुख्य कृषि अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस

संवाददाता
चंडीगढ़

पंजाब के कैबिनेट मंत्री स. गुरमीत सिंह खुड्डियां के निर्देशों पर, आज कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने गुणवत्ता नियंत्रण अभियान के लक्ष्यों को पूरा करने में विफल रहने वाले सात मुख्य कृषि अधिकारियों (सी.ए.ओ.) को कारण बताओ नोटिस (एससीएन) जारी किए हैं। यह कार्रवाई कृषि मंत्री द्वारा जवाबदेही और सुधार सुनिश्चित करने के लिए गुणवत्ता नियंत्रण अभियान में पीछे रहने वाले जिलों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई का आदेश देने के एक दिन बाद की गई है।

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के प्रशासनिक सचिव डॉ. बसंत गर्ग ने कपूरथला, बरनाला, लुधियाना, फतेहगढ़ साहिब, तरनतारन, संगरूर और होशियारपुर जिलों के मुख्य जिला कृषि अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की है। उन्हें 7 दिनों के भीतर जवाब देने का निर्देश दिया गया है, अन्यथा नियमों के अनुसार आगे सख्त कार्रवाई की जाएगी।

मुख्यमंत्री स. भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार की कर्तव्य में लापरवाही के खिलाफ जीरो-टॉलरेंस नीति को दोहराते हुए, स. गुरमीत सिंह खुड्डियां ने कहा कि कर्तव्य के प्रति लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों को दंडित किया जाएगा और उनकी जवाबदेही तय की जाएगी।

स. गुरमीत सिंह खुड्डियां ने कहा कि कृषि विभाग ने राज्य के किसानों को शोषण से बचाने के लिए कृषि से संबंधित वस्तुओं की नियमित निगरानी और जांच सुनिश्चित करने के लिए पांच फ्लाइंग स्क्वाड टीमों का गठन किया है। उन्होंने किसानों से बीज, खाद और कीटनाशकों की खरीद पर पक्का बिल लेने की भी अपील की।

उन्होंने यह भी सलाह दी कि यदि कोई डीलर बिल देने से इनकार करता है या घटिया कृषि-संबंधित वस्तुओं की आपूर्ति करता है, तो किसानों को तुरंत अपने जिले के कृषि कार्यालयों में इसकी रिपोर्ट करनी चाहिए, ताकि उसके खिलाफ भी उचित कार्रवाई की जा सके।

संक्षिप्त-समाचार

भारतीय चुनाव आयोग द्वारा 345 रजिस्टर्ड गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक पार्टियों को सूची से हटाने की प्रक्रिया शुरू

चंडीगढ़। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की अध्यक्षता में भारतीय चुनाव आयोग ने चुनाव आयुक्त डॉ. सुखबीर सिंह संधू और डॉ. विवेक जोशी के साथ मिलकर 345 रजिस्टर्ड गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक पार्टियों को सूची से हटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। ये वे पार्टियां हैं जो वर्ष 2019 से पिछले छह वर्षों के दौरान किसी भी चुनाव में भाग लेने की आवश्यक शर्त को पूरा करने में असफल रही हैं और जिनके दफ्तरों का भौतिक रूप से कोई पता नहीं लगाया जा सका है। ये 345 रजिस्टर्ड गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक पार्टियां देश के विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित हैं। आयोग के ध्यान में यह बात आई है कि वर्तमान में भारतीय चुनाव आयोग के पास रजिस्टर्ड 2800 से अधिक गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक पार्टियों में से कई पार्टियां आवश्यक शर्तों को पूरा करने में विफल रही हैं। इसी कारण भारतीय चुनाव आयोग द्वारा ऐसी पार्टियों की पहचान के लिए एक देशव्यापी अभ्यास चलाया गया, जिसके अंतर्गत अब तक 345 ऐसी रजिस्टर्ड गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक पार्टियों की पहचान की जा चुकी है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि किसी भी पार्टी को बिना कारण सूची से न हटाया जाए, संबंधित राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य चुनाव अधिकारियों को इन रजिस्टर्ड गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक पार्टियों को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके बाद इन पार्टियों को संबंधित मुख्य चुनाव अधिकारियों के समक्ष सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाएगा। किसी भी रजिस्टर्ड गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक पार्टी को सूची से हटाने का अंतिम निर्णय भारतीय चुनाव आयोग द्वारा ही लिया जाएगा। देश में राजनीतिक पार्टियां (राष्ट्रीय/राज्य/रजिस्टर्ड गैर-मान्यता प्राप्त) जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29ए के प्रावधानों के तहत भारतीय चुनाव आयोग में पंजीकृत होती हैं। इस प्रावधान के अनुसार, एक बार कोई संगठन राजनीतिक पार्टी के रूप में पंजीकृत हो जाता है तो उसे कर में छूट सहित कुछ विशेष अधिकार और लाभ प्राप्त होते हैं।

मोहिंदर भगत ने बागवानी विभाग की प्रगति की समीक्षा की, सब्सिडी वितरण पर जोर दिया

चंडीगढ़। पंजाब के बागवानी मंत्री, श्री मोहिंदर भगत ने चंडीगढ़ स्थित पंजाब सिविल सचिवालय में बागवानी विभाग के कार्यों की प्रगति की समीक्षा बैठक की। इस बैठक में उन्होंने विभाग की चल रही परियोजनाओं और विभिन्न योजनाओं की प्रगति का जायजा लिया। बैठक के दौरान, बागवानी सचिव, श्री मोहम्मद तैय्यब ने मंत्री को विभाग की विभिन्न योजनाओं और परियोजनाओं के तहत हुई प्रगति से अवगत कराया। श्री तैय्यब ने मुख्य उपलब्धियों पर भी प्रकाश डाला और जमीनी स्तर पर उनके कार्यान्वयन के बारे में जानकारी साझा की। श्री भगत ने किसानों को सब्सिडी के पारदर्शी और समय पर वितरण की आवश्यकता पर जोर दिया, ताकि वे बिना किसी देरी के सरकारी योजनाओं का अधिकतम लाभ उठा सकें। उन्होंने बागवानी से संबंधित सभी पहलों को शीघ्र पूरा करने और जमीनी स्तर पर किसानों के साथ सक्रिय रूप से जुड़ने के निर्देश भी दिए। मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार बागवानी क्षेत्र को और मजबूत करने तथा किसानों के लिए बेहतर अवसर सुनिश्चित करने हेतु लगातार काम कर रही है। उन्होंने आगे कहा कि बागवानी को बढ़ावा देना, किसानों की आय बढ़ाने और राज्य में कृषि विविधीकरण लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

सहायता

पानी और कृषि को बचाकर राज्य की समृद्ध विरासत को संरक्षित करने के लिए मांगी मदद

मुख्य मंत्री ने नीति आयोग की उच्च स्तरीय टीम के समक्ष राज्य की मांगें जोरदार ढंग से उठाईं

संवाददाता
चंडीगढ़

पंजाब के मुख्य मंत्री भगवंत सिंह मान ने आज नीति आयोग की टीम के सामने राज्य का पक्ष जोरदार ढंग से रखा और समर्थन की मांग की ताकि एक ओर पंजाब का समग्र विकास सुनिश्चित हो और दूसरी ओर इसके हितों की भी रक्षा हो।

नीति आयोग के सदस्य प्रो. रमेश चंद और प्रोग्राम डायरेक्टर संजीत सिंह के नेतृत्व वाली टीम के साथ विचार-विमर्श के दौरान मुख्य मंत्री ने कहा कि यह उपयुक्त समय है जब आयोग को पानी और कृषि से संबंधित पंजाब की समृद्ध विरासत को बचाने के लिए खुले दिल से मदद करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि राज्य की 553 किलोमीटर लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से लगती है और छह जिले अमृतसर, तरन तारन, गुरदासपुर, पठानकोट, फिरोजपुर और फाजिल्का सीमा पर स्थित हैं। भगवंत सिंह मान ने अफसोस जताया कि केंद्र सरकार द्वारा हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू-कश्मीर को विशेष रियायतें देने से पंजाब के सीमावर्ती जिलों की अर्थव्यवस्था पर बुरा असर पड़ा है।

मुख्य मंत्री ने कहा कि पंजाब के व्यापार और औद्योगिक क्षेत्र में फिर से जान फूंकने के लिए हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू-कश्मीर की तर्ज पर पंजाब के सीमावर्ती जिलों को भी सहारा देने की जरूरत है। सीमावर्ती जिलों के लिए विशेष रियायती पैकेज की मांग करते हुए, उन्होंने प्रत्येक सीमावर्ती जिले में एग्रो फूड प्रोसेसिंग जोन स्थापित करने की वकालत की, जिसमें विशेष ध्यान बासमती चावल उद्योग और लीची जैसे बागवानी उत्पादों पर दिया जाए। भगवंत सिंह ने सीमावर्ती जिलों में मौजूदा फोकल पॉइंट्स के नवीनीकरण और अमृतसर में प्रदर्शनी-कम-सम्मेलन केंद्र स्थापित करने की भी वकालत की।

मुख्य मंत्री ने एग्रो क्षेत्र के लिए पी.एल.आई. स्कीम, टेक्सटाइल क्षेत्र के लिए कर रियायतें, उद्योग के लिए परिवहन सब्सिडी, और सीमावर्ती जिलों के लिए रियायती ब्याज दरों पर ऋण और कार्यशील पूंजी की भी मांग की। उन्होंने अंतरराष्ट्रीय सीमा पर कांटेदार तारों के बीच की जमीन के मालिकों के लिए मुआवजे में वृद्धि की मांग करते हुए कहा कि किसानों की 17,000 एकड़ से अधिक जमीन कांटेदार तारों के पार है। भगवंत सिंह मान ने कहा कि वर्तमान में किसानों को प्रति एकड़ प्रति वर्ष 10,000 रुपए मुआवजा दिया जाता है, जिसे बढ़ाकर 30,000 रुपए किया जाए। उन्होंने आगे कहा कि यह मुआवजा केंद्र और राज्य सरकार द्वारा संयुक्त रूप से देने के बजाय पूरी तरह से केंद्र सरकार द्वारा दिया जाए, क्योंकि ये मेहनती किसान देश को खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर बनाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। सीमावर्ती क्षेत्रों में रक्षा की दूसरी पंक्ति को मजबूत करने के संबंध में, मुख्य मंत्री ने सभी 2107 सीमावर्ती गांवों के लिए बॉर्डर विंग होम गार्ड्स स्कीम को मजबूत करने पर जोर दिया। उन्होंने प्रत्येक जवान के लिए 1999 में निर्धारित ड्यूटी भत्ता 45 रुपए प्रतिदिन से बढ़ाकर न्यूनतम 655 रुपए करने की भी मांग की। उन्होंने कहा कि सीमावर्ती गांवों और बी.एस.एफ. के बीच बेहतर तालमेल के लिए यह आवश्यक है। भगवंत सिंह मान ने ड्रोन के माध्यम से नशे और हथियारों की तस्करी रोकने के लिए जैमर सहित अन्य उपकरण और बुनियादी ढांचे को अपग्रेड करने के लिए 2829 करोड़ रुपये की भी मांग की।

मुख्य मंत्री ने कहा कि यह बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि सीमा का 4/5 हिस्सा जैमिंग सिस्टम के बिना है, जिसके कारण देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता के लिए बड़ी चुनौती खड़ी होती है। भगवंत सिंह मान ने केंद्र सरकार द्वारा शुरू किए गए ह्यगतिशील गांव प्रोग्रामह्ल में संशोधन करके राज्य के अधिक से अधिक सीमावर्ती गांवों को इसका लाभ देने की मांग की। उन्होंने कहा कि पंजाब के सीमावर्ती जिलों में अन्य राज्यों की तुलना में अधिक आबादी रहती है। उन्होंने कहा कि सीमा के 10 किलोमीटर के दायरे में राज्य के 1500 गांव आते हैं, जिनमें से केवल 101 गांवों को इस योजना के लिए चुना गया है।

इस दौरान, मुख्य मंत्री ने कहा कि जब अब सिंधु नदी का पानी देश के आंतरिक राज्यों को दिया जाना है, तो पंजाब का इस पर प्राथमिक अधिकार है। उन्होंने कहा कि पंजाब लंबे समय से देश की खाद्यान्न आवश्यकताओं को पूरा करता आ रहा है, इसलिए यह बहुत जरूरी है कि इसे अपनी सिंचाई जरूरतों के लिए पानी दिया जाए। भगवंत सिंह मान ने कहा कि राज्य के हितों की हर तरह से रक्षा की जानी चाहिए और इस पर कोई कसर बाकी नहीं छोड़नी चाहिए।

बांग्लादेश ने नेपाल के अपर कर्णाली हाइड्रोपावर से बिजली खरीद समझौते को किया खारिज

500 मेगावाट पावर परचेज एग्रीमेंट को भी खत्म करने का निर्णय लिया गया:करीम

एजेंसी (हि.स.)
काठमांडू

नेपाल से भारत के रास्ते 40 मेगावाट बिजली आयात करने वाली बांग्लादेश सरकार ने भारतीय अपर कर्णाली हाइड्रोपावर से बिजली खरीद समझौते को खारिज कर दिया है।

बांग्लादेश के विद्युत विकास बोर्ड ने अपर कर्णाली हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट के साथ किए गए 500 मेगावाट विद्युत आपूर्ति समझौते के प्रारंभिक आशय पत्र को खारिज करने की जानकारी दी है। बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार के समय 2010 में भारत के साथ अधिक से अधिक बिजली खरीद को लक्षित करते हुए लाई गई विशेष ऊर्जा कानून लाया गया था।

सत्ता उलटफेर के बाद बनी युनुस सरकार ने इस ऊर्जा कानून को ही रद्द कर दिया है, जिसके अंतर्गत नेपाल के साथ किए गए अपर कर्णाली हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट से बिजली आपूर्ति समझौता भी खारिज हो गया है।

भारतीय अपर कर्णाली हाइड्रोपावर से नेपाल से भारत के रास्ते 40 मेगावाट बिजली आयात

बांग्लादेश पावर डेवलपमेंट बोर्ड के अध्यक्ष रिजाउल करीम के हवाले से डेली आब्जर्वर अखबार ने पुष्टि की है कि नेपाल के साथ हुए 500 मेगावाट पावर परचेज एग्रीमेंट को भी खत्म करने का निर्णय लिया गया है। इस अखबार का दावा है कि अपर कर्णाली हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट का निर्माण भारतीय कंपनी जीएमआर, सतलुज जैसी कंपनियां कर रही थीं, इसलिए इस समझौते को खारिज किया गया है। जीएमआर की तरफ से एसएम बोर्ड ने बांग्लादेश के ऊर्जा सचिव को फरवरी 2025 में एक पत्र लिखते हुए औपचारिक रूप से बिजली आपूर्ति समझौता करने का आग्रह किया था। इस पत्र में 2029 से लेकर 25 वर्षों तक के लिए बिजली आपूर्ति समझौता करने की बात उल्लेख की गई थी। थी बांग्लादेश के विद्युत विकास बोर्ड ने अपर कर्णाली हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट के साथ किए गए 500 मेगावाट विद्युत आपूर्ति समझौते के प्रारंभिक आशय पत्र को खारिज करने की जानकारी दी है। बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार के समय 2010 में भारत के साथ अधिक से अधिक बिजली खरीद को लक्षित करते हुए लाई गई विशेष ऊर्जा कानून लाया गया था। सत्ता उलटफेर के बाद बनी युनुस सरकार ने इस ऊर्जा कानून को ही रद्द कर दिया है, जिसके अंतर्गत नेपाल के साथ किए गए अपर कर्णाली हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट से बिजली आपूर्ति समझौता भी खारिज हो गया है।

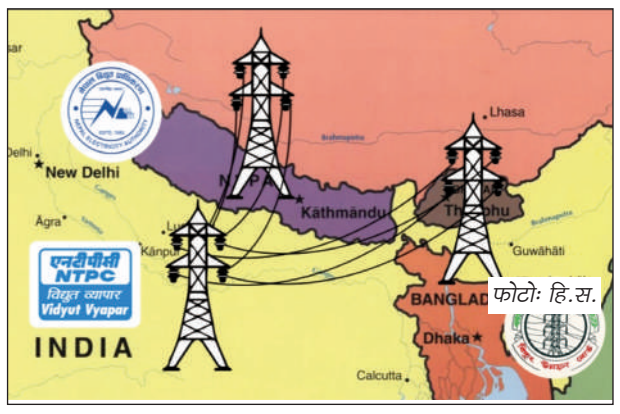

फोटोः हि.स.

बांग्लादेश पावर डेवलपमेंट बोर्ड के अध्यक्ष रिजाउल करीम के हवाले से डेली आब्जर्वर अखबार ने पुष्टि की है कि नेपाल के साथ हुए 500 मेगावाट पावर परचेज एग्रीमेंट को भी खत्म करने का निर्णय लिया गया है। इस अखबार का दावा है कि अपर कर्णाली हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट का निर्माण भारतीय कंपनी जीएमआर, सतलुज जैसी कंपनियां कर रही थीं, इसलिए इस समझौते को खारिज किया गया है। जीएमआर की तरफ से एसएम बोर्ड ने बांग्लादेश के ऊर्जा सचिव को फरवरी 2025 में एक पत्र लिखते हुए औपचारिक रूप से बिजली आपूर्ति समझौता करने का आग्रह किया था। इस पत्र में 2029 से लेकर 25 वर्षों तक के लिए बिजली आपूर्ति समझौता करने की बात उल्लेख की गई थी।

ममदानी भयानक दिखते हैं: डोनाल्ड ट्रंप

फोटोः हि.स.

ट्रंप का न्यूयॉर्क सिटी के भावी मेयर ममदानी पर तीखा तंज

एजेंसी (हि.स.)
वाशिंगटन

न्यूयॉर्क सिटी के मेयर बनने के करीब पहुंच चुके भारत की मशहूर फिल्मकार मीरा नायर के बेटे जोहरान ममदानी कई लोगों के निशाने पर आ गए हैं। उन पर निशाना साधने वालों में लोगों में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी शामिल हो गए हैं। द न्यूयॉर्क टाइम्स की खबर के अनुसार, राष्ट्रपति ट्रंप ने वीरवार एम्स्टर्डम से वाशिंगटन की अपनी उड़ान के कुछ घंटों बाद अपने सोशल ट्रुथ पर लिखा, हमारे पास पहले भी कट्टरपंथी वामपंथी थे, लेकिन यह थोड़ा हास्यास्पद हो रहा है। ममदानी भयानक दिखते हैं। उल्लेखनीय है कि ममदानी इस समय न्यूयॉर्क स्टेट असेंबली सदस्य हैं।

यही नहीं कल रात वोटों की गिनती के समय न्यूयॉर्क रिपब्लिकन की प्रतिनिधि एलिस स्टेफनिक ने न्यूयॉर्क शहर के मेयर के लिए डेमोक्रेटिक प्राइमरी में ममदानी की लगभग आधिकारिक जीत के लिए संभावित राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी को दोषी ठहराने की कोशिश की।

उल्लेखनीय है कि भारतीय मूल के 33 वर्षीय जोहरान ममदानी इस पद पर पहुंचने वाले पहले भारतीय-अमेरिकी और पहले मुस्लिम होंगे। उनकी मां मीरा नायर के खाते में सलाम बॉम्बे, नेमसेक और मॉनसून वेडिंग जैसी मशहूर फिल्में हैं। जोहरान ने चुनाव प्रचार में मुफ्त बस सेवा, मुफ्त चाइल्ड केयर, अधिक किफायती मकान, न्यूनतम वेतन में इजाफा और अमीरों पर अतिरिक्त टैक्स जैसे मुद्दों को उठाया है। युगांडा में जन्मे मीरा नायर के बेटे जोहरान के पिता महमूद ममदानी मशहूर शिक्षाविद हैं। अमेरिकी न्यूज चैनल सीएनएन का अनुमान है कि ममदानी का शुरुआती समर्थन 50 फीसद से कम रहेगा। इसका आशय यह हुआ कि इस दौड़ में औपचारिक रूप से रैंक-चॉइस वोट निर्णायक होंगे। इसकी घोषणा 1 जुलाई से की जाएगी।

डोनाल्ड ट्रंप अगले हफ्ते करेंगे ईरान से बातचीत

हेग (नीदरलैंड)। उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन (नाटो) शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने पहुंचे अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वह अगले हफ्ते ईरान से बातचीत करेंगे। उन्होंने यह स्पष्ट नहीं किया कि बातचीत का प्रारूप क्या होगा। उन्होंने कहा कि ईरान-इजराइल में युद्ध विराम के बाद स्थितियां अनुकूल बन रही हैं। द न्यूयॉर्क टाइम्स अखबार की खबर के अनुसार, ट्रंप ने कल हेग में नाटो शिखर सम्मेलन में संवाददाताओं से कहा कि ईरान अपनी परमाणु महत्वाकांक्षा को त्यागने को तैयार है। इसलिए अब बातचीत करने में कोई हर्ज नहीं है। और यह भी ईरान और इजराइल के बीच युद्ध विराम दूसरे दिन में प्रवेश कर गया है। अब दोनों देशों से बुरी खबरें नहीं आ रहीं। ट्रंप ने कहा कि अगर अमेरिका ने ईरान के परमाणु सुविधा केंद्रों पर आक्रमण नहीं किया होता तो शायद वह समझौते के लिए तैयार नहीं होता। इस दौरान ट्रंप ने मंगलवार को जारी एक प्रारंभिक अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट के निष्कर्षों के खिलाफ भी तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की। इसमें कहा गया था कि ईरान की परमाणु सुविधाओं पर अमेरिका के हमलों ने देश की महत्वाकांक्षाओं को केवल कुछ महीनों के लिए पीछे धकेल दिया है।

कामाख्या धाम में अंबुबासी की निवृति, नीलाचल पहाड़ पर दर्शन के लिए पहुंचे लाखों भक्त

एजेंसी (हि.स.)
गुवाहाटी

फोटोः हि.स.

कामाख्या धाम में 22 जून को प्रवृत्ति के साथ आरंभ अंबुबासी महायोग का आज सुबह निवृत्ति के साथ समापन हो गया। अंबुबासी महायोग के चलते 22 जून से बंद मंदिर के कपाट आज सुबह देवी के स्नान, विधि-विधान से पूजा-अर्चना के बाद श्रद्धालुओं के लिए खोले गए। मंदिर के कपाट खुलते ही बड़ी संख्या में भक्तगण मां के दर्शन के लिए उमड़ पड़े। मां के दर्शन के लिए बीती रात से ही भक्त कतारबद्ध थे। मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत बिस्व सरमा ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट कर कामाख्या धाम पहुंचे लोगों को अपनी शुभकामनाएं प्रेषित कीं।

निवृति के दिन सुबह 4 बजे विशेष पूजा-अर्चना के साथ मंदिर प्रांगण और देवी को सुंदर तरीके से फूलों से सजाया गया। पूर्ण विश्राम के बाद मां कामाख्या की मूर्ति उज्ज्वल नव वस्त्र और फूलों से सजाई गई । मंदिर खुलने के साथ ही देश-विदेश से आए लाखों भक्त दर्शन के आस में कतार में लगे हुए हैं। इस बार अंबुबासी मेले के समय कामाख्या पर्वत और इसके आसपास के क्षेत्र के साथ-साथ पूरा गुवाहाटी शहर एक धार्मिक शहर में परिवर्तित हो गया था। दर्शन, पूजा-पाठ के अलावा मेले में साधु-संतों के धार्मिक संबोधन, पुण्य स्नान और विभिन्न लोक संस्कृतियों का प्रदर्शन आयोजित किया गया।

ऐसी मान्यता है कि अंबुबासी के दौरान मां कामाख्या रजस्वला होती हैं। ऐसे में कामाख्या समेत राज्य के सभी मंदिरों के कपाट अंबुबासी महायोग की निवृत्ति तक पूरी तरह से बंद रहते हैं। पूजा-पाठ भी मंदिरों में नहीं होता है। महायोग की निवृत्ति के साथ ही मंदिरों में पूजा-पाठ आरंभ हो गया है। अंबुबासी महायोग मुख्य रूप से तंत्र साधकों के लिए बेहद महत्वूर्ण माना जाता है।

अलकनंदा में गिरा टेंपो ट्रैवलर, दो की मौत, आठ घायल, 10 लापता

एजेंसी (हि.स.)
देहरादून

रुद्रप्रयाग के घोलतीर क्षेत्र में गुरुवार सुबह एक टेंपो ट्रैवलर अनियंत्रित होकर अलकनंदा नदी में गिर गया। इस हादसे दो यात्रियों की मौत हो गई, जबकि आठ घायलों को रेस्क्यू के उपरान्त जिला चिकित्सालय भिजवाया गया है। दुर्घटना में 10 यात्री लापता बताए जा रहे हैं, जिनकी तलाश के लिए रेस्क्यू कार्य जारी है। प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि युद्ध स्तर पर राहत एवं बचाव कार्य किया जा रहा है।

फोटोः हि.स.

जिला आपदा प्रबंध अधिकारी नंदन रजवार ने बताया कि टेंपो ट्रैवलर बद्रीनाथ की ओर जा रहा था, जो घोलतीर क्षेत्र में अनियंत्रित होकर अलकनंदा नदी में गिर गया। रेस्क्यू टीमों ने त्वरित राहत एवं बचाव कार्य प्रारंभ करते हुए घायलों को उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया है। मौके पर रेस्क्यू अभियान जारी है। घटनास्थल पर एसडीआरएफ, पुलिस बल और स्थानीय प्रशासन की टीमें राहत कार्यों में जुटी हुई हैं। घायलों की पहचान दीपिका सोनी निवासी सिरोही मीना वास, राजस्थान उम्र 42 वर्ष, हेमलता सोनी निवासी गोगुण्डा, राजस्थान उम्र 45 वर्ष, ईश्वर सोनी निवासी ई 202 पर्वत सिलिकॉन पैलेस, नियर अर्चना स्कूल, गुजरात उम्र 46 वर्ष, अमिता सोनी निवासी मीरा रोड, महाराष्ट्र उम्र 49 वर्ष, सोनी भावना ईश्वर निवासी ई 202 पर्वत सिलिकॉन पैलेस, नियर अर्चना स्कूल, गुजरात उम्र 43 वर्ष, भव्य सोनी निवासी ई 202 सिलिकॉन पैलेस, बाम्बे मार्केट, नियर अर्चना स्कूल, गुजरात उम्र 07 वर्ष, पार्थ सोनी निवासी वार्ड नं. 11 राजगढ़, वीर सावरकर मार्ग ग्राम राजगढ़ मध्य प्रदेश उम्र 10 वर्ष, सुमित कुमार (चालक) पुत्र नरेश कुमार निवासी बैरागी कैम्प, हरिद्वार, उम्र 23 वर्ष के रूप में हुई है। मृतकों की पहचान की जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, "जनपद रुद्रप्रयाग में एक टेंपो ट्रैवलर के नदी में गिरने का समाचार अत्यंत दुःखद है। एसडीआरएफ सहित अन्य बचाव दलों द्वारा युद्ध स्तर पर राहत एवं बचाव कार्य किया जा रहा है। इस संबंध में निरंतर स्थानीय प्रशासन से संपर्क में हूं। ईश्वर से सभी के सकुशल होने की प्रार्थना करता हूं।

संक्षिप्त-समाचार

जम्मू कश्मीरः उधमपुर में सुरक्षाबलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़

उधमपुर। जम्मू संभाग के उधमपुर के बसंतगढ़ इलाके में गुरुवार सुबह सुरक्षाबलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ हो रही है। दोनों ओर से भारी गोलीबारी जारी है। एक शीर्ष पुलिस अधिकारी ने बताया कि संदिग्ध गतिविधि के बारे में विशेष इनपुट मिलने के बाद कड़ी घेराबंदी की गई थी। अधिकारी ने बताया कि तलाशी के दौरान सुरक्षाबलों पर गोलीबारी हुई, जिसके बाद सुरक्षाबलों ने भी जवाबी गोलीबारी की है। दोनों ओर से फिलहाल भारी गोलीबारी जारी है। उन्होंने बताया कि सुरक्षाबलों ने इलाके की घेराबंदी कर दी है तथा और अतिरिक्त बल भेजा गया है।

पतंजलि जमीन घोटाले में पूर्व प्रधानमंत्री माधव नेपाल को मिली जमानत

काठमांडू। नेपाल में करोड़ों रुपये के पतंजलि ट्रस्ट के जमीन घोटाला मामले में विशेष अदालत ने पूर्व प्रधानमंत्री माधव कुमार नेपाल को जमानत प्रदान कर दी। इस मामले में एंटी करप्शन ब्यूरो ने पूर्व प्रधानमंत्री माधव कुमार नेपाल को आरोपित बनाते हुए विशेष अदालत में मुकदमा दायर किया था। इस पर बुधवार को सुनवाई करते हुए विशेष अदालत ने माधव नेपाल का बयान दर्ज किया। साथ ही न्यायिक हिरासत में भेजे जाने की सरकारी पक्ष की मांग को अस्वीकार करते हुए उन्हें जमानत पर बाहर रखने का आदेश दिया । विशेष अदालत ने बुधवार देररात माधव कुमार नेपाल को 35 लाख रुपये के मुचलके पर जमानत दी। यह जानकारी उनके वकील शंभू थापा ने दी।उन्होंने बताया कि माधव कुमार को अदालत ने हर तारीख पर अदालत में उपस्थित होने का आदेश दिया है। साथ बिना कोर्ट की इजाजत के विदेश जाने पर रोक लगा दी।

बांग्लादेश के तीन पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्तों के खिलाफ केस दर्ज, देशद्रोह का आरोप

ढाका। बांग्लादेश के तीन पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्तों काजी रकीबुद्दीन अहमद, केएम नूरुल हुदा और काजी हबीबुल अवाल समेत 10 पूर्व चुनाव आयुक्त और 11 अन्य के खिलाफ दर्ज केस में देशद्रोह समेत तीन नए आरोप जोड़े गए हैं। इन पर 2014, 2018 और 2024 के राष्ट्रीय चुनाव के दौरान अनियमितता और पूर्वाग्रह में कथित संलिप्तता का आरोप लगाया गया है। द डेली स्टार अखबार की खबर के अनुसार, ढाका मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट मोहम्मद मिनहाजुर रहमान ने जांचकर्ताओं के आवेदन पर पूर्व में दर्ज केस में कल सुनवाई के दौरान नए आरोप जोड़ने की अनुमति प्रदान की। अब इन सभी को दंड संहिता की धारा 124ए (देशद्रोह), 420 (धोखाधड़ी और बेईमानी से संपत्ति हड़पने के लिए प्रेरित करना) और 406 (आपराधिक विश्वासघात) जैसे संगीन आरोपों का सामना करना पड़ेगा।

बसंतगढ़ के सुदूर बिहाली इलाके में जैश-ए-मोहम्मद के चार आतंकवादी सुरक्षाबलों के घेरे में

जम्मू। जम्मू-कश्मीर के उधमपुर बसंतगढ़ के सुदूर बिहाली इलाके में जैश-ए-मोहम्मद के चार आतंकवादी सुरक्षाबलों के साथ मुठभेड़ में फंसे हुए हैं, जिनकी पिछले एक साल से तलाश की जा रही थी। सुरक्षाबल बारिश और कोहरे के बीच उन्हें मार गिराने की कोशिश कर रहे हैं। जम्मू रेंज के पुलिस महानिरीक्षक भीम सेन टूटी ने वीरवार को बताया कि यह मुठभेड़ तब शुरू हुई, जब सेना और पुलिस के संयुक्त तलाशी दल ने एक विशेष खुफिया सूचना के आधार पर आज सुबह जिले के बसंतगढ़ के सुदूर बिहाली इलाके में तलाशी अभियान शुरू किया। अतिरिक्त सुरक्षाबलों को भेजा गया है और खराब मौसम के बावजूद व्यापक तलाशी अभियान जारी है। उन्होंने बताया कि सुबह करीब साढ़े आठ बजे आतंकवादियों से संपर्क स्थापित हुआ। माना जा रहा है कि उनकी संख्या चार है और हम पिछले एक साल से इस समूह पर नजर रख रहे हैं। उन्होंने कहा कि कोहरे के बावजूद तलाशी अभियान जारी है और मौसम में सुधार होने पर ही वास्तविक तस्वीर सामने आएगी। फंसे हुए आतंकवादी पाकिस्तान स्थित जैश-ए-मोहम्मद के सदस्य हैं और सेना के पैरा कमांडो के नेतृत्व में संयुक्त तलाशी दल ने उन्हें करूर नाले के पास छिपे हुए पाया।

चकराता में कार दुर्घटना में चार की मौत, तीन घायल

देहरादून। देहरादून जिले में चकराता मार्ग पर डाकपत्थर के समीप बृहस्पतिवार को एक कार के गहरी खाई में गिरने से उसमें सवार तीन व्यक्तियों की मृत्यु हो गयी तथा एक अन्य घायल हो गया । पुलिस ने यहां बताया कि हादसा जजरेड़ में हुआ जहां वाहन अनियंत्रित होकर 400 मीटर गहरी खाई में गिरकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। दुर्घटना की सूचना मिलने पर पुलिस तथा राज्य आपदा प्रतिवादन बल की टीमें मौके पर पहुंची और राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया। तीन व्यक्तियों की मौके पर ही मृत्यु हो गयी जबकि एक अन्य को घायल अवस्था में खाई से बाहर निकाला गया। हादसे का शिकार हुए सभी व्यक्ति स्थानीय हैं । घायल व्यक्ति की पहचान चकराता तहसील के रहने वाले मयंक चौहान के रूप में हुई है । मृतकों में चकराता के कोटी कनासर गांव के मुकेश राणा , सहसपुर निवासी प्रियांशु चौहान और भाऊवाला के दीपक सती शामिल हैं।

मायावती ने केजीएमयू का नाम बदलकर छत्रपति शाहूजी महाराज रखने की मांग की

मायावती ने 'राजर्षि' छत्रपति शाहूजी महाराज की जंयती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की

एजेंसी (हि.स.)
लखनऊ,

26 बहुजन समाज पार्टी (बीएसपी) की राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने 'राजर्षि' छत्रपति शाहूजी महाराज की जंयती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इसी के साथ उन्होंने किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी (केजीएमयू) का नाम बदल कर छत्रपति शाहूजी महाराज मेडिकल यूनिवर्सिटी करने की मांग की है। उन्होंने आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी (सपा) की सरकार द्वारा इसका नाम जबरदस्ती बदलकर किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी कर दिया गया था।

फोटोः हि.स.

मायावती ने गुरुवार को सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि कोल्हापुर, महाराष्ट्र रियासत में दलितों को नौकरी में आरक्षण देने का क्रान्तिकारी कदम उठाकर भारत में आरक्षण के जनक के रूप में अमर हो जाने वाले राजर्षि छत्रपति शाहूजी महाराज को आज उनकी जयंती पर शत-शत नमन व अपार श्रद्धा-सुमन अर्पित तथा उनके समस्त अनुयाइयों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएंं। किन्तु विशेष उल्लेखनीय है राजधानी लखनऊ में यूपी की पहली छत्रपति शाहूजी महाराज मेडिकल यूनिवर्सिटी स्थापित करके उसे तुरन्त चालू करना, जिसको दलित व पिछड़े वर्ग के बहुजनों व उनके आरक्षण के हमेशा विरोधी रही समाजवादी पार्टी (सपा) की सरकार द्वारा उसका नाम जबरदस्ती बदलकर किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी कर दिया गया है।

हालांकि उसी नाम से लखनऊ में मेडिकल कॉलेज काफी पहले से ही स्थापित है। मायावती ने लिखा कि दुखद है कि यूपी में सपा के बाद आयी भाजपा सरकार ने भी इतना लम्बा समय बीत जाने के बावजूद, अभी तक भी सपा के ऐसे घोर द्वेषपूर्ण एवं जातिवादी रवैये को व्यापक जनहित में जरूरी बदलाव/सुधार नहीं किया है। अतः छत्रपति शाहूजी महाराज मेडिकल यूनिवर्सिटी का असली नाम जितनी जल्द बहाल हो उतना बेहतर।

छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में मुठभेड़, दो महिला नक्सली ढेर

फोटोः हि.स.

एजेंसी (हि.स.)
नारायणपुर/रायपुर

नारायणपुर जिले में अबूझमाड़ के कोहकामेटा थाना क्षेत्र के घने जंगलों में सुरक्षाबलों और नक्सलियों के बीच जबरदस्त मुठभेड़ हुई है। यहां सुरक्षाबलों की नक्सलियों के साथ बुधवार रात से गुरुवार सुबह तक चली मुठभेड़ में दो महिला नक्सली मारी गई हैं। घटनास्थल से महिला नक्सलियों के शव, एक इंसास राइफल, एक .315 बोर हथियार, मेडिकल किट और अन्य समान बरामद हुआ है। पुलिस अधीक्षक प्रभात कुमार ने इसकी पुष्टि की है।

नारायणपुर पुलिस के अनुसार माड़ डिवीजन के सक्रिय माओवादी कैडर की मौजूदगी की जानकारी के बाद डीआरजी (डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड) नारायणपुर, कोंडागांव एवं एसटीएफ (स्पेशल टास्क फोर्स) की संयुक्त टीम ने बुधवार शाम से क्षेत्र में सर्चिंग अभियान शुरू किया। गुरुवार सुबह तक चली मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने दो महिला नक्सलियों को मार गिराया है। पुलिस ने बताया कि मारी गई महिला नक्सलियों की पहचान की जा रही है। सर्चिंग अभियान अब भी जारी है।

इमरान खान की पत्नी बुशरा बीबी की अंतरिम जमानत अवधि कोर्ट ने बढ़ाई

एजेंसी (हि.स.)
रावलपिंडी (पाकिस्तान)

आतंकवाद निरोधक अदालत ने आज पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) संस्थापक और पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पत्नी बुशरा बीबी की अंतरिम जमानत अवधि बढ़ा दी। अदालत ने उन्हें यह राहत 26 नवंबर के विरोध प्रदर्शन से संबंधित मामलों में प्रदान की। दुनिया न्यूज चैनल की खबर के अनुसार, न्यायाधीश अमजद अली शाह ने पूर्व प्रथम महिला के खिलाफ 12 मामलों की सुनवाई की और उनकी उपस्थिति को अदालत के नोटिस के माध्यम से दर्ज किया। अदालत ने सुनवाई 10 जुलाई तक स्थगित करते हुए अगली तारीख पर सभी मामलों के लिए पुलिस से आरोप पत्र भी तलब किया है। न्यायाधीश ने दोनों पक्षों के वकीलों को अगली सुनवाई पर अपनी दलीलें पेश करने का निर्देश भी दिया है। इस बीच, आतंकवाद निरोधी अदालत ने जीएचक्यू हमले और 09 मई के मामलों की सुनवाई भी 03 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दी है। इस सप्ताह की शुरूआत में लाहौर हाई कोर्ट ने पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की 09 मई, 2023 की घटनाओं से संबंधित आठ मामलों में जमानत याचिकाओं को खारिज कर दिया। न्यायमूर्ति सैयद शाहबाज अली रिजवी की अध्यक्षता वाली लाहौर हाई कोर्ट की दो सदस्यीय पीठ ने पीटीआई संस्थापक इमरान खान की जमानत याचिकाओं पर सुनवाई की।

फोटोः हि.स.

उनके वकील बैरिस्टर सलमान सफदर ने तर्क दिया कि मामले राजनीति से प्रेरित थे और याचिकाकर्ता सुप्रीम कोर्ट के समक्ष पेश होने के समय एनएबी की हिरासत में था, उसे बाहर की स्थिति के बारे में पता नहीं था। उन्होंने कहा कि इमरान खान ने दंगों की निंदा की है और अदालत से गिरफ्तारी के बाद जमानत देने का अनुरोध किया है।

फैसला वर्ष 1964 में 27 जून को तीन मूर्ति भवन में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का संग्रहालय बनाया जाएग

इतिहास के पन्नों में 27 जून: दिलचस्प है तीन मूर्ति भवन की कहानी

देश-दुनिया के इतिहास में 27 जून की तारीख तमाम अहम वजह से दर्ज है। इस तारीख का रिश्ता नई दिल्ली के तीन मूर्ति भवन से भी है। वर्ष 1964 में 27 जून को यह फैसला किया गया था कि तीन मूर्ति भवन में भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का संग्रहालय (नेहरू मेमोरियल म्यूजियम) बनाया जाएगा। दरअसल इसी तीन मूर्ति भवन में नेहरू का आधिकारिक आवास था। उनकी मृत्यु के बाद इसे संग्रहालय में बदल दिया गया। 14 नवंबर, 1964 को तत्कालीन राष्ट्रपति एस. राधाकृष्णन ने तीन मूर्ति भवन में नेहरू स्मारक संग्रहालय का उद्घाटन किया था। केंद्र सरकार ने दो बरस पहले इसका नाम बदलकर पीएम म्यूजियम कर दिया है। यह भवन भारत में आजादी से पहले और आजादी के बाद कई दशकों तक सत्ता के वर्चस्व का प्रतीक रहा है। साल 1948 में जब पंडित नेहरू देश के प्रधानमंत्री बने तो तीन मूर्ति भवन उनका आधिकारिक आवास बना। नेहरू 16 साल तक यहां रहे और यहीं पर अंतिम सांस ली। आजादी से पहले एडविन लुटियंस की इंपीरियल कैपिटल का हिस्सा रहा तीन मूर्ति भवन अंग्रेजी शासन में भारत के कमांडर इन चीफ का आधिकारिक आवास था। इस भवन का नाम तीन मूर्ति क्यों पड़ा इसकी भी एक कहानी है। जिस जगह यह भवन स्थित है वहां के गोल चक्कर पर बीचों बीच एक स्तंभ के किनारे तीन दिशाओं में मुंह किए हुए तीन सैनिकों की मूर्तियां लगी हुई हैं। ये द्वितीय विश्व युद्ध में लड़े सैनिकों का स्मारक है। इस स्मारक की वजह से ही भवन का नाम तीन मूर्ति पड़ा यह भवन मूल रूप से ऑस्ट्योर क्लासिक शैली में निर्मित है। इसी शैली से निर्मित दूसरा भवन दिल्ली का हैदराबाद हाउस भी है।

फोटोः हि.स.

जन्म

1919: मशहूर भारतीय नृत्यांगना एवं कोरियोग्राफर अमला शंकर।
1939: हिन्दी फिल्मों के संगीतकार राहुल देव बर्मन।
1950: हिन्दी सिनेमा के प्रसिद्ध भारतीय गायक नितिन मुकेश।
1964: भारतीय धावक पीटी उषा।

निधन

1839: पंजाब के महाराजा रणजीत सिंह।
2008: भारतीय सेना के पूर्व अध्यक्ष सैम मानेकशॉ। सैम के ही नेतृत्व में भारत ने सन 1971 में हुए भारत-पाकिस्तान युद्ध में विजय प्राप्त की थी।

महत्वपूर्ण घटनाचक्र

1693: लंदन में महिलाओं की पहली पत्रिका लेडीज मरकरी का प्रकाशन शुरू।
1940: सोवियत संघ की सेना ने रोमानिया पर हमला किया।
1957: ब्रिटेन की मेडिकल रिसर्च काउंसिल की एक रिपोर्ट में बताया गया कि धूम्रपान की वजह से फेफड़ों का कैंसर हो सकता है।
1967: लंदन के एनफील्ड में विश्व का पहला एटीएम स्थापित किया गया।
1967: भारत में निर्मित पहले यात्री विमान एचएस 748 को इंडियन एयरलाइंस को सौंपा गया।
1991: युगोस्लाविया की सेना ने स्लोवेनिया के स्वतंत्र होने के 48 घंटे के भीतर ही इस छोटे से देश पर हमला कर दिया।
2002: जी-8 देश परमाणु हथियार नष्ट करने की रूसी योजना पर सहमत।
2003: संयुक्त राज्य अमेरिका में समलैंगिकता पर प्रतिबंध रद्द।
2004: अमेरिका और यूरोपीय संघ ने जीपीएस. गैलेलियो के विकास में सहयोग से संबंधित समझौते पर हस्ताक्षर किए।
2005: ब्रिटेन ने भारत की वीटो रहित स्थायी सदस्यता का समर्थन किया।
2006: गुयेन मिन्ह ट्रयेट वियतनाम के राष्ट्रपति चुने गए।
2007: जेम्स गार्डन ब्राउन ने ब्रिटिश प्रधानमंत्री का पद संभाला। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर ने महारानी एलिजाबेथ को अपना त्यागपत्र सौंपा।
2008: भारत और पाकिस्तान ने ईरान से आने वाली गैस पाइप लाइन परियोजना को चालू करने के लिए आ रही रुकावटों को हल किया।
2008: माइक्रोसॉफ्ट कारपोरेशन के चेयरमैन बिल गेट्स ने अपने पद से इस्तीफा दिया।
2015: भारतीय फिल्मकार सत्यजीत रे (सत्यजित राय) की तस्वीर को संयुक्त राष्ट्र ने अपने मुख्यालय में प्रदर्शित करने का फैसला किया।
2021: जम्मू में वायुसेना के अड्डे पर आतंकवादियों ने ड्रोन के जरिए विस्फोटक गिराए।

ब्रिजटाउन टेस्ट: पहले दिन गिरे 14 विकेट, ऑस्ट्रेलिया 180 पर ढेर

वेस्टइंडीज भी संकट में, शामार जोसेफ और सील्स की घातक गेंदबाजी

एजेंसी (हि.स.)
ब्रिजटाउन

- ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों का फ्लॉप शो
- ख्वाजा और हेड की साझेदारी बनी सहारा

वेस्टइंडीज ने पहले टेस्ट के पहले दिन गुरुवार (भारतीय समयानुसार) को ऑस्ट्रेलिया को सिर्फ 180 रनों पर समेट दिया, लेकिन केंसिंग्टन ओवल की पिच की चुनौती का अंदाजा उसे तब हुआ जब दिन के अंत तक उसने खुद 4 विकेट गंवा दिए। स्टंप्स तक वेस्टइंडीज का स्कोर 57/4 रहा, जहां डेब्यू कर रहे ब्रैंडन किंग 23 रन बनाकर नाबाद हैं।

हालांकि किंग के लिए दिन मिश्रित रहा, क्योंकि उन्होंने फील्डिंग में तीन कैच छोड़े, लेकिन अंत में बल्लेबाजी में संभलने की कोशिश की। वेस्टइंडीज के लिए सबसे प्रभावशाली गेंदबाज शामार जोसेफ रहे, जिन्होंने 46 रन देकर 4 विकेट झटके। वहीं जयडेन सील्स ने 60 रन देकर 5 विकेट लिए, जो कि उनके टेस्ट करियर का तीसरा पांच विकेट हॉल रहा। दिलचस्प बात यह है कि उनके 34 टेस्ट विकेटों में से 17 ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज हैं। ऑस्ट्रेलियाई टीम पहली पारी में महज 56.1 ओवर में सिमट गई – यह वेस्टइंडीज की जमीन पर ऑस्ट्रेलिया का सबसे कम स्कोर है जब उन्होंने पहले बल्लेबाजी की हो।

फोटोः हि.स.

ऑस्ट्रेलिया की ओर से केवल तीन बल्लेबाज ही दहाई का आंकड़ा पार कर सके – ट्रैविस हेड (59), उस्मान ख्वाजा (47) और कप्तान पैट कमिंस (28)। पैट कमिंस ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया, लेकिन पिच पर तेज गेंदबाजों को जबरदस्त मदद मिली – सीम, स्विंग और कई बार गेंद नीची रही। दिन के कुल 14 विकेटों में से 10 विकेट कैच के जरिए गिरे। ऑस्ट्रेलिया ने पहले घंटे में ही 3 विकेट गंवा दिए थे। मार्नस लाबुशेन की जगह उतरे सैम कॉन्स्टास सिर्फ 3 रन बनाकर जोसेफ की गेंद पर एलबीडब्ल्यू आउट हुए। जोसेफ ने इसके बाद कैमरून ग्रीन को भी चलता किया, जिन्हें गली में किंग ने जीवनदान देने के बाद स्लिप में आउट कर दिया। ख्वाजा और हेड ने मिलकर पारी को थोड़ा संभाला और लंच के बाद 89 रनों की साझेदारी की। हेड ने 57 गेंदों में अर्धशतक पूरा किया, लेकिन ख्वाजा 128 गेंदों पर 47 रन बनाकर आउट हुए। जोसेफ ने एक समय 12 ओवर में 4 विकेट लेकर ऑस्ट्रेलिया को झकझोर दिया। चार साल बाद टेस्ट में वापसी कर रहे विकेटकीपर शाई होप ने चार कैच लपके। उन्होंने जोश इंग्लिस का कैच लेकर अपना खाता खोला। जवाब में वेस्टइंडीज की शुरूआत भी खराब रही। मिचेल स्टार्क ने कप्तान क्रैग ब्रैथवेट (4) और जॉन कैंपबेल (7) को आउट किया। कमिंस ने कीसी कार्टी (20) को पवेलियन भेजा जबकि जोश हेजलवुड ने नाइटवॉचमैन जोमेल वोरिकन को शून्य पर आउट कर दिया।

अब तक का स्कोर

ऑस्ट्रेलिया पहली पारीः 180 ऑलआउट (ट्रैविस हेड 59, ख्वाजा 47; सील्स 5/60, जोसेफ 4/46)

वेस्टइंडीज पहली पारीः 57/4 (ब्रैंडन किंग 23*, चेस 1*; स्टार्क 2/15)

वीरांगना की धरती पर हॉकी का संग्राम 17 से 22 जुलाई तक

फोटोः हि.स.

- विभिन्न राज्यो की 12 महिला टीमें करेंगी शिरकता

एजेंसी (हि.स.)
झांसी

वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की भूमि झांसी में आगामी 17 से 22 जुलाई तक मेजर ध्यानचंद एस्ट्रोटर्फ हॉकी स्टेडियम में आयोजित होने वाली अखिल भारतीय आमंत्रण प्राइजमनी महिला हॉकी प्रतियोगिता को लेकर तैयारियों का दौर तेज हो गया है। देश भर से हॉकी प्रतियोगिता में शामिल होने आ रहीं 12 टीमों के स्वागत के लिए झांसी तैयार है। जिलाधिकारी मृदुल चौधरी की अध्यक्षता में प्रतियोगिता के सफल आयोजन हेतु समीक्षा बैठक भी आयोजित की गई।

बैठक में क्षेत्रीय क्रीड़ाधिकारी सुरेश बोनकर ने बताया कि खेल निदेशालय, उत्तर प्रदेश एवं हॉकी इंडिया, नई दिल्ली के मानकों के अनुरूप इस छह दिवसीय प्रतियोगिता में देश की 12 प्रमुख महिला हॉकी टीमें भाग लेंगी। इनमें यूनियन बैंक ऑफ इंडिया मुंबई, साई छात्रावास सोनीपत, एमपी एकेडमी ग्वालियर, साई नेशनल सेंटर फॉर एक्सीलेंस कोलकाता, साई स्पोर्ट्स हॉस्टल रांची, साई हॉस्टल भोपाल, उत्तर मध्य रेलवे प्रयागराज, हॉकी कर्नाटक बेंगलुरु, स्टील प्लांट भिलाई, स्पोर्ट्स हॉस्टल राउरकेला, यूपी हॉकी आदि प्रमुख टीमें शामिल हैं।

प्रतियोगिता में विजेता टीम को दो लाख, उपविजेता को एक लाख और तीसरे स्थान पर रहने वाली टीम को पचास हजार नकदी देकर सम्मानित किया जाएगा। जिलाधिकारी ने संबंधित विभागों को निर्देशित किया कि महिला खिलाड़ियों के ठहरने के लिए अच्छे होटलों में व्यवस्था कराई जाए। आवासीय स्थल से स्टेडियम तक आवागमन के लिए बसें उपलब्ध कराई जाएं। साथ ही सुरक्षा के दृष्टिगत पुलिस व्यवस्था, नगर निगम द्वारा साफ-सफाई, चिकित्सा विभाग द्वारा डॉक्टरों और एम्बुलेंस की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बैठक में क्षेत्राधिकारी नगर, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जिला पंचायत राज अधिकारी, जिला युवा कल्याण अधिकारी, हॉकी झांसी के सचिव सुबोध खाण्डेकर, ओलंपिक संघ मंडल संयोजक संजीव सरावगी, पूर्व राष्ट्रीय खिलाड़ी मो. इब्राहिम खान, कोच अंकुर राणा और वरिष्ठ क्रिकेट खिलाड़ी विकास वेंदया भी उपस्थित रहे।

जिम्बाब्वे महिला टीम पहली बार खेलेगी आईसीसी महिला चैंपियनशिप, न्यूजीलैंड दौरे से होगा आगाज

एजेंसी (हि.स.)
हरारे

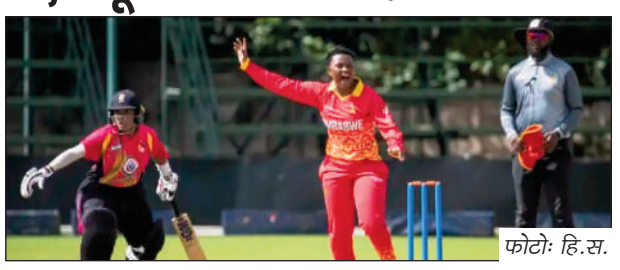
फोटोः हि.स.

जिम्बाब्वे महिला क्रिकेट टीम इतिहास रचने के लिए तैयार है। पहली बार आईसीसी महिला चैंपियनशिप में हिस्सा लेने जा रही जिम्बाब्वे की टीम अगले साल फरवरी-मार्च 2026 में न्यूजीलैंड दौरे पर जाएगी, जहां वह तीन एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय मैच खेलेगी। यह मुकाबले जिम्बाब्वे की महिला चैंपियनशिप में आधिकारिक शुरूआत होंगे।

तीन वनडे मैच 5, 8 और 11 मार्च को डुनेडिन में खेले जाएंगे। इससे पहले दोनों टीमों के बीच तीन टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच 25 फरवरी, 27 फरवरी और 1 मार्च को हैमिल्टन में होंगे। यह टी20 मुकाबले भी दोनों टीमों के बीच पहले आधिकारिक महिला टी20 मुकाबले होंगे। आईसीसी महिला चैंपियनशिप 2025-29 चक्र में जिम्बाब्वे की टीम को कुल आठ श्रृंखलाएं खेलनी हैं—चार घर में और चार विदेश में। जिम्बाब्वे घरेलू मैदान पर दक्षिण अफ्रीका, वेस्ट इंडीज, श्रीलंका और आयरलैंड के खिलाफ खेलेगी, जबकि विदेशी दौरे भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के होंगे।

महिला विश्व कप 2029 की राह

यह चैंपियनशिप 2029 में होने वाले महिला वनडे विश्व कप के लिए क्वालीफाई करने का मुख्य रास्ता है। 2025-29 का यह चक्र आईसीसी महिला चैंपियनशिप का चौथा संस्करण है। जिम्बाब्वे की इस प्रतियोगिता में एंट्री के बाद अब इसमें 11 टीमें हिस्सा ले रही हैं। अब तक जिम्बाब्वे महिला टीम ने छह टीमों के खिलाफ वनडे मुकाबले खेले हैं, जिनमें से बांग्लादेश, आयरलैंड और पाकिस्तान आईसीसी के पूर्ण सदस्य हैं।

जिम्बाब्वे क्रिकेट ने जताया गर्व

जिम्बाब्वे क्रिकेट (जेडसी) के प्रबंध निदेशक गिवेमोर माकोनी ने एक आधिकारिक बयान में कहा, ₹यह हमारे लिए गर्व और रोमांच का क्षण है कि जिम्बाब्वे महिला टीम अब वैश्विक स्तर पर शीर्ष क्रिकेट में कदम रख रही है। यह इस बात का प्रमाण है कि हमारी महिला क्रिकेट कितनी आगे बढ़ी है और यह हमारे विजन और निवेश की भी पुष्टि करता है।

एफसी बार्सिलोना की कैंप नू में वापसी की तारीख तय, 10 अगस्त को होगा पहला मैच

एजेंसी (हि.स.)
मैड्रिड

फोटोः हि.स.

एफसी बार्सिलोना ने बुधवार को पुष्टि की कि क्लब दो वर्षों के लंबे इंतजार के बाद 10 अगस्त को अपने ऐतिहासिक स्टेडियम कैंप नू में वापसी करेगा। क्लब की आधिकारिक वेबसाइट पर दी गई जानकारी के अनुसार, बार्सिलोना पारंपरिक जोआन गैम्पर प्री-सीजन ओपनर इसी दिन कैंप नू में खेलेगा। पिछले दो वर्षों से कैंप नू में व्यापक पुनर्निर्माण कार्य चल रहा है, जिसके कारण बार्सिलोना को अस्थायी रूप से लुईस कंपनी ओलंपिक स्टेडियम, मोंटजुइक में अपने घरेलू मुकाबले खेलने पड़े।

हालांकि यह स्टेडियम प्रशंसकों के बीच ज्यादा लोकप्रिय नहीं रहा और लगभग 57,000 दर्शकों की क्षमता के बावजूद अक्सर खाली नजर आया। बार्सिलोना अब अपने पारंपरिक घर में लौट रहा है, हालांकि निर्माण कार्य अभी पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ है। क्लब ने जानकारी दी कि, ₹जिन हिस्सों पर अभी काम बाकी है उनमें शामिल हैं ₹ नया तीसरा स्टैंड, डबल वीआईपी रिंग, छत की स्थापना, कुछ आंतरिक हिस्सों की तैयारी और स्टेडियम के आसपास के क्षेत्र का पुनर्निर्माण।₹ निर्माण कार्य जारी रहने के कारण 10 अगस्त को स्टेडियम की क्षमता लगभग 60,000 दर्शकों की होगी, जो कि 99,354 की अंतिम क्षमता से काफी कम है, लेकिन फिर भी जोआन गैम्पर मैच के लिए पहले अनुमानित 25,000 दर्शकों से कहीं अधिक है।

बार्सिलोना की यह वापसी न सिर्फ प्रशंसकों के लिए बड़ी खुशी की बात है, बल्कि यह क्लब के नए युग की शुरूआत भी मानी जा रही है।

सूर्यकुमार का जर्मनी में खेल हर्निया का सफल आपरेशन

नईदिल्ली। भारत के टी20 कप्तान सूर्यकुमार यादव का जर्मनी के म्युनिख में पेट के दायें ओर खेल हर्निया का सफल आपरेशन हुआ । 34 वर्ष के सूर्यकुमार ने बुधवार को अपने सोशल मीडिया हैंडिल पर लिखा ,ह्यह्य लाइफ अपडेट : पेट के निचले दायें ओर खेल हर्निया की सर्जरी हो गई है । यह बताते हुए खुशी हो रही है कि सफल आपरेशन के बाद अब मैं रिकवरी की राह पर हूं । खेल हर्निया कमर या पेट के निचले हिस्से में नरम ऊतकों की चोट है जिसमें अक्सर मांसपेशियां, कंडराएं या स्नायुबंधन शामिल होते हैं। जर्मनी में सर्जरी के बाद सूर्यकुमार बेंगलुरु में बीसीसीआई के उत्कृष्टता केंद्र पर रिहैबिलिटेशन शुरू करेंगे ।भारत को अगस्त में बांग्लादेश दौरे पर तीन वनडे और तीन टी20 मैच खेलने हैं । सूर्यकुमार ने 2023 विश्व कप फाइनल के बाद से 50 ओवरों के प्रारूप में नहीं खेला है ।यह तीन साल में सूर्यकुमार का तीसरा आपरेशन था । इससे पहले 2023 में उनके टखने का आपरेशन हुआ था और 2024 में खेल हर्निया की भी सर्जरी हुई थी । आईपीएल में शानदार प्रदर्शन करने वाले सूर्यकुमार 2025 सत्र में ह्यप्लेयर आफ द टूर्नामेंटह्व रहे थे । उन्होंने 717 रन बनाये हालांकि मुंबई इंडियंस को प्लेआफ में दूसरे क्वालीफायर में पंजाब किंग्स ने हराया ।

बोटाफोगो के अनुभवी डिफेंडर बास्टोस फीफा क्लब वर्ल्ड कप से बाहर

एजेंसी (हि.स.)
फिलाडेल्फिया

फोटोः हि.स.

अनुभवी डिफेंडर बास्टोस को घुटने की पुरानी चोट दोबारा उभरने के कारण बोटाफोगो की फीफा क्लब वर्ल्ड कप टीम से बाहर कर दिया गया है। ब्राजीलियन क्लब ने बुधवार को यह जानकारी दी। 34 वर्षीय अंगोला अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी बास्टोस ने सोमवार को एटलेटिको मैड्रिड के खिलाफ 1-0 से मिली हार में बतौर अनयूज्ड सब्स्टीट्यूट टीम में जगह बनाई थी। वह फरवरी से चोट के कारण बाहर थे, लेकिन हाल ही में फिट होकर टीम में लौटे थे।

हालांकि मैच के बाद उन्होंने घुटने में फिर से तकलीफ की शिकायत की, जिसके बाद उन्हें इलाज के लिए ब्राजील भेजा जा रहा है। बोटाफोगो ने ग्रुप बी में दूसरा स्थान हासिल किया है और अब वह शनिवार को फिलाडेल्फिया में राउंड ऑफ 16 मुकाबले में अपने ब्राजीलियन प्रतिद्वंदी पल्मेरास से भिड़ेगा। बास्टोस, जिन्हें अंगोला के लिए 58 अंतरराष्ट्रीय मैच खेलने का अनुभव है, ने 2023 में अल-अहली से बोटाफोगो में शामिल होने के बाद क्लब के लिए सभी प्रतियोगिताओं में 60 मैच खेले हैं। वह उस बोटाफोगो टीम का हिस्सा रहे हैं जिसने पिछले साल कोपा लिबटाडोरेस (दक्षिण अमेरिका की शीर्ष क्लब प्रतियोगिता) और ब्राजीलियाई सेरी ए का खिताब जीता था।

अंतरराष्ट्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम दिवस आज

वैश्विक स्तर पर प्रत्येक वर्ष 27 जून को सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 6 अप्रैल, 2017 को आयोजित 74वीं पूर्ण बैठक में प्रतिवर्ष 27 जून को सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग दिवस के रूप में घोषित किया था, इस दिवस के आयोजन का मुख्य उद्देश्य सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने और नवाचार को बढ़ावा देने में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के महत्व को पहचानना है।

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग भारतीय अर्थव्यवस्था में योगदान

ये देश के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में लगभग 29 फीसदी का योगदान करते हैं. एमएसएमई सेक्टर देश में रोजगार का सबसे बड़ा जरिया है। करीब 12 करोड़ लोगों की आजीविका इस क्षेत्र पर निर्भर करती है। भारत के कुल निर्यात में करीब 45% योगदान देते हैं। देश के सकल घरेलू उत्पाद में इस क्षेत्र का योगदान लगभग 8% का है। सेवा क्षेत्र से मिलने वाली ₹ृद्ध में 25% का योगदान देते हैं। बहुत सी इकाइयाँ ग्रामीण क्षेत्रों में भी स्थित है जिसके कारण गावों से शहरों की ओर पलायन रुका है।

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग की नयी परिभाषा

सूक्ष्म उद्योगः सूक्ष्म उद्योग के अंतर्गत रखा अब वह उद्यम आते हैं जिनमें एक करोड़ रुपये का निवेश (मशीनरी वगैरह में) और टर्नओवर 5 करोड़ तक हो. यहां निवेश से मतलब यह है कि कंपनी ने मशीनरी वगैरह में कितना निवेश किया है. यह मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर दोनों क्षेत्र के उद्यमों पर लागू होता है.

लघु उद्योगः उन उद्योगों को लघु उद्योग की श्रेणी में रखते है जिन उद्योगों में निवेश 10 करोड़ और टर्नओवर 50 करोड़ रुपये तक है. यह निवेश और टर्नओवर की सीमा मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस दोनों सेक्टर में लागू होती है.

मध्यम उद्योगः मैनुफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर के ऐसे उद्योग जिनमें 50 करोड़ का निवेश और 250 करोड़ टर्नओवर है वह मध्यम उद्योग में आएँगे।

सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए प्रापण नीति

सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए एक सार्वजनिक प्रापण नीति मार्च, 2012 में अधिसूचित की गई थी। इस नीति में विचार किया गया है कि प्रत्येक केन्द्रीय मंत्रालय/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम तीन वर्ष की अवधि में सूक्ष्म और लघु उद्यमों से कुल वार्षिक क्रय के न्यूनतम 25 प्रतिशत के उद्देश्य की प्राप्ति के साथ सूक्ष्म और लघु क्षेत्र से प्रापण के लिए वार्षिक लक्ष्य निर्धारित करेगा। इसमें से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों के स्वामित्व वाले सूक्ष्म और लघु उद्यमों से प्रापण के लिए 4 प्रतिशत अभिनिर्धारित किया जाएगा। यह नीति सरकारी क्रय में सूक्ष्म और लघु उद्यमों द्वारा भागीदारी बढ़ाकर विपणन पहुंच और प्रतिस्पर्धा में सुधार करके तथा सूक्ष्म और लघु उद्यमों और बड़े उद्यमों के बीच संबंधो को प्रोत्साहित करके सूक्ष्म और लघु उद्यमों के संवर्धन में सहायता करेगी।

सूक्ष्म लघु व मध्यम उद्यम के लिए राष्ट्रीय बोर्ड

सरकार ने सूक्ष्म, लघु मध्यम उद्यमों के लिए पहली बार एक सांविधिक राष्ट्रीय सूक्ष्म, और मध्यम उद्यम बोर्ड की स्थापना की जिससे कि इस क्षेत्र के सशक्त विकास को गति देने के उद्देश्य से नीति बनाने वाले, बैंकरों, व्यापार संघ एवं अन्यों के साथ सूक्ष्म लघु व मध्यम उद्यम(सूलमउ) के भिन्न-भिन्न उपक्षेत्रों के प्रतिनिधियों को साथ लाया जा सके। बोर्ड को हाल ही में 27 मई,2013 को पुनगर्ठित किया गया है। राष्ट्रीय बोर्ड के विचार और निर्देश अत्यधिक प्रतिस्पर्धी और स्वावलंबी बनाने के लिए इस क्षेत्र को मार्गदर्शन एवं उद्यम विकास को दिशा देते हैं।

मुख्य सचिव ने नशा मुक्त भारत की शपथ दिलाई

अंतरराष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस मनाने के लिए सुखना झील से रैली को हरी झंडी दिखाई

संवाददाता
चंडीगढ़

सामूहिक संकल्प और प्रतिबद्धता के एक उल्लेखनीय प्रदर्शन में, चंडीगढ़ प्रशासन के समाज कल्याण, महिला और बाल विकास विभाग ने चंडीगढ़ पुलिस, राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस) और राष्ट्रीय कैडेट कोर (एनसीसी) के साथ मिलकर सुखना झील पर एक नशा विरोधी शपथ और रैली का आयोजन किया, जो प्रशासन द्वारा ह्लअंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस और अवैध तस्करीह्व मनाने के लिए आयोजित किए जा रहे कार्यक्रमों की श्रृंखला का हिस्सा है।

कार्यक्रम में 700 एनसीसी कैडेट, 400 एनएसएस स्वयंसेवक और 100 चंडीगढ़ पुलिस कर्मियों की उत्साही भागीदारी देखी गई, जो नशीली दवाओं के दुरुपयोग के गंभीर मुद्दे से निपटने और चंडीगढ़ को वास्तव में नशा मुक्त बनाने के लिए एक साझा भावना के तहत एक साथ आए।सुबह की शुरूआत सुखना झील पर प्रतिभागियों के एकत्र होने से हुई, क्योंकि वे उद्देश्यपूर्ण मार्च के लिए तैयार थे। अतिरिक्त महानिदेशक (एनसीसी) ने एक सुरक्षित समाज के निर्माण के लिए युवाओं और कानून प्रवर्तन की जिम्मेदारी पर एक प्रेरक संदेश के साथ भीड़ को संबोधित किया। इसके बाद, चंडीगढ़ के पुलिस महानिरीक्षक ने भी बात की और प्रतिभागियों को नशे की लत के खतरे के खिलाफ एकजुट होने के लिए प्रेरित किया।

इस अवसर पर चंडीगढ़ प्रशासन के मुख्य सचिव, आईएएस श्री राजीव वर्मा मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे।नशा मुक्त भविष्य के प्रतीक के रूप में औपचारिक गुब्बारा छोड़ने के बाद, मुख्य सचिव ने एकत्रित प्रतिभागियों और गणमान्य व्यक्तियों को नशा मुक्त भारत की शपथ दिलाई। उन्होंने सभी शामिल एजेंसियों के समन्वित प्रयासों की सराहना की और दीर्घकालिक परिणाम सुनिश्चित करने के लिए सभी क्षेत्रों में निरंतर सहयोग की आवश्यकता पर जोर दिया।

इसके बाद मुख्य सचिव ने सुखना झील से रैली को हरी झंडी दिखाई। प्रतिभागियों ने एक उत्साही मार्च शुरू किया जो सुखना झील से हाईकोर्ट राउंडअबाउट तक और उसी मार्ग से वापस आया। रैली के दौरान, लोगों की ऊर्जा साफ देखी जा सकती थी क्योंकि भीड़ ने बैनर, पोस्टर और तख्तियां लेकर नशा विरोधी संदेश को मजबूती से पेश किया। युवा कैडेटों और स्वयंसेवकों के साथ-साथ वर्दीधारी पुलिस कर्मियों की मौजूदगी ने टीम वर्क और दृढ़ संकल्प का एक शक्तिशाली संदेश दिया।

सुखना झील पर कार्यक्रम का समापन शानदार तरीके से हुआ।रैली ने न केवल युवाओं और समुदाय के बीच गर्व और जिम्मेदारी की भावना को बढ़ावा दिया, बल्कि समाज कल्याण विभाग, महिला एवं बाल विकास, चंडीगढ़ पुलिस, एनसीसी, एनएसएस और सभी हितधारकों के बीच सहयोगात्मक भावना को भी मजबूत किया।

यह पहल चंडीगढ़ प्रशासन की नशीली दवाओं की लत से लड़ने और नागरिकों, खासकर युवाओं को स्वस्थ, नशा मुक्त जीवन जीने के लिए प्रेरित करने की अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाती है। आगे बढ़ते हुए, सभी विभाग शहर को मादक द्रव्यों के सेवन के खिलाफ राष्ट्रीय अभियान में एक शानदार उदाहरण बनाने के लिए उसी ऊर्जा और उत्साह के साथ मिलकर काम करना जारी रखेंगे।

एसडी कॉलेज के एनसीसी कैडेट्स ने जीते बेस्ट इंस्टीट्यूशन और बेस्ट कंपनी अवार्ड

संवाददाता
चंडीगढ़

- दस दिवसीय कंबाइंड एनुअल प्रशिक्षण ट्रेनिंग कैंप संपन्न, कॉलेज के 31 कैडेट्स ने लिया था हिस्सा

सेक्टर-32 स्थित गोस्वामी गणेश दत्त सनातन धर्म कॉलेज के एनसीसी कैडेट्स ने 16 से 25 जून, 2025 तक आयोजित कंबाइंड एनुअल प्रशिक्षण ट्रेनिंग कैंप (सीएटीसी-174) में बेस्ट इंस्टीट्यूशन अवार्ड और बेस्ट कंपनी अवार्ड जीतकर कॉलेज को गौरवान्वित किया है। दस दिवसीय कैंप 2 चंडीगढ़ बटालियन एनसीसी के तत्वावधान में आयोजित किया गया था। जीजीडीएसडी कॉलेज के 31 कैडेट्स ने कंबाइंड एनुअल प्रशिक्षण ट्रेनिंग कैंप (सीएटीसी-174) में अपने असाधारण प्रदर्शन, अनुशासन और उत्साह के माध्यम से अपनी अलग पहचान बनाई, जिसमें 16 संस्थानों के 429 कैडेट्स ने भाग लिया था।

ये प्रतिष्ठित अवार्ड विभिन्न गतिविधियों जैसे खेल प्रतियोगिताएं, पोस्टर मेकिंग, स्लोगन राइटिंग, रैंक अप्वाइंटमेंट्स की संख्या और कैंप ड्यूटीज में सक्रिय भागीदारी में कैडेट की समग्र भागीदारी के आधार पर दिए गए। कॉलेज के प्रिंसिपल डॉ. अजय शर्मा ने पूरी एनसीसी टीम को बधाई देते हुए कहा कि यह गौरवपूर्ण उपलब्धि कॉलेज के अनुशासन, नेतृत्व और समग्र विकास पर ध्यान केंद्रित करने का प्रतिबिंब है।एनसीसी यूनिट ने एक बार फिर संस्थान को गौरवान्वित किया है।

अपने विचार साझा करते हुए मेजर (डॉ.) वीरेंद्र सिंह ने कहा कि यह सफलता पूरे कैंप के दौरान कैडेट्स द्वारा दिखाई गई लगातार कड़ी मेहनत, समर्पण और दृढ़ता का प्रत्यक्ष परिणाम है। यह सफलता एसोसिएट एनसीसी आफिसर लेफ्टिनेंट रितिका सिन्हा के समर्पित मार्गदर्शन में हासिल की गई, जो कैंप में भी उपस्थित थीं।इस अवसर पर उन्होंने कैडेट्स पर गर्व व्यक्त किया तथा कहा कि उनकी प्रतिबद्धता और टीम भावना ने यह सम्मान दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जीजीडीएसडी कॉलेज की एनसीसी यूनिट सेवा, अनुशासन और सामुदायिक विकास के मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध है। कैंप्स, सामाजिक आउटरीच कार्यक्रमों और राष्ट्र निर्माण गतिविधियों में लगातार भागीदारी के साथ, यूनिट कैडेट्स को जिम्मेदार और सक्रिय नागरिक बनने के लिए प्रेरित करती रहती है।

व्यक्तिगत ऋण स्कीम के अंतर्गत 60 केसों का रखा गया लक्ष्य

संवाददाता
पंचकूला

- योजना के तहत महिलाएं 1.50 लाख का कर सकती है आवेदन
- सहायता के लिए फोन नंबर जारी किए

हरियाणा महिला विकास निगम द्वारा चलाई जा रही व्यक्तिगत ऋण स्कीम में वर्ष 2025-26 के लिए 60 केसों (20 अन्य श्रेणी व 40 अनुसूचित जाति) का लक्ष्य रखा गया है।

इस संबंध में जानकारी देते हुए निगम के जिला प्रबन्धक ने बताया कि जिन महिलाओं की वार्षिक आय 1.80 लाख रुपये से अधिक न हो तथा उसके परिवार का कोई सदस्य आयकर दाता न हो। व्यक्तिगत ऋण स्कीम के अन्तर्गत 1.50 लाख रुपये का आवेदन कर सकती है ।

उन्होंने बताया कि इस पर निगम द्वारा 25 प्रतिशत (अधिकतम 10,000 रुपये अन्य श्रेणी व 25,000 रुपये अनुसूचित जाति) अनुदान राशि दी जाती है। 10 प्रतिशत लाभार्थी को स्वयं वहन करना पड़ता है। शेष राशि की व्यवस्था राष्ट्रीज्यकृत/ सहकारी बैंकों से करवाई जाती है। विभिन्न क्रियाकलापों के लिए जैसे की सिलाई, कढ़ाई, करियाना, मनियारी, रेडीमेट गारमैन्टस , कपड़े की दुकान, स्टेशनरी, बुटीक व जनरल स्टोर इत्यादि। यह ऋण योजना शहरी/ ग्रामीण दोनो के लिए उपलब्ध है।

उन्होंने बताया कि इच्छुक उम्मीदवार अधिक जानकारी के लिए निगम के जिला प्रबन्धक, हरियाणा महिला विकास निगम, कमरा न0 52, तीसरी मंजिल, नई बिल्डिग, मिनी सचिवालय सैक्टर-1 पंचकूला, फोन न0 0172-2585271 पर सम्पर्क कर सकते हैं।

ट्राइडेंट ग्रुप ने मादक पदार्थ विरोधी जागरूकता अभियान के साथ स्वस्थ और सुरक्षित कार्यस्थलों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता मजबूत की

संवाददाता
चंडीगढ़

ट्राइडेंट ग्रुप ने 26 जून 2025 को अंतरराष्ट्रीय मादक द्रव्य निषेध एवं तस्करी रोकथाम दिवस के वैश्विक थीम के तहत को मादक पदार्थों के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ पंजाब में बरनाला स्थित संघेड़ा और मध्यप्रदेश में बुधनी कार्यस्थलों में विशेष जागरूकता कार्यशालाओं का आयोजन किया। आयोजन का मुख्य उद्देश्य कर्मचारियों को स्वस्थ जीवनशैली अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना और मादक पदार्थों के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करना था। इन विशेष कार्यशालाओं को वैश्विक थीम ह्लब्रेक द साइकिल और #स्टॉपऑर्गनाइज्डक्राइमह्व के विषयों अनुसार आयोजित किया गया।

संघेड़ा संयंत्र में हुए विशेष सत्र का संचालन बरनाला सिविल अस्पताल के डॉ. गगनदीप सिंह सेखों ने किया। डॉ. सेखों ने बताया कि नशे की लत अक्सर छोटी मात्रा से शुरू होती है, जो धीरे-धीरे गंभीर निर्भरता में बदल जाती है। उन्होंने मादक पदार्थों के सेवन से उत्पन्न पारिवारिक आर्थिक अस्थिरता और दीर्घकालिक मानसिक तनाव के दुष्प्रभावों पर विस्तार से चर्चा की।

कर्मचारियों को नशे की आदत के शुरूआती लक्षण – जैसे व्यवहारिक तथा भावनात्मक बदलाव – के बारे में जागरूक किया गया और नियमित व्यायाम, खेलकूद व सामाजिक सहभागिता के माध्यम से स्वस्थ जीवनशैली अपनाने के लिए प्रेरित किया गया। डॉ. सेखों ने अपने संबोधन में प्रतिभागियों से एक-दूसरे की मदद करने और सतर्कता तथा सहानुभूति से युक्त वातावरण बनाने का आह्वान किया। कर्मचारियों ने इस सत्र में सक्रिय भाग लिया तथा जानकारीपूर्ण एवं आकर्षक संवाद की सराहना की।

यह आयोजन ट्राइडेंट ग्रुप की सुरक्षित, स्वस्थ और सामाजिक रूप से उत्तरदायी कार्य वातावरण बनाने की सतत प्रतिबद्धता को दर्शाता है। साथ ही, यह वैश्विक स्तर पर मादक पदार्थों के दुरुपयोग से मुकाबला करने और संगठित अपराध के चक्र को तोड़ने के व्यापक प्रयासों में भी योगदान देता है। संघेड़ा में आयोजित कार्यशाला में 250 से अधिक कर्मचारियों ने भाग लिया। ट्राइडेंट द्वारा चलाये जा रहे ह्यनशा मुक्तिह्व अभियान के तहत पूरे वर्ष नियमित रूप से ऐसे विशेष सत्र आयोजित किए जाते हैं, जिसमें विश्व तंबाकू दिवस जैसे आयोजन शामिल हैं, साथ ही सभी कर्मचारियों के लिए समय-समय पर चिकित्सा स्वास्थ्य जांच भी की जाती है।

संक्षिप्त-समाचार

नशीली दवाओं के दुरुपयोग के खिलाफ अंतराष्ट्रीय दिवस पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित

चंडीगढ़। आज नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए), यूटी चंडीगढ़ द्वारा शिव मंदिर रामदरबार, इंदिरा कॉलोनी और हल्लोमाजरा में एनजीओ सेहत के सहयोग से जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम का विषय था ड्रग्स को न कहें, जीवन को हां कहें, नशा मुक्त भारत, युद्ध नशे के विरुद्ध, नशा मुक्त भारत और नोप टू डोप। इस कार्यक्रम का उद्देश्य नशीली दवाओं की लत और दुरुपयोग के हानिकारक प्रभावों के बारे में जागरूकता फैलाना था। यह दिन लोगों को नशीली दवाओं की लत से होने वाले विकारों के बारे में शिक्षित करने में उपयोगी है। शहर के गणमान्य व्यक्तियों, एनजीओ पदाधिकारियों और चंडीगढ़ पुलिस के अधिकारियों की मौजूदगी में सभी ने 'ड्रग्स को न कहें' की शपथ ली। लोगों को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, यूटी, चंडीगढ़ की देखरेख में लीगल एड क्लिनिक रामदरबार द्वारा प्रदान की जाने वाली मुफ्त कानूनी सहायता और अन्य सेवाओं के बारे में भी जानकारी दी गई।

भ्रष्टाचार के मामले में मुख्य चिकित्साधिकारी पर केस

चंडीगढ़। एसीबी हिसार द्वारा कल दिनांक 25.6.2025 को भ्रष्टाचार के मामले में आरोपी डॉ. नरेश कुमार तत्कालीन मुख्य चिकित्सा अधिकारी, हिसार (सेवानिवृत) के विरूद्ध चालान धारा 7 पी.सी. एक्ट व 201 भा.द.स. के तहत माननीय न्यायालय हिसार में दिया है। आरोपी डॉ. नरेश कुमार उपरोक्त अभी जिला जेल हिसार में बन्द है। मामला यह था कि शिकायतकर्ता ने एसीबी हिसार को दी गई अपनी शिकायत में आरोप लगाया था कि आरोपी डॉक्टर नरेश कुमार, तत्कालीन मुख्य चिकित्सा अधिकारी, हिसार द्वारा उसके विरूद्ध भ्रुण हत्या का मुकदमा दर्ज न करवाने की एवज में उससे 5,00,000/- रूप्ये नकद (पाँच लाख रूप्ये) बतौर रिश्वत की माँग की जा रही है। शिकायतकर्ता द्वारा आरोपी डॉक्टर नरेश कुमार, तत्कालीन मुख्य चिकित्सा अधिकारी, हिसार द्वारा उससे उसके विरूद्ध मुकदमा दर्ज न करवाने बारे माँगी गई रिश्वत के सम्बन्ध में रिकार्डिंग की गई थी। रिकार्डिंग के आधार पर एसीबी हिसार द्वारा अभियोग संख्या 21 दिनांक 12.08.2023 धारा 7 पीसी एक्ट, थाना भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, हिसार दर्ज किया गया था। एसीबी हिसार ने आरोपी डॉ. नरेश कुमार, तत्कालीन मुख्य चिकित्सा अधिकारी, हिसार के विरूद्ध चालान माननीय न्यायालय हिसार में दिया।

राहुल भारतीय गुप्ता बने पंचकूला जिला आम आदमी पार्टी के चेयरमैन

पंचकूला। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक श्री अरविंद केजरीवाल जी एवं हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष डॉ. सुशील गुप्ता जी के मार्गदर्शन में राहुल भारतीय गुप्ता को पंचकूला जिला आम आदमी पार्टी का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। इस महत्वपूर्ण जिम्मेदारी के लिए मैं पार्टी के सभी वरिष्ठ नेताओं का आभार व्यक्त करता हूँ। जल्द ही, पंचकूला जिला आम आदमी पार्टी टीम द्वारा पंचकूला के निवासियों के कल्याण हेतु कार्ययोजना एवं भविष्य की रणनीति पर विस्तृत प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की जाएगी, जिसमें सभी मीडिया कर्मियों को आमंत्रित किया जाएगा। मैं मीडिया के सहयोग और मार्गदर्शन की अपेक्षा करता हूँ। समस्त जानकारी और अपडेट्स के लिए कृपया राहुल भारतीय गुप्ता के नंबर 9888223323 को अपने कॉन्टैक्ट लिस्ट में सेव करें।

पीजीआई के प्रो. बलजिंदर सिंह को अमेरिका में डायनामिक मॉलीक्यूल अवार्ड 2025

संवाददाता
चंडीगढ़

पीजीआई चंडीगढ़ के न्यूक्लियर मेडिसिन विभाग के प्रोफेसर बलजिंदर सिंह को न्यू ऑरलियन्स, अमेरिका में आयोजित सोसाइटी ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड मॉलिक्यूलर इमेजिंग की वार्षिक बैठक के दौरान प्रतिष्ठित ह्यडायनामिक मॉलीक्यूल अवार्ड 2025ह्व से सम्मानित किया गया है। यह सम्मान उन्हें इंडो-अमेरिकन सोसाइटी ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन द्वारा उनके अनुसंधान पत्र के लिए प्रदान किया गया।

उनका अनुसंधान पत्र था: पोस्ट-इंडक्शन थेरेपी के बाद मल्टीपल मायलोमा रोगियों में मिनिमल रेसिडुअल डिजीज के मूल्यांकन में 68जीए-पेनटीक्साफॉर पेट/सीटी की संभावनाएं-प्रारंभिक निष्कर्ष। इस शोध ने न्यूक्लियर मेडिसिन के क्षेत्र में एक नई दिशा दिखाई है। इसके साथ ही प्रो. बलजिंदर सिंह को विशेष सम्मान भी प्रदान किया गया, जो राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर न्यूक्लियर मेडिसिन को आगे बढ़ाने में उनके योगदान को मान्यता देता है। पीजीआई के निदेशक प्रो. विवेक लाल ने इस अवसर पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि यह अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मिली पहचान पीजीआई के लिए गर्व की बात है।

संयुक्त प्रयास का नतीजा: यह अनुसंधान न्यूक्लियर मेडिसिन, हीमेटोलॉजी और क्लीनिकल ऑन्कोलॉजी विभागों के संयुक्त प्रयास का परिणाम है, जिसे पीएचडी स्कॉलर हरनीत कौर ने अपने शोध कार्य के तहत अंजाम दिया। इस अध्ययन में यह पाया गया कि कई मामलों में बेहतर परिणाम देती है, जैसेः रोग ग्रंथियों की बेहतर पहचान, उच्च ट्रेसर अपटेक और इमेज कंट्रास्ट, प्रभावी रोग प्रतिक्रिया मूल्यांकन और भविष्य के लिए बनी आधारशिलाः यह अध्ययन आने वाले वर्षों में और भी बड़े शोध कार्यों की नींव रखता है।

हरनीत कौर को भी मिल चुकी है अंतरराष्ट्रीय पहचानः शोधकर्ता हरनीत कौर को पहले भी कई प्रतिष्ठित पुरस्कार मिल चुके हैं, जिनमें सोसाइटी ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन इंडिया द्वारा अलावी-तकालकर-कुमार अवार्ड, और ब्राजील में आयोजित इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ मल्टीपल मायलोमा की बैठक में यंग इन्वेस्टिगेटर ट्रैवल अवार्ड शामिल हैं।

उपायुक्त ने पुलिस उपायुक्त को अमरावती में पीसीआर तैनात करने के दिए निर्देश

संवाददाता
पंचकूला

उपायुक्त मोनिका गुप्ता ने समाधान शिविर में अमरावती रेजीडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के प्रधान शमशेर व अन्यों की मांग पर संज्ञान लेते हुए पुलिस उपायुक्त को अमरावती में पीसीआर तैनात करने के निर्देश दिए। उपायुक्त श्रीमती मोनिका गुप्ता आज लघु सचिवालय के सभागार में समाधान शिविर में जिले के लोगों की समस्याएं सुन रही थी। समाधान शिविर में उपायुक्त ने जिलावासियों की 19 समस्याओं को सुना और उनको प्राथमिकता के आधार पर समाधान के लिए संबंधित अधिकारी को निर्देश दिए। उपायुक्त ने गांव सुखदर्शनपुर के ग्रामीणों की सर्विस रोड की वजह से पानी खडा हो गया है और अनेक समस्याएं आ रही हैं, कि शिकायत पर संज्ञान लेते हुए अतिरिक्त उपायुक्त को मौके का मुआयना कर किसकी ये सर्विस लेन बनाई हुई है, विभाग की रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। उपायुक्त ने बताया कि हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी के निदेर्शानुसार जिले की जनता की समस्याओं का जल्द से जल्द समाधान के लिए समाधान शिविर आयोजित किए जा रहे है। उन्होंने बताया कि जिले की जनता की समस्याओं का अधिकारी प्राथमिकता के आधार पर निदान करें ताकि जनता को बिना वजह के अपने कार्यों के लिए जिला प्रशासन के कार्यालयों के चक्कर न लगाने पडे। उन्होंने बताया कि समाधान शिविर की मुख्यमंत्री स्वयं मॉनिटरिंग करते है व स्वयं वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से जुडकर लोगों की समस्याओं पर की गई कार्रवाही की चैकिंग भी करते है।इसलिए कौताही की कोई गुंजाइश नहीं है। उपायुक्त ने बताया कि जिले में हर सोमवार व गुरूवार को दो दिन समाधान शिविर आयोजित किए जाते हैं। उन्होने बताया कि इन समाधान शिविरों में परिवार पहचान पत्र, प्रॉपर्टी आईडी, जमीन की रजिस्ट्री, शहरी निकाय विभाग से एनडीसी लेने, नक्शे की मंजूरी, पेंशन, राशन कार्ड एवं सार्वजनिक वितरण व्यवस्था, अपराध, बिजली-पानी संबंधी आदि शिकायतों का मौके पर ही निपटारा किया जा रहा है।

कार्यशाला

राज्य आयुक्त दिव्यांगजन चंडीगढ़ ने किया आयोजन

दिव्यांगजनों के वित्तीय समावेशन और सशक्तिकरण के लिए कार्यशाला आयोजित

संवाददाता
चंडीगढ़/पंचकूला

राज्य आयुक्त दिव्यांगजन (एससीपीडी), यूटी चंडीगढ़ द्वारा दिव्यांगजनों के वित्तीय समावेशन और सशक्तिकरण के लिए कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला का आयोजन सरकारी बौद्धिक दिव्यांगजन पुनर्वास संस्थान (जीआरआईआईडी), सेक्टर-31सी, चंडीगढ़ में किया गया, जिसमें 100 से अधिक दिव्यांगजन, उनके माता-पिता/अभिभावक, दिव्यांगजनों के लिए काम करने वाले गैर सरकारी संगठनों ने भाग लिया और विभिन्न प्रकार के कौशल विकास, प्रशिक्षण और ऋण के लिए सरकार की विभिन्न योजनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त की। आरंभ में बताया गया कि दिव्यांगजनों के लिए वित्तीय समावेशन इतना महत्वपूर्ण क्यों है।

राज्य आयुक्त, श्रीमती माधवी कटारिया, आईएएस (सेवानिवृत्त) ने कहा कि कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य आर्थिक स्वतंत्रता को बढ़ाना और निर्भरता को कम करना है और इस प्रकार आर्थिक जीवन में दिव्यांगजनों की पूर्ण भागीदारी को सक्षम करके सम्मान और समानता को बढ़ावा देना है। सरकार की विभिन्न योजनाओं, कौशल विकास के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों और ऋण के माध्यम से वित्तीय सहायता के बारे में जागरूकता दिव्यांगजनों और उनके परिवारों को उद्यमिता के लिए बचत, निवेश और ऋण प्राप्त करने में सशक्त बनाएगी।

एक बौद्धिक रूप से दिव्यांग व्यक्ति के माता-पिता ने कहा, रदिव्यांगजनों के सामने कई बाधाएं हैं, जिनमें बैंकों और वित्तीय संस्थानों में सुलभ बुनियादी ढांचे की कमी, सुलभ डिजिटल प्लेटफॉर्म (मोबाइल ऐप, वेबसाइट) की अनुपस्थिति, जटिल प्रक्रियाएं और दस्तावेजीकरण आवश्यकताएं और सबसे बढ़कर उपलब्ध वित्तीय सेवाओं के बारे में अपर्याप्त जागरूकता शामिल है। एक गैर सरकारी संगठन के प्रतिनिधि ने कहा, रदिव्यांग व्यक्तियों (दिव्यांगजनों) के लिए, वित्तीय समावेशन आर्थिक स्वतंत्रता, सम्मान और सामाजिक एकीकरण प्राप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। आज की कार्यशाला एक उत्साहजनक कदम है और ऐसी जानकारी पहले अधिकांश उपस्थित लोगों के पास उपलब्ध नहीं थी। इससे विभिन्न वित्तीय संस्थानों और बैंकों से ऋण प्राप्त करने के बारे में कई मिथकों को दूर करने में भी मदद मिली।ह्र इस बैठक में उद्योग एवं वाणिज्य विभाग, चंडीगढ़ बाल एवं महिला विकास निगम (राष्ट्रीय दिव्यांगजन वित्त विकास निगम के लिए चैनलाइजिंग एजेंसी), विशेष रोजगार कार्यालय, पंजाब नेशनल बैंक-अग्रणी बैंक और नगर निगम के अधिकारियों ने सरकारी योजनाओं, स्वरोजगार और व्यवसाय योजनाओं के लिए प्रशिक्षण और ऋण, पात्रता मानदंड, लाभ और इन योजनाओं और दिव्यांग व्यक्तियों के लिए ऋण प्राप्त करने की प्रक्रियाओं के सभी पहलुओं के बारे में विस्तार से बताया। दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार (आरपीडब्ल्यूडी) अधिनियम 2016 के तहत दिव्यांगों के वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए एक नीति और कानूनी ढांचा मौजूद है, जो वित्तीय सेवाओं तक पहुंच सहित समान अधिकारों को अनिवार्य करता है। अग्रणी बैंक प्रबंधक ने पीएम मुद्रा ऋण की विभिन्न श्रेणियों के बारे में जानकारी दी, उद्योग निदेशालय के अधिकारियों ने पीएम रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) के बारे में जानकारी दी जो सूक्ष्म उद्यमों के माध्यम से रोजगार के अवसरों के सृजन के लिए एक ऋण से जुड़ा सब्सिडी कार्यक्रम है। दिव्यांगजनों की उत्पादकता और उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार के अलावा बाजार लिंकेज आदि के अलावा जमानत मुक्त ऋण तक आसान पहुंच प्रदान करना। चंडीगढ़ बाल एवं महिला विकास निगम के अधिकारियों ने, जो समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत काम करते हैं, बताया कि निगम राष्ट्रीय दिव्यांगजन वित्त विकास निगम के लिए ऋण के लिए एक चैनलाइजिंग एजेंसी है और रियायती ऋण प्राप्त करने के लिए दिशा-निर्देशों की व्याख्या की। उन्होंने सेक्टर 46 में आशा किरण भवन के बारे में भी बताया, जहां दिव्यांगजनों के लिए कई व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं और यह दिव्यांगजनों के लिए मुफ्त सहायक उपकरणों का केंद्र भी है। सभी संसाधन व्यक्तियों ने अपने संपर्क विवरण साझा किए और उपस्थित लोगों को उनके प्रति उत्तरदायी होने का आश्वासन दिया। उन्होंने उनके प्रश्नों के उत्तर दिए और आज की बातचीत से सरकारी विभागों, बैंकों और वित्तीय संस्थानों के बीच सेतु बनाने में मदद मिली।

बृज भूषण शर्मा की 18वी पुस्तक 'हम घर एक मुरारी' जल्द उपलब्ध होगी पुस्तक भंडार में

कालका। प्रिंसिपल बृज भूषण शर्मा (रिटायर्ड) आजकल चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन में महिला बाल विकास निगम में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के पद पर कार्य कर रहे हैं। बृज भूषण शर्मा बुक्स राइटर भी हैं, वह 17 बुक्स लिख चुके हैं, अब उनकी लिखी 18वी पुस्तक 'हम घर एक मुरारी' पंजाबी में, इस सप्ताह पुस्तक मार्केट में आ रही है। यह पुस्तक गुरु ग्रन्थ साहिब की बानी पर आधारित है ओर यह पुस्तक पूरी नई खोज पर आधारित है। भगवान श्रीकृष्ण के अनेक नाम जो गुरु ग्रन्थ साहिब में दर्ज है उनको लेकर लिखी गई है जैसे गोबिंद, बिट्ठल, दामोदर, कृष्ण, गोपाल आदि इसमें और बहुत से पहलू है जो 90 प्रतिशत लोगों को नहीं पता। उदाहरण के तौर पर वाहेगुरु शब्द की उत्पति जो नाम सबसे पहले गुरु अर्जन देव साहिब के मामा जी थे, उनकी पहली बार की 49वीं पौड़ी में से है। वाहेगुरु और वाहगुरु शब्द का अन्तर जानना चाहते हैं तो अंग 1402 /1403/1404 श्री गुरू ग्रन्थ साहिब जी से देखना होगा। यह पुस्तक हिंदी में भी उपलब्ध है। बृज भूषण शर्मा को शुद्ध लेखनी पर पिछले महीने इंडोनेशिया के दूतावास में स्वागत और सम्मान मिल चुका है। शर्मा ने बताया की उनकी पुस्तक 'मेरी इंडोनेशिया यात्रा' 30 जून तक मार्केट में आएगी।